FOCUS NEWS
फोकस न्यूज

facebook.com/fnind
x.com/fnind
focusnewsindia.blogspot.in

www.focusnews.co.in
@FocusnewsIn

...आपका अपना अखबार

राष्ट्रीय संस्करण। नई दिल्ली। गुरुवार 17 अप्रैल 2025। पंचमी, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष। 2081 विक्रम संवत । पेज – 12 । मूल्य 2 रु । वर्ष : 12। अंक : 272

आगामी राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करेगाः जयशंकर

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि अहमदाबाद के निकट बनने वाला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (एनएमएचसी) भारत की समुद्री धरोहर और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करेगा।

भारत को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए कनाडा, नाइजीरिया से मिलेगी चुनौती

राष्ट्रमंडल खेल ने घोषणा की कि 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को कनाडा, नाइजीरिया और दो अन्य देशों से चुनौती का सामना करना पड़ेगा।

इस बार मानसून में देश में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना : आईएमडी

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि आगामी दक्षिण–पश्चिम मानसून मौसम में भारत में सामान्य से अधिक वर्षा होने की उम्मीद है, जिससे फसलों की अच्छी पैदावार की उम्मीद बढ़ गई है।

लाभदायक है फल, सब्जियों के रस का सेवन

उत्तम स्वास्थ्य के लिए अच्छे व संतुलित आहार के साथ–साथ ताजे फलों एवं सब्जियों के रस भी बहुत लाभकारी होते हैं। इनमें खनिज लवणों, विटामिनों, एंजाइम आदि तत्वों की भरपूर मात्रा होती है।

कृतिका कामरा 'पीपली लाइव' की निर्देशक अनुषा रिजवी की अगली फिल्म में काम करेंगी

'भीड़', 'बंबई मेरी जान', और 'ग्यारह ग्यारह' जैसी फिल्मों के लिए मशहूर अभिनेत्री कृतिका कामरा, 'पीपली लाइव' से मशहूर अनुषा रिजवी द्वारा निर्देशत एक आगामी महिला–प्रधान ड्रामा में मुख्य भूमिका में नजर आएंगी।

छत्तीसगढ़ की 1460 ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल से शुरू होगी नकद भुगतान की सुविधा

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की 1460 ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के अवसर पर नकद भुगतान की सुविधा सहित अन्य डिजिटल सेवाएं शुरू करने का फैसला किया है।

शुल्क छूट की तीन माह की अवधि से पहले निर्यात खेप अमेरिका भेजने में जुटे निर्यातक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुल्क के कार्यान्वयन को 90 दिन के लिए टाले जाने के बीच उसका लाभ उठाने के मकसद से निर्यातक तय समय से पहले ही वस्तुओं को अमेरिका भेजने में जुट गये हैं।

समय और स्थिति
कभी भी बदल सकती है इसलिए कभी भी किसी का 'अपमान' न करें और न ही किसी को 'कमज़ोर' समझें आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन 'समय' सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है...

शादी से पहले उसे देखने मेरा पूरा खानदान गया था,

अब शादी के बाद वो अकेली ही मेरे पूरे खानदान को देख लेती है।

पीएम मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति के बीच डिजिटल सहयोग और वैश्विक मुद्दों पर हुई बातचीत

। कृष्णा अग्रवाल ।

नई दिल्ली। फोकस न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने आज बुधवार को फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत–फिनलैंड साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया। खास तौर पर डिजिटल तकनीक, क्वांटम कंप्यूटिंग, 5ळ और 6ळ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (।प्) और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने बातचीत के बाद एक्स पर लिखा, "फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ महत्वपूर्ण बातचीत हुई। फिनलैंड यूरोपीय संघ में भारत का एक अहम साझेदार है। हमने यूक्रेन की स्थिति सहित कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा किए।" पीएमओ के मुताबिक दोनों नेताओं ने डिजिटलाइजेशन, टिकाऊ विकास और मोबिलिटी समीक्षा की। इसके साथ ही यूक्रेन संकट समेत अन्य अंतरराष्ट्रीय विषयों पर भी बातचीत हुई। फिनलैंड के राष्ट्रपति स्टब ने भी एक्स पर लिखा कि उन्होंने पीएम मोदी के साथ अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि इस समय दुनिया में जो सामरिक बदलाव हो रहे हैं, ऐसे में भारत और फिनलैंड की दोस्ती पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने का समर्थन भी जताया। इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन से भी फोन पर बात की थी। दोनों नेताओं ने भारत–डेनमार्क ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने जलवायु परिवर्तन, हरित ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने की बात कही।

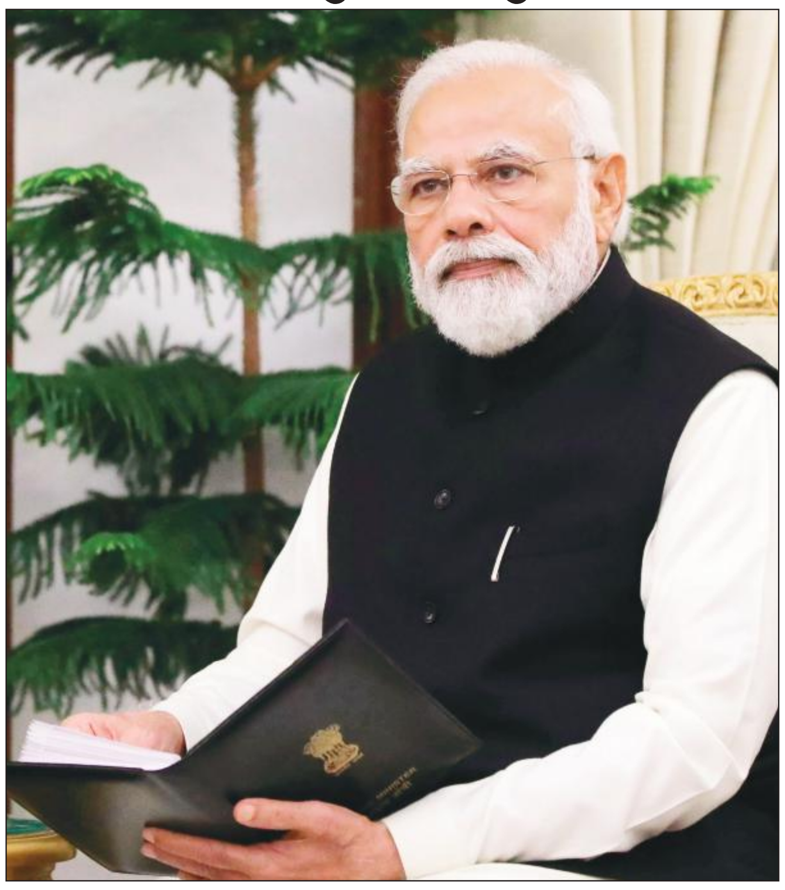

सभी जिलों में होने चाहिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय : योगी

लखनऊ, फोकस न्यूज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पुनर्गठन की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा है कि प्रत्येक जनपद में बोर्ड का एक–एक कार्यालय स्थापित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि 1995 में गठन के बाद से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गतिविधियों, क्षेत्र, कार्य प्रकृति में व्यापक परिवर्तन आ चुका है और बदलते समय की आवश्यकताओं के दृष्टिगत बोर्ड में भी बदलाव किया जाना चाहिए। एक बयान के मुताबिक, बुधवार को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के 75 ज़िलों में 28 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। उन्होंने कहा "इन्हें 18 मंडलों पर पुनर्गठित किया जाए, प्रत्येक जनपद में एक–एक कार्यालय स्थापित किया जाए और जिन मंडलों में औद्योगिक गतिविधियां अधिक हैं, वहां एक से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय बनाये जा सकते हैं।" मुख्यमंत्री ने कहा कि नए दौर की पर्यावरणीय चुनौतियों के समुचित समाधान के लिए बोर्ड में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तरल अपशिष्ट प्रबंधन, हैजाड्र्स वेस्ट, ई–वेस्ट, बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन प्रकोष्ठ का गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निवारण हेतु, अनुसंधान एवं विकास संबंधी अध्ययन हेतु, पर्यावरणीय जन–जागरूकता तथा प्रकाशन हेतु, आईटी तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग हेतु विशेष यूनिट का गठन भी किया जाना चाहिए जिससे बोर्ड की प्रभावशीलता पर सकारात्मक असर पड़ेगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने उद्योगों से संबंधित अनापत्ति आवेदन (सीटीओ/सीटीई) के निपटारे के समय को (शेष पेज दो पर)

विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास से जुड़ी है नई शिक्षा नीतिः राजस्थान के राज्यपाल बागडे

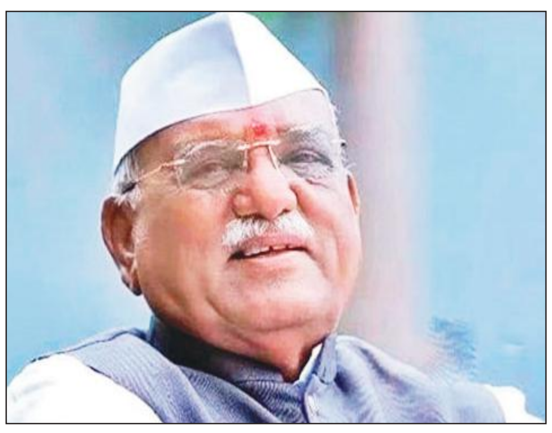

जयपुर, फोकस न्यूज, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास और विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमता बढ़ाने से जुड़ी है। राज्यपाल बागडे, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम उषा अभियान) के अंतर्गत 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में आपदा प्रबंधन एवं भारतीय ज्ञान प्रणाली' विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। आधिकारिक बयान के अनुसार, केंद्र सरकार ने विभिन्न योजनाओं में शिक्षा के लिए जो बजट आवंटित किया है वह विद्यार्थियों के विकास के लिए है। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा (शेष पेज दो पर)

विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन में जिला अध्यक्षों की भूमिका अधिक होगीः राहुल

मोडासा (गुजरात), कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात में पार्टी कार्यकर्ता भले ही "हतोत्साहित" दिख रहे हैं, लेकिन केवल उनकी पार्टी ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भाजपा को हरा सकती है। एक सप्ताह में गुजरात की अपनी दूसरी यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद ने राज्य में संगठन को नया रूप देने के लिए रोडमैप पेश किया और पार्टी के उन नेताओं को हटाने का वादा किया जो या तो निष्क्रिय हैं या "भाजपा के लिए काम करते हैं।" उन्होंने कभी अपना गढ़ रहे गुजरात को अपनी पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य बताया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) तथा 30 (शेष पेज दो पर)

सिल्क्यारा सुरंग में सफलता मिली, धामी ने कहा– इसका नामकरण बाबा बौखनाग के नाम पर होगा

सिल्क्यारा। फोकस न्यूज। 'सिल्क्यारा बेंड–बरकोट रोड' सुरंग में दोनों तरफ से खुदाई पूरी होने के साथ बुधवार को बड़ी सफलता मिली। इसी सुरंग में 2023 में 41 श्रमिक दो सप्ताह से अधिक समय तक फंसे रहे थे। सफलता मिलने पर एक समारोह आयोजित किया गया। इस दिन सुरंग के मुहाने पर बाबा बौखनाग मंदिर का अभिषेक समारोह भी हुआ। दोनों समारोहों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि 2023 में सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों को बाबा बौखनाग के आशीर्वाद के कारण बचाया जा सका और देवता के नाम पर सुरंग का नाम बदलने के लिए कदम उठाए जाएंगे। धामी ने सुरंग स्थल पर दोनों कार्यक्रमों के उपलक्ष्य में आयोजित (शेष पेज दो पर)

जब हम अदालत में बैठते हैं, तो किसी धर्म के मानने वाले नहीं रहते : प्रधान न्यायाधीश

नयी दिल्ली, (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को वक्फ बोर्ड में गैर–मुस्लिमों को शामिल करने के समर्थन में केंद्र द्वारा पेश की गई उस दलील पर कड़ा संज्ञान लिया कि इस तर्क के अनुसार, हिंदू न्यायाधीशों की पीठ को वक्फ से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई नहीं करनी चाहिए। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के उन प्रावधानों पर सवाल कर रही थी जो केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में गैर–मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति की अनुमति देते हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, "क्या आप ये सुझाव दे रहे हैं कि मुस्लिमों सहित अल्पसंख्यकों को भी हिंदू धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन करने वाले बोर्ड में शामिल किया जाना चाहिए? कृपया इसे खुलकर बताएं।" मामले में केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रावधानों का बचाव करते हुए जोर दिया कि गैर–मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना सीमित है और इन निकायों की मुख्य रूप से मुस्लिम संरचना को प्रभावित नहीं करता है। मेहता ने यह भी कहा कि गैर–मुस्लिम (शेष पेज दो पर)

घर पर भी पा सकते हैं सोने जैसा निखार, फॉलो करें गोल्ड फेशियल का स्टेप बाय स्टेप गाइड

अक्सर महिलाएं पार्टी में जाने से पहले अपने चेहरे पर निखार लाने के लिए और स्किन को साफ़ करने के लिए पार्लर जाती हैं। पार्लर में महंगे प्रोडक्ट्स से गोल्ड फेशियल किया जाता है। इससे स्किन को निखार तो मिलता है लेकिन इन प्रोडक्ट्स में मौजूद केमिकल्स त्वचा को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में हम आपके लिए एक उपाय लेकर आए हैं जिससे आप घर पर ही नेचुरल चीजों से मिनटों में गोल्ड फेशियल कर सकती हैं। घर पर मौजूद इन चीज़ों से गोल्ड फेशियल करने से आपके चेहरे पर पार्लर जैसा निखार आएगा। तो, आइए जानें कैसे आप घर पर ही गोल्ड फेशियल (ळवसक थ्ंबपंस ।ज भ्वउम ैजमच ठल ैजमच ळनपकम प्द भ्पदकप) करके आसानी से पार्लर जैसा निखार पा सकती हैं।

घर पर गोल्ड फेशियल करने के तरीकेः

स्टेप 1ः क्लींजिंगः गोल्ड फेशियल करने के लिए त्वचा की क्लींजिंग बहुत जरूरी है। इसके लिए 1/2 चम्मच बेसन में 1 चम्मच कच्चा दूध अच्छी तरह मिलाएं। फिर इसे चेहरे पर लगाकर 1 मिनट तक मसाज करें। इसके बाद चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें।

स्टेप 2ः एक्सफोलिएटिंगः त्वचा को (शेष पेज दो पर)

शरीर में दिखाई दे रहे हैं ये लक्षण, तो आपके लिवर की सेहत पर मंडरा रहा है खतरा

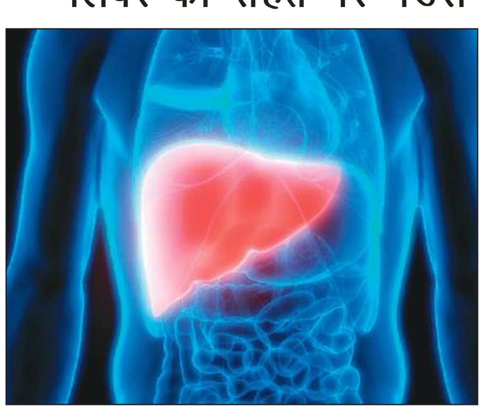

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक जितनी जल्दी लिवर से जुड़ी बीमारी को डिटेक्ट कर लिया जाए, सेहत को उतना ही कम नुकसान पहुंचता है। लेकिन जागरुकता की कमी की वजह से लोग अक्सर लिवर से जुड़ी बीमारियों के दौरान दिखाई देने वाले लक्षणों को नजरअंदाज करने की गलती कर बैठते हैं। आइए लिवर की खराब सेहत की तरफ इशारा करने वाले कुछ कॉमन लक्षणों के बारे में जानते हैं। पेट में भारीपन– पेट के ऊपरी हिस्से में भारीपन महसूस होना, गैस या फिर सूजन की समस्या पैदा होना, फैटी लिवर का संकेत साबित हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लिवर से जुड़ी बीमारियों की वजह से आपकी गट हेल्थ बुरी तरह से (शेष पेज दो पर)

फ्रिज को 24 घंटे में कितनी देर तक ऑन रखना चाहिए? जान लें इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका

जैसे–जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, लोग फ्रिज का इस्तेमाल भी ज्यादा कर रहे हैं। कुछ लोग तो दिन भर फ्रिज ऑन करके रखते हैं जिसकी वजह से बिजली का बिल भी ज्यादा आता है। अगर आपको भी यही लगता है कि चीजों को खराब होने से बचाने के लिए आपको दिन भर फ्रिज को ऑन करके रखना चाहिए, तो आपको अपनी इस गलतफहमी को जल्द से जल्द दूर कर लेना चाहिए।

फ्रिज को कितनी देर तक ऑन रखना चाहिए? : 24 घंटे फ्रिज को ऑन रखना जरूरी नहीं है। आप जानते ही होंगे कि गर्मियों में सर्दियों की तुलना में इस मशीन का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। गर्मियों के मौसम में अक्सर लोग दिन भर (शेष पेज दो पर)

सभी जिलों... (पेज एक का शेष) और कम करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आवश्यक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अनापत्ति एवं सहमति शुल्क में वर्ष 2008 के बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और इस संबंध में बोर्ड द्वारा गहन विचार–विमर्श कर आवश्यक परिवर्तन किया जाना चाहिए। उन्होंने रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाने का आह्वान करते हुए कहा कि आईआईटी आदि प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों के दक्ष युवाओं को अच्छे पैकेज पर नियुक्ति देना चाहिए।

उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, गाजियाबाद और नोएडा में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाएगी: उत्तर प्रदेश सरकार ने कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित, सुलभ और किफायती आवास उपलब्ध कराने के मकसद से लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में आधुनिक छात्रावास के निर्माण की योजना बनाई है। मीडिया को जारी एक बयान के मुताबिक, 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई)' योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कामकाजी महिलाओं के लिए कुल आठ छात्रावास के निर्माण को मंजूरी दी गई है। बयान के अनुसार, ये छात्रावास लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में बनाए जाएंगे और इनमें से प्रत्येक में 500 महिलाओं के रहने की व्यवस्था होगी। बयान में बताया गया है कि छात्रावास निर्माण परियोजना के लिए 381.56 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार ने 251.8296 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी है, जिसे राज्य के वित्त विभाग ने महिला कल्याण विभाग को हस्तांतरित कर दिया है। बयान के मुताबिक, छात्रावास बनाने के लिए निर्माण एजेंसी नामित कर दी गई है। इसमें कहा गया है कि निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की संभावना है।

विद्यार्थियों के... (पेज एक का शेष) से विद्यार्थी का मन विकसित होता है और ऐसा होने से समाज अपने आप ही आपदाओं से जूझने के लिए तैयार होगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प के अंतर्गत मन, आचार– विचार भी विकसित होंगे। राज्यपाल ने विनोबा भावे के कथन की चर्चा करते हुए कहा कि जब देश आजाद हुआ और देश का झंडा बदला गया तभी शिक्षा नीति भी बनानी चाहिए थी लेकिन नीति नहीं बदली इसलिए विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमता नहीं बढ़ी। उन्होंने कहा कि अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी है वह विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास से और विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमता बढ़ाने से जुड़ी है। बागडे ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने 'मानव जोड़ों आदमी जोड़ो' की शिक्षा दी है। उन्होंने नकल मुक्त शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी तभी यह संभव हो सकेगा। बागडे ने रटने की बजाय मन से पढ़ने, पढ़ाने लिए कार्य किए जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वही ज्ञान सार्थक है, जो समय के साथ प्रासंगिक रहे और इसलिए नई शिक्षा नीति इसी आधार पर तैयार की गई है। राज्यपाल ने राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने वाली संस्थाओं, कार्यक्रम अधिकारियों व स्वयंसेवकों को सम्मानित भी किया। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने आपदा प्रबंधन से जुड़ी भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय ग्रंथों में बाढ़, सूखा, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के तरीके बताए गए हैं। अखिल भारतीय सह सेवा प्रमुख राजकुमार मटाले ने आपदा प्रबंधन के अंतर्गत देश में समय–समय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा किए गए कार्यों के आलोक में पाठ्यक्रमों में भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में आपदा से बचाव के लिए मन से विद्यार्थी तैयार किए जाने पर जोर दिया।

सिल्क्यारा सुरंग... (पेज एक का शेष) एक समारोह में उपस्थित लोगों से कहा, ''बाबा बौखनाग की पूजा करने के केवल तीन दिन बाद, दुनिया के सबसे लंबे और सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियान में सभी 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया। यह बाबा बौखनाग के आशीर्वाद से संभव हुआ जो किसी चमत्कार से कम नहीं था।'' उन्होंने लंबे समय तक जारी बचाव अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन के लिए उनको भी धन्यवाद दिया। चार धाम यात्रा के मद्देनजर 4.531 किलोमीटर लंबी यह सुरंग काफी महत्वपूर्ण है। दो लेन की दो दिशा वाली इस सुरंग का निर्माण लगभग 853 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। धामी ने कहा कि सुरंग के पूरा होने पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के बीच की दूरी 26 किलोमीटर कम हो जाएगी और तीर्थयात्रियों के लिए चार धाम यात्रा अधिक सुविधाजनक हो जाएगी। उन्होंने कहा, ''सुरंग के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में केवल पांच मिनट लगेंगे। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।'' राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) के एमडी कृष्ण कुमार ने कहा कि सुरंग को पूरी तरह से चालू होने में लगभग 15–18 महीने और लगेंगे। उन्होंने कहा कि 2023 के भूस्खलन के बाद 17 दिनों की कठिन परीक्षा से गुजरने वाले 41 श्रमिकों में से 15–16 अब भी सुरंग में काम कर रहे हैं।

जब हम... (पेज एक का शेष) भागीदारी पर आपत्ति तार्किक रूप से न्यायिक निष्पक्षता तक विस्तारित हो सकती है और उस तर्क से, पीठ स्वयं मामले की सुनवाई करने से ''अयोग्य'' हो जाएगी। मेहता ने कहा कि यदि वैधानिक बोर्ड में गैर–मुस्लिमों की उपस्थिति पर आपत्ति स्वीकार कर ली जाती है, तो वर्तमान पीठ भी मामले की सुनवाई नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा, ''तब यदि हम उस तर्क के अनुसार चलते हैं, तो माननीय (मौजूदा पीठ के न्यायाधीश) इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते।'' प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ''नहीं, माफ कीजिए मिस्टर मेहता, हम केवल न्याय निर्णय के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जब हम यहां बैठते हैं, तो हम किसी धर्म के मानने वाले नहीं रह जाते हैं। हम पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष हैं। हमारे लिए, एक पक्ष या दूसरा पक्ष समान है।''

शरीर में... (पेज एक का शेष) प्रभावित हो सकती है। त्वचा का पीला पड़ना– क्या आपकी आंखों में या फिर त्वचा में पीलापन नजर आने लगा है? अगर हां, तो आपको तुरंत किसी अच्छे से डॉक्टर से अपना चेकअप करवा लेना चाहिए। त्वचा पर खुजली होना या फिर त्वचा पर दाने निकलना, इस तरह के लक्षण भी लिवर की खराब सेहत की तरफ इशारा कर सकते हैं। उल्टी या फिर घबराहट– अगर आपके लिवर की सेहत में कुछ गड़बड़ है, तो हो सकता है कि आपको बार–बार उल्टी जैसा महसूस हो या फिर आपको घबराहट महसूस होने लगे। इस तरह के लक्षणों को मामूली समझकर नजरअंदाज करने की गलती आपकी सेहत पर काफी ज्यादा भारी पड़ सकती है। थकान और कमजोरी– अगर आपको दिन भर थकान और कमजोरी महसूस होती रहती है, तो हो सकता है कि आपका लिवर ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लिवर की खराब सेहत की वजह से आपके एनर्जी लेवल्स बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं।

विधानसभा चुनाव... (पेज एक का शेष) वर्षों से राज्य की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को हराने का संकल्प व्यक्त किया। गांधी गुजरात में संगठन को नया रूप देने के कांग्रेस के प्रयासों के तहत जिला इकाइयों को मजबूत करने की प्रायोगिक योजना शुरू करने के बाद अरवल्ली जिले के मोडासा शहर में बूथ स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। गुजरात में 2027 के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। एक एआईसीसी पर्यवेक्षक और चार राज्य पर्यवेक्षकों समेत पांच सदस्यों वाली एक समिति गुजरात में पार्टी की 41 जिला इकाइयों (आठ शहरों समेत) में से प्रत्येक के लिए नए प्रमुखों की नियुक्ति की प्रक्रिया की देखरेख करेगी, जिसकी शुरुआत अरवल्ली जिले से होगी। अपने संबोधन में गांधी ने कार्यकर्ताओं से कई वादे किए जैसे कि जिला इकाइयों को अधिक शक्ति एवं धन उपलब्ध कराना, वरिष्ठ नेताओं–कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन का आकलन करना, जमीनी स्तर पर सक्रिय पदाधिकारियों को बढ़ावा देना और उन नेताओं को हटाना जो या तो निष्क्रिय हैं या "भाजपा के लिए काम कर रहे हैं।'' उन्होंने कहा, "यह विचारधाराओं की लड़ाई है। केवल दो ही पार्टियां हैं जिनकी विचारधाराएं हैं – एक भाजपा और दूसरी कांग्रेस। केवल कांग्रेस ही भाजपा और आरएसएस को हरा सकती है। गुजरात पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य है क्योंकि भाजपा की हार का रास्ता गुजरात से होकर जाता है।" गांधी ने उपस्थित लोगों से कहा, "एक तरह से, कांग्रेस गुजरात में अस्तित्व में आई क्योंकि पार्टी के दो महान नेता – महात्मा गांधी और सरदार पटेल – इसी राज्य से थे।" गांधी ने इस बात को स्वीकार किया कि गुजरात में पार्टी कार्यकर्ता 'हताश' हैं, क्योंकि कांग्रेस लगभग तीन दशकों से राज्य में सत्ता से बाहर है। उन्होंने कहा कि भाजपा को हराना मुश्किल नहीं है। उन्होंने कहा, "आपको लगता है कि यहां भाजपा को हराना मुश्किल है। लेकिन मैं यहां आपको यह बताने आया हूं कि भाजपा को हराना आसान है और हम निश्चित रूप से इसमें सफल होंगे। हमें पार्टी की कार्यप्रणाली में बस कुछ बदलाव की जरूरत है। स्थानीय नेताओं ने, नेताओं के बीच विनाशकारी प्रतिस्पर्धा और स्थानीय नेतृत्व से परामर्श किए बिना चुनाव टिकटों का बंटवारा जैसे कुछ मुद्दों को उजागर किया है।" लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष गांधी ने कांग्रेस नेताओं को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया – रेस के घोड़े, बारात के घोड़े और 'लंगड़े घोड़े' ।उन्होंने कहा कि पार्टी गुजरात में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही, क्योंकि रेस के घोड़ों को "शादियों में नचाया जाता है", जबकि जो "नाचने" के लिए होते हैं, उन्हें दौड़ (चुनाव लड़ने) में हिस्सा लेने के लिए कहा जाता है। गांधी ने कहा, "उन्हें अलग करने का समय आ गया है। हम रेस के घोड़ों को (चुनावों में) दौड़ाएंगे और बारात के घोड़ों को (कोई काम नहीं देंगे) नचाएंगे। जिला इकाइयों को अहमदाबाद से नहीं, बल्कि जिलों से चलाया जाना चाहिए। इसीलिए हमने जिला अध्यक्षों को अधिक अधिकार देने की यह कवायद शुरू की है।" पांच सदस्यीय समिति प्रत्येक जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेगी और पांच–छह संभावित उम्मीदवारों के नामों का चयन करेगी, जिन्हें जिला अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उन्होंने वादा किया कि चुने गए जिला अध्यक्ष बिना किसी हस्तक्षेप या "ऊपरी" निर्देश के जिला इकाई को चलाने के लिए निर्णय लेंगे। गांधी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन में जिला अध्यक्षों की भूमिका अधिक होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, "पार्टी संगठन और चुनाव उम्मीदवारों के बीच संबंध होना चाहिए। कई बार चुनाव जीतने के बाद विधायक संगठन की चिंता नहीं करते, जिसने उनकी जीत में अहम भूमिका निभाई थी। अब संगठन ही उम्मीदवारों का चयन करेगा। उम्मीदवारों के बारे में ऊपर से कोई फैसला नहीं होगा।" गांधी ने एक नया दृष्टिकोण अपनाते हुए घोषणा की कि केवल उन पार्टी नेताओं को बढ़ावा दिया जाएगा जो लोगों से जुड़े रहते हैं और उनके मुद्दों को उठाते हैं, जबकि जो लोग निष्क्रिय रहते हैं या केवल चुनावों के दौरान सक्रिय होते हैं उन्हें दरकिनार कर दिया जाएगा। लोकसभा सदस्य ने कहा, "पार्टी जमीनी कार्यकर्ताओं से परामर्श के बाद ही निर्णय लेगी। हम नयी पीढ़ी और लोगों के बीच रहने वालों को बढ़ावा देना चाहते हैं। हमें उन लोगों की पहचान करने और उन्हें किनारे करने की भी जरूरत है जो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं।" कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान एक कार्यकर्ता ने गांधी से कहा कि कांग्रेस के नेता चुनाव से सिर्फ 10 दिन पहले सक्रिय होते हैं और फिर वे "गायब हो जाते हैं।" इस पर गांधी ने माना कि फिलहाल पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं के प्रदर्शन का आकलन नहीं करती। उन्होंने कहा, "लेकिन अब हम इसकी शुरुआत करेंगे। हम पता लगाएंगे कि कोई नेता कितने बूथ जीतने में कामयाब रहा। इससे प्रतिस्पर्धा शुरू होगी। अगर हम गुजरात में सरकार बनाते हैं तो सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिला अध्यक्ष को मंत्री बनाया जाएगा। हम उन लोगों को सत्ता देंगे जो कांग्रेस को मजबूत कर सकते हैं।" गांधी ने संगठन में और अधिक महिलाओं को शामिल करने का वादा किया और कहा कि फिलहाल गुजरात में एक भी महिला जिला अध्यक्ष नहीं है।

बिहार चुनावः दस दलों के बूथ स्तरीय एजेंट को निर्वाचन आयोग ने दिया प्रशिक्षण

नयी दिल्ली, (भाषा) निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बुधवार को बूथ स्तर के एजेंट के रूप में तैनात किए जाने वाले राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 10 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से जुड़े बिहार के लगभग 280 बूथ–स्तरीय एजेंट (बीएलए) भाग ले रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने राज्यों में समान संख्या वाले मतदाता पहचान पत्रों के विषय को उठाया। चुनाव निकाय ने बेहतर मतदाता सूची सुनिश्चित करने के लिए यूआईडीएआई (आधार) और जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिकारियों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। मतदाता सूची के साथ आधार को जोड़ना कानून के तहत स्वैच्छिक आधार पर अधिकृत है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए अपनी तरह के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम में बीएलए को संबोधित किया। बीएलए मतदाता सूची तैयार करने और अद्यतन करने में चुनाव आयोग के बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ काम करते हैं और मतदान के दिन पूरी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। आयोग ने चुनाव प्रक्रियाओं में बीएलए के महत्व को रेखांकित किया और कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम उन्हें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951 और संबंधित नियमों में उल्लिखित अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद करेगा। आयोग ने कहा कि बीएलए को कानूनी ढांचे के अनुसार उनकी नियुक्ति, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया।

फ्रिज को... (पेज एक का शेष) फ्रिज को ऑन करके रखते हैं। अगर ज्यादा गर्मी है, तब भी आपको बीच में थोड़ी देर के लिए फ्रिज को ऑफ कर मशीन को रेस्ट देना चाहिए। एक दिन में दो से तीन बार आप फ्रिज को एक से दो घंटे के लिए बंद कर सकते हैं। **गौर करने वाली बात :** आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब फ्रिज के एडवांस मॉडल्स में बिजली को बचाने वाला फीचर भी अवेलेबल होता है। अगर आपके पास फ्रिज का इसी तरह का कोई एडवांस मॉडल है, तो आप फ्रिज को दिन भर ऑन करके रख सकते हैं। **बाहर जाते समय फ्रिज को बंद कर देना चाहिए :** अगर आप कुछ दिनों तक घूमने के लिए या फिर किसी भी काम के लिए घर से बाहर जाने वाले हैं, तो आपको फ्रिज बंद करके ही जाना चाहिए। इसके अलावा आपको समय–समय पर अपने फ्रिज को साफ भी करते रहना चाहिए। कभी–कभी लोग इस मामले में लापरवाही दिखाते हैं और खराब हो चुकी खाने–पीने की चीजों को फ्रिज से बाहर नहीं निकालते। इस वजह से पूरे फ्रिज में अजीब सी महक भी आने लगती है।

घर पर... (पेज एक का शेष) एक्सफोलिएट करने के लिए एक कटोरी में 1/2 चम्मच बेसन, 1/2 चम्मच चावल का आटा और टमाटर का रस मिलाकर पेस्ट बना लें। अगर आपकी त्वचा बहुत रूखी है, तो आप इसमें 1/2 चम्मच दही भी मिला सकते हैं। फिर इस मिश्रण को आधे कटे हुए टमाटर के स्लाइस में डुबोकर अपने चेहरे पर 2 मिनट तक स्क्रब करें। इसके बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें।

स्टेप 3: फेशियल पैक: त्वचा को एक्सफोलिएट करने के बाद आपको अपने चेहरे पर फेशियल पैक लगाना है। इसके लिए 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच दही और 1/2 चम्मच हल्दी का मिश्रण तैयार करें। फिर इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद अपने चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें।

स्टेप 4: मॉइस्चराइजिंग: फेशियल का आखिरी स्टेप त्वचा को मॉइस्चराइज करना है। इसके लिए आप अपनी त्वचा के हिसाब से कोई भी मॉइस्चराइजर या एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे चेहरे पर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें।

Although every possible care and caution has been taken to avoid errors or omissions, this publication is being sold on the condition and understanding that information given in this publication is merely for reference and must not be taken as having the authority of or binding in any way on the writers, editors, publishers, and printers and sellers who do not owe any responsibility for any damage or loss to any person, a purchaser of this publication or not for the result of any action taken on the basis of this work. All disputes are subject to the exclusive jurisdiction of competent court and forums in Delhi/New Delhi only

Published, Printed, Edited and Owned by Krishna Aggarwal Published from New Delhi, Tel- 011-43560023 E-mail- info@focusnews.co.in, focusnews9@gmail.com
RNI NUMBER - DELBIL/2013/56173, Printed from Vibha Publication Pvt Ltd- D-160 B, Noida Phase - I, Uttar Pradesh - 201301

आगामी राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर भारत की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करेगाः जयशंकर

अहमदाबाद, फोकस न्यूज, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि अहमदाबाद के निकट बनने वाला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (एनएमएचसी) भारत की समुद्री धरोहर और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करेगा। जयशंकर ने गुजरात दौरे के तीसरे दिन प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक लोथल पुरातात्विक स्थल और निर्माणाधीन एनएमएचसी का दौरा किया। यह जगह अहमदाबाद से लगभग 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। एनएमएचसी का दौरा करने के बाद जयशंकर ने कहा कि ऐसा संस्थान समुद्री क्षेत्र में हमारे अनुसंधान, योजना और विमर्शों को आधार प्रदान करेगा। जयशंकर ने 'एक्स' पर कहा, ''लोथल पुरातात्विक स्थल और निर्माणाधीन राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का दौरा किया। यह परिसर हमारी समुद्री धरोहर के साथ–साथ आकांक्षाओं का भी प्रतिनिधित्व करेगा। जैसे–जैसे हम विजन 'महासागर' को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा संस्थान समुद्री क्षेत्र में हमारे शोध, योजना और विमर्शों को आधार प्रदान करेगा।'' बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय भारत की 4,500 साल पुरानी समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के लिए लोथल में एक विश्व स्तरीय एनएमएचसी स्थापित कर रहा है। अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस परियोजना के विकास को मंजूरी दी, जिसे दो चरणों में पूरा किया जाएगा।

दिल्ली सरकार 23 अप्रैल से 1,000 से अधिक स्थानों पर संस्कृत भाषा की निःशुल्क कक्षाएं आयोजित करेगी

नयी दिल्ली, दिल्ली में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार यहां के विद्यालयों, कॉलेजों और मंदिरों सहित 1,000 से अधिक स्थानों पर संस्कृत की 10 दिवसीय निःशुल्क कक्षाएं आयोजित करेगी। संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने बुधवार को यह घोषणा की। योजना के अनुसार, संस्कृत भाषा की कक्षाएं 23 अप्रैल से शुरू होंगी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में शिविर आयोजित करने के लिए एनजीओ 'संस्कृत भारती' के साथ साझेदारी की है। प्रत्येक शिविर में 10 दिनों तक प्रतिदिन दो घंटे के सत्र होंगे, जिसमें भाषा की बुनियादी बातों पर ध्यान दिया जाएगा। मिश्रा ने यहां आयोजित एक समारोह में कहा, ''दिल्ली में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1,008 शिविरों में कक्षाएं आयोजित की जाएंगी और यह बड़े पैमाने पर पहला ऐसा कार्यक्रम होगा।'' मिश्रा राष्ट्रीय राजधानी के उन सात विधायकों में से एक हैं जिन्होंने आठवीं दिल्ली विधानसभा में संस्कृत में शपथ ली थी। कार्यक्रम में मौजूद उत्तर–पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, ''हम अक्सर लोगों को 'अंग्रेजी सीखने' के लिए प्रोत्साहित करने वाले होर्डिंग्स देखते हैं। पहली बार, दिल्ली में लोग 'संस्कृत सीखें' अभियान देखेंगे। इस भाषा ने मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव डाला है।'' दिल्ली विश्वविद्यालय में चार मई को आयोजित होने वाले एक समारोह के साथ इस अभियान का समापन होगा।

सेना प्रमुख ने वरिष्ठ एनआईए अधिकारियों को संबोधित किया

नयी दिल्ली, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यहां एनआईए मुख्यालय में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के महानिदेशक सहित वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित किया। इस दौरान ''उभरते सुरक्षा खतरों'' से निपटने के लिए आवश्यक ''सहयोगात्मक प्रयासों'' पर प्रकाश डाला गया। बल के अतिरिक्त लोक सूचना महानिदेशालय (एडीजीपीआई) ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में बुधवार को यह बात कही और तस्वीरें भी साझा कीं। उसने कहा, ''जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एनआईए मुख्यालय में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के अधिकारियों को संबोधित किया। इस सत्र में श्री सदानंद दाते, महानिदेशक, एनआईए और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।'' सेना ने कहा, ''चर्चा के दौरान उभरते सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए आवश्यक सहयोगात्मक प्रयासों पर प्रकाश डाला गया।''

अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस अपनी पत्नी उषा के साथ 21–24 अप्रैल तक भारत यात्रा पर रहेंगे

नयी दिल्ली, (भाषा) अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा 21 अप्रैल से भारत की चार दिवसीय यात्रा पर आएंगे। इस दौरान वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देने और भारत–अमेरिका संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने बुधवार को इस यात्रा की घोषणा की। वेंस के कार्यालय ने भी अलग से इस यात्रा की घोषणा की। उनकी पत्नी उषा भारतीय–अमेरिकी हैं। वेंस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शुल्क विवाद पर बढ़ती वैश्विक चिंताओं के बीच भारत की यात्रा पर आ रहे हैं और दोनों पक्ष प्रस्तावित व्यापार समझौते को मजबूत करने पर विचार–विमर्श कर सकते हैं जिसका उद्देश्य शुल्क, बाजार पहुंच और आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा, "यह उपराष्ट्रपति वेंस की पहली भारत यात्रा होगी। इस यात्रा के दौरान वह 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे।" इसने कहा, "उपराष्ट्रपति और उनके प्रतिनिधिमंडल के दिल्ली में अन्य कार्यक्रम होंगे तथा 24 अप्रैल को वाशिंगटन डीसी के लिए रवाना होने से पहले उनका जयपुर और आगरा जाने का भी कार्यक्रम है।" अमेरिकी उपराष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी उषा, उनके तीन बच्चे – इवान, विवेक और मीराबेल – तथा अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ सदस्य भी आएंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "यह यात्रा दोनों पक्षों को द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करने और प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान 13 फरवरी को जारी भारत–अमेरिका संयुक्त वक्तव्य के परिणामों के कार्यान्वयन का अवसर प्रदान करेगी।" इसमें कहा गया कि दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान–प्रदान करेंगे।

वेंस के कार्यालय ने कहा कि वह 18 से 24 अप्रैल तक इटली और भारत की यात्रा पर जा रहे हैं और वह ''प्रत्येक देश के नेताओं के साथ साझा आर्थिक और भू–राजनीतिक प्राथमिकताओं पर चर्चा करेंगे।" इसमें कहा गया है, "भारत में उपराष्ट्रपति दिल्ली, जयपुर और आगरा का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ बैठक करेंगे।" अमेरिकी बयान में कहा गया है कि वेंस और उनका परिवार भारत में सांस्कृतिक स्थलों पर कार्यक्रमों में भी भाग लेगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ट्रंप की शुल्क नीति की पृष्ठभूमि में भारत की यात्रा कर रहे हैं। इस नीति से बड़े पैमाने पर व्यापार में व्यवधान और वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंका पैदा हुई। मामले से परिचित लोगों ने बताया कि आगमन के तुरंत बाद वेंस और उनके परिवार के लाल किला जाने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि दोपहर में वेंस राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी भारत यात्रा पर आए वेंस और उनके परिवार से बातचीत करेंगे तथा शाम को उनके लिए औपचारिक रात्रिभोज का आयोजन करेंगे। उषा प्रथम हिंदू अमेरिकी द्वितीय महिला हैं। उन्होंने बताया कि वेंस 22 अप्रैल को जयपुर जाएंगे और प्रमुख पर्यटक स्थलों का दौरा करेंगे तथा कुछ कार्यक्रमों में भाग लेंगे। सूत्रों ने बताया कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति और उनका परिवार अगले दिन ताजमहल देखने के लिए आगरा जाएंगे। इस महीने पारस्परिक शुल्क लागू होने के कुछ दिन बाद, ट्रंप ने चीन को छोड़कर सभी देशों के लिए इस पर 90 दिनों की रोक की घोषणा की। सूत्रों ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वाल्ट्ज ने भी अगले सप्ताह की शुरुआत में भारत आने की योजना बनाई थी, लेकिन उनकी यात्रा स्थगित कर दी गई है। रोम में, वेंस इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ वार्ता करेंगे और 'ईस्टर संडे' से पहले आयोजित समारोहों में भाग लेंगे एवं वेटिकन के राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो परोलिन से मिलेंगे। अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक (डीएनआई) तुलसी गबार्ड की भारत यात्रा के कुछ सप्ताह बाद वेंस की यह यात्रा हो रही है। डीएनआई ने प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल के साथ अलग–अलग बैठकें कीं थीं। अमेरिकी राष्ट्रपति के शुल्क विवाद ने वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंकाओं को हवा दे दी है।

एसआरसीसी ने अरुण जेटली स्मृति वाद–विवाद स्पर्धा के दूसरे संस्करण का आयोजन किया

नयी दिल्ली, (भाषा) दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (एसआरसीसी) ने बुधवार को श्री अरुण जेटली स्मृति वाद–विवाद प्रतियोगिता (एसएजेएमडी) के दूसरे संस्करण की मेजबानी की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिवंगत नेता की भाषण कला, बुद्धिमत्ता और उनकी स्थायी विरासत के प्रति सम्मान प्रकट किया गया। जेटली ने 1973 में एसआरसीसी से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी तथा 1977 में दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की। वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के छात्र कार्यकर्ता थे और 1974 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बने। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की अध्यक्षता की तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

शेखावत ने अपने संबोधन में कहा, "अपनी राजनीतिक पहचान से परे, अरुण जेटली अपने आप में एक संस्था थे। उनकी नैतिकता, राजनीतिक कौशल और एसआरसीसी के प्रति प्रेम बेजोड़ था।" सान्याल ने औद्योगिकीकरण और सतत विकास के बीच संबंधों पर बात की तथा इसे भारत के वर्तमान भू–राजनीतिक और व्यापक आर्थिक परिदृश्य के संदर्भ में प्रस्तुत किया। उन्होंने भारत के आर्थिक विमर्श पर जेटली के बौद्धिक प्रभाव पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का समापन एक औपचारिक पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ। विजेताओं को कुल 2.5 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी गई – जो अंग्रेजी और हिंदी श्रेणियों में बराबर–बराबर बांटी गई। बयान में कहा गया कि यह प्रतिस्पर्धा द्विभाषी प्रारूप में आयोजित की गई और इसमें देश भर के 40 से अधिक संस्थानों ने भाग लिया।

उत्तर प्रदेशः गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभा रहा 'ऑपरेशन कायाकल्प'

लखनऊ, (भाषा) उत्तर प्रदेश में वर्ष 2018 में 'ऑपरेशन कायाकल्प' की शुरुआत के बाद से विद्यालयों में बड़े सुधार देखने को मिले हैं। बुधवार को यहां जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गयी। बयान के मुताबिक, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में शुरू की गई योजना का उद्देश्य प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प करना था। इस योजना के तहत, 19 प्रमुख बुनियादी ढांचों के मापदंडों के आधार पर विद्यालयों का कायापलट किया जा रहा है, जिसमें स्वच्छ पेयजल, कार्यात्मक शौचालय, चारदीवारी, सुरक्षित भवन और उचित बैठने की व्यवस्था जैसी आवश्यक सुविधाएं शामिल हैं। बयान के मुताबिक, इस परिवर्तन के माध्यम से न केवल विद्यालयों को आदर्श शैक्षणिक संस्थानों के रूप में विकसित किया जा रहा है, बल्कि ग्राम सभाओं में सबसे अनुकरणीय भवन भी बन रहे हैं। विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018 से लेकर अब तक प्रदेश में 19 मानकों में से 18 मानकों पर 80 प्रतिशत से अधिक सफलतापूर्वक कार्य पूरे किये जा चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, शौचालय, ब्लैकबोर्ड और परिसर विद्युतीकरण जैसे नौ मानकों पर 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जा चुका है, जबकि आठ मानकों पर 94 प्रतिशत से अधिक की लक्ष्य प्राप्ति की जा चुकी है। बेसिक शिक्षा विभाग की रिपोर्ट में बताया गया कि 2018 की तुलना में स्कूल फर्नीचर आपूर्ति में बड़ी प्रगति हुई है, जो 19 प्रतिशत से बढ़कर 65 प्रतिशत हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, स्वच्छ पेयजल सुविधाएं, जो 2018 में 67 प्रतिशत थीं, अब 100 फीसदी तक पहुंच गयी है। रिपोर्ट में बताया गया कि टाइलयुक्त शौचालय निर्माण, जो 2018 में सिर्फ 21 प्रतिशत था, मार्च 2025 तक 91 प्रतिशत तक पहुंच गया। रिपोर्ट के अनुसार, परिषदीय विद्यालयों के परिसर में गेट युक्त चारदीवारी का निर्माण और रसोई घर का नवीनीकरण जैसे मानकों पर क्रमशः 98 और 94 प्रतिशत लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है।

निगम भाजपा के होर्डिंग क्यों हटा देता है, जबकि एआईएमआईएम के बैनरों की अनदेखी करता हैः राजा सिंह

हैदराबाद, (भाषा) तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक विधायक ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि हैदराबाद नगर निगम भाजपा के लगाए होर्डिंग तुरंत क्यों हटा देता है, जबकि एआईएमआईएम के लगाए बैनरों पर आंखें मूंद लेता है। विधायक राजा सिंह ने हैदराबाद में वक्फ (संशोधन) कानून के खिलाफ आयोजित प्रदर्शन के बारे में एआईएमआईएम नेताओं द्वारा लगाए गए कई होर्डिंग की तस्वीरें 'एक्स' पर साझा कीं और पूछा कि क्या शहर में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लिए कोई अलग नियमावली है। उन्होंने लिखा, ''हैदराबाद नगर निगम आयुक्त, नगर प्रशासन मंत्री और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मेरा प्रश्न है कि हैदराबाद नगर निगम भाजपा के होर्डिंग नियमों का हवाला देते हुए तुरंत क्यों हटा देता है, जबकि एआईएमआईएम के लगाए होर्डिंग पर आंखें मूंद लेता है?'' गोशामहल से विधायक सिंह ने कहा, ''क्या वे समानांतर प्रशासन चला रहे हैं, या उन्हें विशेष विशेषाधिकार प्राप्त हैं?'' ओवैसी ने तीन दिन पहले कहा था कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) 19 अप्रैल को हैदराबाद में वक्फ (संशोधन) कानून के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। इस बीच, विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को पुलिस महानिदेशक जितेंद्र से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 'मुस्लिम चरमपंथी संगठन' वक्फ संशोधन कानून के विरोध की आड़ में हिंदुओं पर हमलों की साजिश रच रहे हैं। विहिप ने एक विज्ञप्ति में कहा, ''तेलंगाना के मदरसों और मस्जिदों में बड़ी संख्या में संदिग्ध लोग हैं। मुस्लिम चरमपंथी संगठनों को कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं दें।'' तेलंगाना में एआईएमआईएम नेताओं पर 'मुस्लिम कट्टरता' भड़काने का आरोप लगाते हुए विहिप ने पूरे राज्य में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। विहिप ने कहा, ''हैदराबाद में आईएसआईएस के झंडे फहराने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें।''

अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण के पहले दिन 4,200 से अधिक तीर्थयात्रियों ने कराया पंजीकरण

नयी दिल्ली, (भाषा) जम्मू–कश्मीर बैंक ने इस साल शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण के पहले दिन 4,200 से अधिक तीर्थयात्रियों का पंजीकरण किया है। बैंक के एक प्रवक्ता ने बुधवार को कहा कि वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जा रहा है और इसमें पात्र तीर्थयात्रियों को यात्रा परमिट जारी करना शामिल है। अमरनाथ यात्रा के लिए 14 अप्रैल से पंजीकरण शुरू हुआ है। प्रवक्ता ने कहा, ''इस वर्ष श्री अमरनाथजी यात्रा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया की मजबूत रूप से शुरुआत करते हुए जम्मू–कश्मीर बैंक ने देशभर में स्थित अपनी 91 नामित शाखाओं के माध्यम से मंगलवार को 4,200 से अधिक तीर्थयात्रियों का पंजीकरण किया है।''

उन्होंने बताया कि इस वर्ष तीर्थयात्रा तीन जुलाई को दो मार्गों– दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबे पहलगाम मार्ग और गंदेरबल जिले में 14 किलोमीटर लंबे छोटे लेकिन खड़ी चढ़ाई वाले बालटाल मार्ग से शुरू होगी। 38 दिवसीय यात्रा नौ अगस्त को रक्षा बंधन के त्योहार के साथ समाप्त होगी। बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष अमिताव चटर्जी ने कहा, ''पहले दिन ही श्रद्धालुओं से अच्छी प्रतिक्रिया देखना उत्साहजनक है। एक ही दिन में 4,200 से अधिक तीर्थयात्रियों का पंजीकरण लोगों का बैंक की सेवा में विश्वास और इस पवित्र तीर्थयात्रा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।''

'विकास' के विमान ने जब उड़ान भरी तब मैं उसका 'पायलट' था : एकनाथ शिंदे

अमरावती, (भाषा) महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को कहा कि जब पिछली 'महायुति' सरकार का 'विकास का विमान' उड़ा, तब वह 'पायलट' और देवेंद्र फडणवीस तथा अजित पवार 'सह–पायलट' थे। शिवसेना अध्यक्ष पूर्वी महाराष्ट्र के अमरावती शहर में एक हवाई अड्डे और एक वाणिज्यिक यात्री उड़ान सेवा के उद्घाटन के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर वर्तमान मुख्यमंत्री फडणवीस और उप मुख्यमंत्री पवार भी मौजूद थे। शिंदे ने दावा किया कि अमरावती हवाई अड्डे का काम तब शुरू हुआ जब 2014–2019 के दौरान फडणवीस मुख्यमंत्री थे, लेकिन 2019 में उद्धव ठाकरे–नीत महा विकास आघाडी (एमवीए) के सत्ता में आने पर यह रुक गया। उन्होंने कहा कि जब 2022 में ''जनता की सरकार'' (उनके नेतृत्व वाली महायुति सरकार) सत्ता में आई तो हवाई अड्डे का निर्माण तेजी से पूरा हुआ। शिंदे ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए दावा किया कि 'महायुति' सरकार आने से पहले कई परियोजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी गई थीं और विकास अवरुद्ध हो गया था।

उप्र : आदित्यनाथ ने कहा कि सभी जिलों में होने चाहिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय

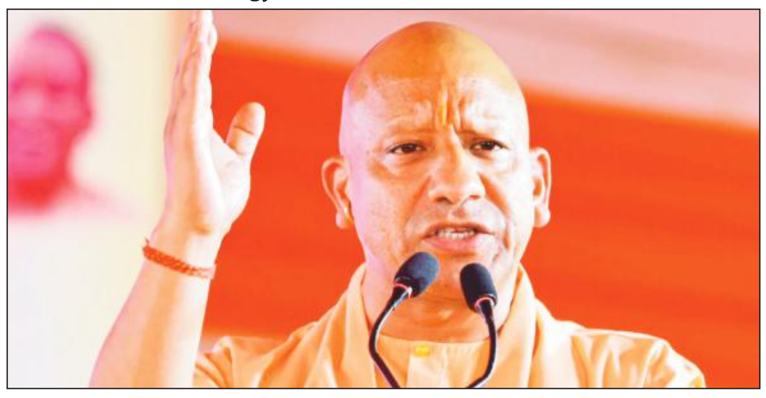

लखनऊ, (भाषा) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पुनर्गठन की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा है कि प्रत्येक जनपद में बोर्ड का एक–एक कार्यालय स्थापित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि 1995 में गठन के बाद से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गतिविधियों, क्षेत्र, कार्य प्रकृति में व्यापक परिवर्तन आ चुका है और बदलते समय की आवश्यकताओं के दृष्टिगत बोर्ड में भी बदलाव किया जाना चाहिए। एक बयान के मुताबिक, बुधवार को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के 75 ज़िलों में 28 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। उन्होंने कहा ''इन्हें 18 मंडलों पर पुनर्गठित किया जाए, प्रत्येक जनपद में एक–एक कार्यालय स्थापित किया जाए और जिन मंडलों में औद्योगिक गतिविधियां अधिक हैं, वहां एक से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय बनाये जा सकते हैं।'' मुख्यमंत्री ने कहा कि नए दौर की पर्यावरणीय चुनौतियों के समुचित समाधान के लिए बोर्ड में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तरल अपशिष्ट प्रबंधन, हैजार्ड्स वेस्ट, ई–वेस्ट, बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन प्रकोष्ठ का गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निवारण हेतु, अनुसंधान एवं विकास संबंधी अध्ययन हेतु, पर्यावरणीय जन–जागरूकता तथा प्रकाशन हेतु, आईटी तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग हेतु विशेष यूनिट का गठन भी किया जाना चाहिए जिससे बोर्ड की प्रभावशीलता पर सकारात्मक असर पड़ेगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने उद्योगों से संबंधित अनापत्ति आवेदन (सीटीओ/सीटीई) के निपटारे के समय को और कम करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आवश्यक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अनापत्ति एवं सहमति शुल्क में वर्ष 2008 के बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और इस संबंध में बोर्ड द्वारा गहन विचार–विमर्श कर आवश्यक परिवर्तन किया जाना चाहिए। उन्होंने रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाने का आह्वान करते हुए कहा कि आईआईटी आदि प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों के दक्ष युवाओं को अच्छे पैकेज पर नियुक्ति देना चाहिए।

दिल्ली सरकार ने यमुना सफाई और नयी जेल सहित अन्य परियोजनाओं के लिए धनराशि को मंजूरी दी

नयी दिल्ली, (भाषा) दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की पहली बैठक में भाजपा सरकार ने यमुना की सफाई और नरेला में उच्च सुरक्षा वाली जेल के निर्माण सहित अन्य कार्यों के लिए 4,000 करोड़ रुपये की धनराशि को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि ईएफसी ने बुनियादी ढांचे से जुड़ी 4,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें 27 जलमल शोधन संयंत्र (एसटीपी) के निर्माण और अत्यधिक प्रदूषित यमुना को साफ करने के प्रयासों को बढ़ाने के वास्ते सीवरलाइन बिछाने के लिए 3,140 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, कपिल मिश्रा और पंकज सिंह के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। सरकार द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि दिल्ली के परिवहन ढांचे को मजबूत करने के लिए डीटीसी डिपो, आईएसबीटी और द्वारका में क्लस्टर बस डिपो पर इलेक्ट्रिक बसों के लिए 'चार्जिंग स्टेशन' स्थापित करने को भी मंजूरी दी गई है। समिति ने द्वारका में क्लस्टर डिपो–1 और 2, आईएसबीटी सेक्टर–22 और डीटीसी डिपो सेक्टर–8 में इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड को 107.02 करोड़ रुपये आवंटित करने का फैसला किया है। बयान में कहा गया कि समिति ने नरेला में उच्च सुरक्षा वाली जेल के निर्माण के लिए 148.58 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

दिल्लीः फीस वृद्धि की शिकायतों पर 600 स्कूलों का निरीक्षण, 10 से अधिक को कारण बताओ नोटिस

नयी दिल्ली, (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी की सरकार ने मनमाने ढंग से फीस बढ़ोतरी की मिली कई शिकायतों के बाद दिल्ली के 600 निजी स्कूलों का बुधवार को निरीक्षण किया और 10 से अधिक विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। एक बयान के अनुसार, दिल्ली शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने मनमाने ढंग से और अत्यधिक फीस बढ़ोतरी की मिली शिकायतों के बाद निजी स्कूलों की जांच के लिए जिला स्तरीय समितियों का गठन किया है। संबंधित उप–विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) की अध्यक्षता वाली इन समितियों में शिक्षा उपनिदेशक, लेखा अधिकारी और सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्य शामिल हैं। उक्त टीम को निजी गैर–सहायता प्राप्त स्कूलों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है, जिनमें शिक्षा निदेशालय को प्राप्त शिकायतों में खासतौर पर उल्लिखित विद्यालय शामिल हैं। बयान में कहा गया, ''दिल्ली के अब तक 600 से अधिक स्कूलों का निरीक्षण किया जा चुका है और यह प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर जारी है।'' शिक्षा निदेशालय ने कहा कि मुनाफाखोरी के लिए मनमाने ढंग से फीस में बढ़ोतरी करने के लिए दोषी पाए गए स्कूलों को दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम और नियम (डीएसईएआर) 1973 की धारा 24(3) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। इसमें कहा गया कि 10 से ज़्यादा ऐसे स्कूलों को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है। शिक्षा निदेशालय ने कहा कि गंभीर मामलों में मान्यता रद्द करने और स्कूल के प्रबंधन को अपने नियंत्रण में लेने जैसी कार्रवाई पर भी विचार किया जा रहा है।

आईएसएल फाइनल के दौरान प्रशंसकों पर फेंके गये पटाखे, क्लब मालिक और समर्थक घायल: बेंगलुरु एफसी

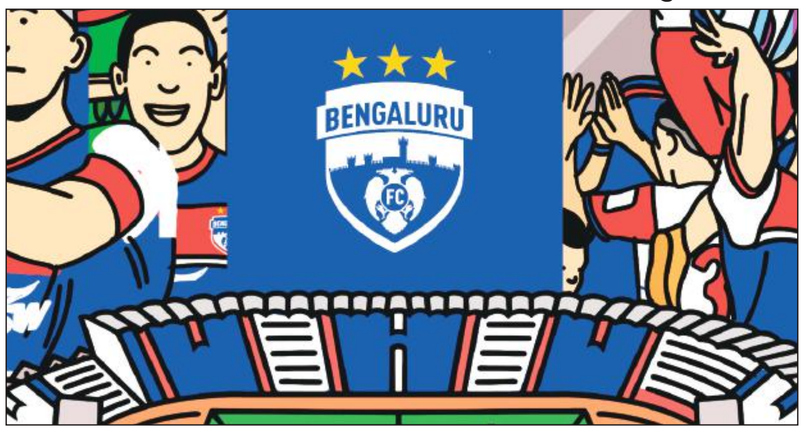

बेंगलुरु, (भाषा) बेंगलुरु फुटबॉल क्लब (बीएफसी) ने मंगलवार को दावा किया कि पिछले सप्ताह मोहन बागान सुपर जायंट के खिलाफ इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) फाइनल के दौरान घरेलू टीम के प्रशंसकों के एक वर्ग द्वारा उनके समर्थकों पर किए गए हमले में उसके मालिक पार्थ जिंदल भी 'चोटिल' हुए हैं। क्लब ने दावा किया कि कोलकाता में खेले गये मैच के दौरान दर्शक दीर्घा में एक जलता हुए पटाखा फेंका गया, जिसमें उसके एक समर्थक की आंख में चोट लग गयी। बेंगलुरु की टीम अतिरिक्त समय तक चले इस खिताबी मुकाबले को 1–2 से हार गयी थी। उसने अपने प्रशंसकों पर हुए हमले की अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के समक्ष औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। बीएफसी ने 'एक्स' पर लिखा, '' बेंगलुरु एफसी अपने समर्थकों पर घरेलू प्रशंसकों के एक वर्ग द्वारा किए गए कायराना हमले की कड़ी निंदा करता है। शनिवार को कोलकाता में मोहन बागान सुपर जायंट के खिलाफ आईएसएल फाइनल के दौरान स्टैंड में एक जलता हुआ पटाखा फेंका गया था।'' उन्होंने कहा, ''इस घटना में बीएफसी के एक समर्थक की आंख में चोट लग गई, जिसका इलाज कराना पड़ा। इसमें क्लब के मालिक पार्थ जिंदल सहित अन्य समर्थकों को जलन और चोटें आईं हैं।'' क्लब ने एआईएफएफ और आईएसएल आयोजकों एफएसडीएल से स्टेडियमों में प्रशंसकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा, ''क्लब ने एआईएफएफ और एफएसडीएल को औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। हम महासंघ और लीग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि इस घटना की जांच हो और स्टेडियमों में प्रशंसक सुरक्षा मानदंडों के लिए एक मिसाल कायम हो।'' उन्होंने कहा, ''इस तरह की हरकतें न केवल जान को खतरे में डालती हैं बल्कि हमारे शानदार खेल की मूल भावना के भी खिलाफ हैं। स्टेडियम प्रशंसकों के लिए हमेशा सुरक्षित स्थान होने चाहिए। इस तरह की हरकतों का फुटबॉल या कहीं भी कोई स्थान नहीं है।'' मोहन बागान सुपर जायंट ने 12 अप्रैल को बेंगलुरु एफसी को रोमांचक फाइनल में 2–1 से हराकर खिताबी डबल पूरा किया। टीम ने इससे पहले तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लीग शील्ड का खिताब सुनिश्चित किया था। मोहन बागान सुपर जायंट इस कारनामे को करने वाली दूसरी टीम है। इससे पहले मुंबई सिटी ने 2020–21 सत्र में लीग शील्ड और आईएसएल चैंपियनशिप को अपने नाम किया था।

भारत को अपनी खेल महत्वाकांक्षा को मजबूत डोपिंग रोधी प्रणाली से जोड़ना चाहिए: खेल सचिव

नयी दिल्ली, (भाषा) खेल सचिव सुजाता चतुर्वेदी ने बुधवार को कहा कि भारत 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए बोली पेश कर रहा है और ऐसे में देश को अपने खेल महत्वाकांक्षा को एक मजबूत डोपिंग रोधी प्रणाली के साथ जोड़ना चाहिए ताकि निष्पक्षता, अखंडता और स्वच्छ खेल के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित हो सके। खेल मंत्रालय की इस शीर्ष अधिकारी ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) द्वारा यहां इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (आईआईसी) में 'एक साथ मिलकर स्वच्छ खेल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण' विषय पर आयोजित सम्मेलन में अपने विचार व्यक्त किये। 'प्ले ट्रू वीक 2025' के हिस्से के रूप में आयोजित इस कार्यक्रम में भारत में स्वच्छ, निष्पक्ष और मूल्य–आधारित खेलों के माहौल को बढ़ावा देने के लिए बड़ी संख्या में हितधारकों को एक साथ लाया गया। विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी (वाडा) के एशिया/ओशिनिया कार्यालय की निदेशक मयूमी याया यामामोटो ने इस वर्ष के वैश्विक 'प्ले ट्रू' अभियान में नाडा के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने 'इट स्टार्ट्स विद मी' अभियान के महत्व पर जोर देते हुए एकजुटता के साथ स्वच्छ खेल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए आवश्यक साझा जिम्मेदारी पर अपने विचार रखे। इसके उद्घाटन सत्र में 10 अलग–अलग क्षेत्रीय भाषाओं में नाडा के 'फेयर प्ले गाइड' का अनावरण किया गया। इसका मकसद पूरे देश में खिलाड़ियों और हितधारकों के लिए स्वच्छ खेल शिक्षा को और अधिक सुलभ बनाना है। इस दौरान राष्ट्रीय खेल महासंघों, चिकित्सा संस्थानों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के विशेषज्ञों ने भारत की डोपिंग रोधी प्रणाली को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक दृष्टि और रणनीतियों को साझा किया।

बीसीसीआई महिला टीम के लिये नये फिजियो और ट्रेनर की तलाश में

नयी दिल्ली, (भाषा) भारतीय महिला क्रिकेट टीम को जल्दी ही एक नया फिजियोथेरेपिस्ट और स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच मिलने वाले हैं जो अगले दो साल तक बेंगलुरू के उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर आफ एक्सीलैंस) में नियुक्त होंगे । बीसीसीआई ने दोनों पदों के लिये आवेदन मंगवाये हैं । नितिन पटेल के जाने के बाद खेल विज्ञान और मेडिसिन विभाग को भी नया प्रमुख मिलने वाला है । फिजियो और ट्रेनर उत्कृष्टता केंद्र में काम करेंगे और घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में टीम के साथ दौरा करेंगे । फिजियो का पद आकांक्षा सत्यवंशी के जाने के बाद और स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच का पद आनंद दाते के जाने से खाली हुआ है । दोनों पदों के लिये पात्रता उन्नत जीवन सहायता (फिजियो के लिये) में , मूलभूत जीवन सहायता (ट्रेनर के लिये) में सर्टिफिकेशन कोर्स और ट्रॉमा मैनेजमेंट में डिग्री शामिल है । सर्टिफिकेशन कोर्स पिछले दो साल में ही पूरा हुआ होना चाहिये । दस साल के अनुभव वाले फिजियो को प्राथमिकता दी जायेगी । बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने एक विज्ञप्ति में कहा ,''खेल विज्ञान और मेडिसिन टीम के लिये ये पद अहम हैं , जो खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने और प्रभावी चोट प्रबंधन और रोकथाम प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए उच्च प्रदर्शन सहायता सेवाएं प्रदान करते हैं।''

भारत को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए कनाडा, नाइजीरिया से मिलेगी चुनौती

लंदन, (भाषा) राष्ट्रमंडल खेल (सीडब्ल्यूएस) ने बुधवार को घोषणा की कि 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को कनाडा, नाइजीरिया और दो अन्य देशों से चुनौती का सामना करना पड़ेगा। राष्ट्रमंडल खेल 2030 में सौ साल पूरे करेगा। सीडब्ल्यूएस की ओर से यह पुष्टि 'पीटीआई' द्वारा खेल मंत्रालय के एक शीर्ष सूत्र के हवाले से दी गई रिपोर्ट के एक महीने से भी कम समय बाद आई है, जिसमें बताया गया था कि 2036 में ओलंपिक मेजबानी का लक्ष्य रखने वाला भारत 2030 में गुजरात में राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के लिए अपनी बोली प्रस्तुत की है। सीडब्ल्यूएस ने कहा कि उसे खेलों के 2030 सत्र की मेजबानी के लिए कनाडा और नाइजीरिया के अलावा दो और देशों से 'रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)' प्राप्त हुई है। कुल मिलाकर सात देशों ने भविष्य के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी में रुचि व्यक्त की है, जिनमें से पांच ने शताब्दी सत्र के आयोजन की रुचि जताई है। सीडब्ल्यूएस ने यह भी कहा कि न्यूजीलैंड उन दो देशों में से एक है जो 2034 सत्र की मेजबानी करना चाहते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों ने यहां जारी एक बयान में कहा, ''अफ्रीका, अमेरिका, एशिया और ओशिनिया वे क्षेत्र हैं जहां से ईओआई प्रस्तुत किए गए हैं। कनाडा, भारत और नाइजीरिया ने पहले ही सार्वजनिक रूप से पुष्टि कर दी है कि उन्होंने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए ईओआई पेश की है। साथ ही दो अन्य देशों ने भी 2030 में मेजबानी के लिए अपनी रुचि जतायी है।'' उन्होंने कहा, ''दो ईओआई 2030 के बाद के खेलों पर केंद्रित है, जिसमें न्यूजीलैंड भी शामिल है । उसने 2034 की मेजबानी में अपनी रुचि का संकेत दिया है।'' राष्ट्रमंडल खेलों की मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैटी सडलेयर ने कहा कि सीडब्ल्यूएस इन खेलों की मेजबानी को लेकर 'अविश्वसनीय रुचि से रोमांचित' है।

उन्होंने कहा, ''हमारे छह क्षेत्रों में से चार से यह सकारात्मक प्रतिक्रिया राष्ट्रमंडल खेलों के महत्व और महत्व को रेखांकित करती है और ओलंपिक खेलों और पैरालंपिक के साथ–साथ विश्व खेल कैलेंडर में प्रमुख बहु–खेल आयोजन के रूप में इसकी स्थिति को दर्शाती है।'' हाल के वर्षों में राष्ट्रमंडल खेलों का भविष्य अनिश्चित लग रहा था क्योंकि बजट की कमी के कारण ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य ने 2026 खेलों के लिए मेजबानी से अपना नाम वापस ले लिया था। ग्लासगो ने इस आयोजन को बचाने के लिए कदम उठाया, लेकिन खेल कार्यक्रम में कई बदलाव करने के बाद। इसके कार्यक्रम से कई अहम खेलों को हटा दिया गया। भारत 2010 में नयी दिल्ली में इन खेलों की मेजबानी कर चुका है और 2030 सत्र के लिए जो ईओआई दिये गये है वे सभी बहु–राष्ट्र की बजाय एकल हैं। खेलों की मेजबानी के लिए ईओआई प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 मार्च थी और भारत का पत्र भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) द्वारा भेजा गया था।

बांग्लादेश के सीमित ओवरों के दौरे पर मीरपुर में चार, चटगांव में दो मैच खेलेगा भारत

ढाका, (भाषा) भारत अगस्त में बांग्लादेश के खिलाफ अपनी सीमित ओवरों की श्रृंखला के दौरान मीरपुर के शेर–ए–बांग्ला स्टेडियम में चार और चटगांव में दो मैच खेलेगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने मंगलवार को यह घोषणा की। बांग्लादेश दौरे पर भारत तीन एकदिवसीय और इतने ही टी20 मैच खेलेगा। यह बांग्लादेश में भारत की पहली टी20 द्विपक्षीय श्रृंखला और 2014 के बाद सिर्फ सीमित ओवरों का पहला दौरा होगा। शुआती दो एकदिवसीय और आखिरी दो टी20 मीरपुर में खेले जाएंगे जबकि तीसरा एकदिवसीय और पहला टी20 चटगांव में होगा। भारत को 13 अगस्त को ढाका पहुंचना है। शुरुआती दो एकदिवसीय 17 और 20 अगस्त को खेले जाएंगे जिसके बाद टीम 23 अगस्त को तीसरा एकदिवसीय खेलने के लिए चटगांव जाएगी। चटगांव में ही पहला टी20 26 अगस्त को होगा। आखिरी दो टी20 29 और 31 अगस्त को मीरपुर में खेले जाएंगे। यह दौरा एशिया कप टी20 की तैयारी में भी मदद करेगा। भारत इस टूर्नामेंट का मेजबान है लेकिन यह अभी स्पष्ट नहीं है कि यह प्रतियोगिता पूरी तरह से श्रीलंका, बांग्लादेश या यूएई में आयोजित की जाएगी या नहीं क्योंकि दोनों देशों के बीच हुए समझौते के अनुसार पाकिस्तान भारत की यात्रा नहीं करेगा। बीसीबी के मुख्य कार्यकारी निजामुद्दीन चौधरी ने 'ईएसपीएनक्रिकइंफो' से कहा, ''यह श्रृंखला हमारे घरेलू कैलेंडर में सबसे रोमांचक प्रतियोगिता में से एक होगी।'' उन्होंने कहा, ''भारत ने सभी प्रारूपों में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मानक स्थापित किए हैं और दोनों देशों के लाखों क्रिकेट प्रेमी इस मुकाबले का आनंद जरूर लेंगे।'' चौधरी ने कहा, ''बांग्लादेश और भारत ने हाल के वर्षों में कुछ बहुत ही प्रतिस्पर्धी मैच खेले हैं और मुझे विश्वास है कि यह एक और कड़ी टक्कर वाली और मनोरंजक श्रृंखला होगी।''

खेल उद्योग पेशेवरों के संघ ने बोर्ड सदस्यों की घोषणा की

नयी दिल्ली, (भाषा) खेल उद्योग पेशेवरों के संघ (एएसआईपी) ने मंगलवार को अपने संस्थापक प्रबंधन बोर्ड की घोषणा की और इसके अध्यक्ष अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के पूर्व महासचिव शाजी प्रभाकरण होंगे । नीरज झा मानद महासचिव होंगे और गोवा फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कैटानो जोस फर्नांडिस बोर्ड के सदस्यों में से होंगे । दिल्ली फुटबॉल संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे शाजी ने इस साल संगठन की स्थापना की है । बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल दो साल का होगा । बोर्ड की पहली बैठक तीन मई को होगी । एक विज्ञप्ति में कहा गया ,'' खेल इकोसिस्टम के विभिन्न क्षेत्रों से 15 प्रतिष्ठित पेशेवरों को लेकर एएसआईपी प्रबंधन बोर्ड का गठन किया गया है । इसका मकसद खेल उद्योग पेशेवरों को संसाधन, मौके प्रदान करना और उसके हितों की रक्षा के लिये खड़े रहना है।''

चैंपियन्स ट्रॉफी के बाद आईसीसी की शुरुआती बैठकों में शामिल नहीं हुए नकवी

कराची, (भाषा) चैंपियन्स ट्रॉफी की मेजबानी के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की वार्षिक तिमाही बैठक में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी शामिल नहीं हुए। पाकिस्तान में निजी काम के कारण नकवी हाल की बैठकों के लिए हरारे नहीं जा सके। नकवी संघीय गृह मंत्री भी हैं जो केंद्र सरकार में एक महत्वपूर्ण पद है। अधिकारी ने कहा, ''मोहसिन नकवी स्वदेश में काम के कारण नहीं जा सके और बोर्ड के सीईओ सुमेर अहमद आईसीसी की बैठकों में शामिल हुए।'' बैठकों के खत्म होने के बाद से पीसीबी ने इस बात पर चुप्पी साधी हुई है कि क्या उसने दुबई में चैंपियन्स ट्रॉफी के फाइनल के पुरस्कार वितरण समारोह के लिए मंच पर पीसीबी के प्रतिनिधि को नहीं रखने के लिए आईसीसी के विरोध को आगे बढ़ाया है। पीसीबी ने 19 मार्च को चैंपियन्स फाइनल के बाद आईसीसी को कई पत्र लिखकर स्पष्टीकरण मांगा था कि टूर्नामेंट का मेजबान पाकिस्तान होने के बावजूद उसका कोई भी प्रतिनिधि मंच पर क्यों नहीं था। यह समझा जाता है कि आईसीसी कभी कोई आधिकारिक कारण नहीं बताएगा क्योंकि ट्रॉफी समारोह के लिए केवल आईसीसी चेयरमैन, बोर्ड सदस्य या राष्ट्राध्यक्ष ही मंच पर हो सकते हैं।चैंपियन्स ट्रॉफी के सफल आयोजन के लिए पीसीबी की सराहना के अलावा पीसीबी के विरोध पर आईसीसी ने कुछ नहीं कहा है। आईसीसी की बैठक के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है क्योंकि ना तो खेल की वैश्विक संचालन संस्था और ना ही पीसीबी ने इस मुद्दे पर कुछ कहा है। दिलचस्प बात यह है कि आईसीसी बैठक में शिरकत करने वाले सुमेर चैंपियन्स ट्रॉफी फाइनल के लिए दुबई में मौजूद पीसीबी के एकमात्र वरिष्ठ अधिकारी भी थे। एक विश्वसनीय सूत्र ने कहा कि आईसीसी की बैठकों में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए दो स्तरीय प्रणाली पर चर्चा हुई थी लेकिन पीसीबी की ओर से चुप्पी के कारण इस पर बोर्ड के रुख के बारे में पता नहीं चला है। आईसीसी और पीसीबी ने चैंपियन्स ट्रॉफी के वित्तीय मामलों को भी अब तक अंतिम रूप नहीं दिया है। हालांकि पीसीबी का दावा है कि उसने चैंपियन्स ट्रॉफी की मेजबानी से तीन अरब रुपये कमाए हैं। यह राशि आईसीसी द्वारा टूर्नामेंट की कमाई से अपने पूर्ण टेस्ट और एसोसिएट सदस्य देशों के बीच वितरित किए जाने वाले हिस्से के अलावा है।

भारत के नितिन गुप्ता और तन्नु ने एशियाई अंडर–18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता

नयी दिल्ली, (भाषा) भारत के नितिन गुप्ता और तन्नु ने बुधवार को सऊदी अरब के दम्मम में छठी एशियाई अंडर–18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की अपनी–अपनी स्पर्धाओं में रजत पदक हासिल किये। गुप्ता ने 5000 मीटर पैदल चाल जबकि तन्नु ने महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में 57.63 सेकंड का समय लेकर दूसरा स्थान हासिल किया। जापान की इमैनी साकी ने 57. 27 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि चीन की डेंग नानक्सी ने 58.01 सेकंड के समय के साथ कांस्य पदक अपने नाम करने में सफल रही। इस स्पर्धा में अन्य भारतीय एडविना जेसन 58.46 सेकंड का समय लेकर पांचवें स्थान पर रहीं। गुप्ता ने 20 मिनट 21.51 सेकेंड का समय लेकर दूसरा स्थान हासिल किया। चीन के झू निंगहाओ ने 20:21.50 सेकेंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। चीनी ताइपे के शेंग किन लो ने 21:37.88 सेकेंड के साथ कांस्य पदक हासिल किया। सत्रह वर्षीय गुप्ता ने पिछले महीने पटना में राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान 19:24.48 सेकेंड का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय निकालकर अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया था। भारतीय एथलीट अन्य स्पर्धाओं जैसे चक्का फेंक, लंबी कूद और लड़के एवं लड़कियों दोनों के 100 मीटर दौड़ में भी प्रतिस्पर्धा करते दिखेंगे।

मुख्य कोच और चयनकर्ता से बहस हुई थी: रोहित ने खुद को टीम से बाहर करने पर कहा

नयी दिल्ली, (भाषा) भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट से बाहर रहने का उनका फैसला सर्वसम्मति से नहीं लिया गया था और इसमें मुख्य कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के साथ उनकी 'बहस' हुई थी। बॉर्डर–गावस्कर ट्रॉफी के दौरान एडिलेड, ब्रिसबेन और मेलबर्न में खेलने वाले कप्तान लगातार पांच पारियों में विफल रहे थे। मेलबर्न में खेले गए श्रृंखला के चौथे टेस्ट मैच में टीम ने शुभमन गिल को बाहर बैठाने का फैसला किया था। रोहित ने 'बियॉन्ड23 क्रिकेट पॉडकास्ट' के दौरान ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क से कहा, '' हम किसी तरह गिल को अंतिम एकादश में रखना चाहते थे, वह बहुत अच्छा खिलाड़ी है। वह पिछले टेस्ट मैच में नहीं खेल पाया था। मैं ऐसा ही हूं... ठीक है, अगर मैं गेंद को अच्छी तरह से नहीं मार पा रहा हूं, तो यह अभी है। चीजें पांच दिन बाद, दस दिन बाद बदल सकती हैं।'' उन्होंने कहा, '' मैंने कोच और चयनकर्ता से बात की और वे इस पर सहमत भी हुए, असहमत भी हुए। इस मुद्दे पर हमारी बहस भी हुई थी।'' टीम को प्राथमिकता देने वाले अपने नेतृत्व दृष्टिकोण के लिए मशहूर भारतीय कप्तान का तर्क सरल था। रोहित ने कहा, ''आप टीम को प्राथमिकता देने की कोशिश करते हैं, आप बस देखते हैं कि टीम की क्या जरूरत है और उसके अनुसार निर्णय लेते हैं। कभी–कभी यह काम करेगा, कभी–कभी नहीं। ऐसा ही होता है। आप जो भी निर्णय लेने की कोशिश करते हैं, उसमें आपको सफलता की गारंटी नहीं होती।'' इस महान बल्लेबाज ने खुद को बाहर करने के निर्णय पर पहुंचने के लिए तार्किक तर्क भी दिया। उन्होंने कहा, ''मैंने (एडिलेड में) अच्छा नहीं खेला था। मैंने सोचा कि मुझे पारी का आगाज करना चाहिये था। मैं जो करता हूं और वहां असफल होना पसंद करूंगा। यही मेरी जगह है, यही मेरी स्थिति है। मैं वहां जाकर बल्लेबाजी करना पसंद करूंगा, चाहे मुझे सफलता मिले या नहीं, यह एक अलग बात है। लेकिन मैं टीम के लिए अपनी स्वाभाविक जगह पर खेलूंगा।'' रोहित ने सोचा कि उन्हें ब्रिस्बेन में एक और मैच में मध्यक्रम में बल्लेबाजी जारी रखनी चाहिए। उन्होंने कहा, '' मध्यक्रम में एक मैच में निराशा के बाद मैंने ज्यादा चिंता किये बिना सोचा कि इसे एक और मैच में जारी रखते हैं। हम ब्रिस्बेन में चीजों को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। वह मुकाबला ड्रॉ पर छूटा। जब हम मेलबर्न पहुंचे तो हमने अपना मन बदल लिया। मैं पारी की शुरुआत करने के लिए वापस चला गया।'' रोहित ने स्वीकार किया कि उन्हें खुद को बाहर करना पड़ा क्योंकि एक ही समय पर टीम के कई खिलाफ फॉर्म में नहीं थे । इसमें स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भी शामिल थे। पर्थ में पहले टेस्ट में अपने शतक को छोड़कर कोहली पूरी श्रृंखला में संघर्ष करते रहे। रोहित ने कहा, '' श्रृंखला के आखिरी टेस्ट मे मुझे खुद के साथ ईमानदार होना पड़ा। मैं गेंद को अच्छी तरह से नहीं मार पा रहा था। मैं खुद को सिर्फ टीम में इसलिए वहां नहीं रखना चाहता था क्योंकि हमने दूसरे खिलाड़ियों को बाहर कर दिया था जो संघर्ष कर रहे थे।'' कप्तान ने कहा कि जब उन्हें राष्ट्रीय टीम के नेतृत्व की जिम्मेदारी मिली, तो उन्हें हर समय टीम के हितों को सबसे पहले रखना पड़ा। उन्होंने कहा, ''जब से मैंने राष्ट्रीय टीम की कप्तानी शुरू की, मुझे लगा कि न केवल मुझे बल्कि बाकी खिलाड़ियों को भी एक जैसा सोचना चाहिए और टीम को पहले रखना चाहिए। टीम के लिए जो जरूरी है वो करना चाहिए और अपने रन और शतक, अपने पांच विकेटों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। आप टीम स्पोर्ट खेल रहे हैं, अगर आप 100 रन बनाते हैं और टीम को सफलता नहीं दिला सकते तो इसका क्या फायदा?'' भारत 20 जून से चार अगस्त तक पांच टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए इंग्लैंड का दौरा करेगा और कप्तान का मानना है कि मेजबान टीम को अच्छा मौका देने के लिए मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह का पूरी तरह से फिट होना काफी अहम होगा। उन्होंने कहा, '' हमें इनमें से कुछ खिलाड़ियों (बुमराह, शमी) को 100 प्रतिशत फिट रहने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि वे आईपीएल से वाकई अच्छे प्रदर्शन करेंगे। मुझे पता है कि यह केवल चार ओवर का मैच है, लेकिन आप आज खेलते हैं, कल यात्रा करते हैं और फिर अगले दिन दोबारा खेलते हैं, यही चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। हमारे प्रमुख खिलाड़ी अगर पूरी तरह से फिट रहे तो इंग्लैंड में हमारे पास अच्छा मौका होगा।''

इंडियन गोल्फ यूनियन ने खिलाड़ियों के लिये शिविर लगाया

ग्रेटर नोएडा, (भाषा) भारत के सबसे प्रतिभावान अमैच्योर गोल्फर 14 से 19 अप्रैल के बीच यहां जेपी ग्रींस पर इंडियन गोल्फ यूनियन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिविर में भाग ले रहे हैं । उपमहाद्वीप से चुने गए ये दस एलीट अमैच्योर गोल्फर एक से चार मई तक जर्मनी में होने वाले जर्मन इंटरनेशनल अमैच्योर टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे हैं । राष्ट्रीय टीम के शिविर में भाग लेने वाले गोल्फरों में आरिन आहूजा, रक्षित दहिया, सुखमन सिंह, कानव चौहान, वरूण मुथप्पा, अयान गुप्ता, जयवीर, दीपक यादव, संदीप यादव और विनम्र आनंद शामिल हैं ।

बल्ले के आकार की जांच से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा: विटोरी

मुंबई, (भाषा) सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के मुख्य कोच डेनियल विटोरी ने बुधवार को कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में अंपायरों द्वारा बल्ले के आकार की जांच करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा । विटोरी ने कहा कि काश उनके खेलने के दिनों में भी ऐसे मापदंड लागू होते। अंपायर बल्ले की जांच एक गेज (बल्ले के आकार को मापने वाला तिकोना पैमाना) से करते रहे हैं, जिससे बल्ले को गुजरना पड़ता है। इसका मकसद बड़े आकार के बल्ले के इस्तेमाल को खत्म करना है। इस सत्र में मैदानी अंपायरों के पास मैच के दौरान बल्ले की जांच करने की छूट है। इसका ताजा उदाहरण कोलकाता नाइट राइडर्स के एनरिक नॉर्किया है। मंगलवार को उनका बल्ला परीक्षण में विफल रहा जिसके बाद उन्हें पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में इसे बदलना पड़ा। विटोरी ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद के मैच की पूर्व संध्या पर यहां वानखेड़े स्टेडियम में संवाददाता सम्मेलन में कहा,'' काश जब मैं खेल रहा था तब भी उन्होंने बल्ले की जांच की होती।'' उन्होंने कहा, '' नहीं, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ेगा। इन खिलाड़ियों को इस तरह की जांच से नियमित तौर पर गुजरना पड़ता है। अंपायर अक्सर ड्रेसिंग रूम में जाते हैं, इसलिए खिलाड़ियों को पता होता है कि उनके बल्ले नियमों के अनुसार हैं। इसमें बस एक सेकंड का समय लगता है।'' उन्होंने कहा, '' यह बड़ा बल्ला रखने की कोशिश करने वालों पर रोक लगायेगा। अपने बल्ले को हालांकि उस गेज से गुजारना बहुत आसान है।'' विटोरी ने कहा कि यह एसआरएच बल्लेबाजों के बीच चर्चा का विषय नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि बल्ले के आकार में कमी आने की कोई संभावना है। इस पूर्व दिग्गज ने कहा, ''वास्तव में नहीं। मुझे लगता है कि जिस तरह से बल्ले बिना वजन बढ़ाए बड़े आकार के हो गये है, वह बल्ले निर्माताओं का कौशल है (जिसका श्रेय उन्हें दिया जाना चाहिए)। यह आज के दौर के बल्लेबाजी की मांग के अनुरूप है।'' उन्होंने कहा, ''यह खेल का हिस्सा है, विकास का हिस्सा है। ऐसा लगता है कि हर कोई छक्के और चौके का लुत्फ उठा रहा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम बल्ले के आकार में कमी करने जा रहे हैं। मुझे इसकी (बल्ले की जांच) ज्यादा परवाह नहीं है।'' विटोरी ने कहा कि उनकी टीम ईशान किशन के अपने पिछले फ्रेंचाइजी और वानखेड़े स्टेडियम के ज्ञान का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा, '' हम मुंबई की मानसिकता और वे कुछ स्थितियों से कैसे निपटते हैं यह समझने के साथ पिच, ओस और उन सभी छोटी–छोटी चीजों को समझने में उनकी समझ का लाभ उठाना चाहेंगे।

दक्षिण पश्चिमी कमान ने पेशेवर उत्कृष्टता का उच्चतम स्तर को छुआः लेफ्टिनेंट जनरल सिंह

जयपुर, (भाषा) सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने मंगलवार को कहा कि इस कमान ने देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के साथ–साथ परिचालन संबंधी तैयारियों और पेशेवर उत्कृष्टता के उच्चतम स्तर को हासिल किया है। सिंह इस कमान के 21वें स्थापना दिवस पर यहां संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कमान की ये उपलब्धियां उचित प्रशिक्षण, नई तकनीक के अंगीकरण और नई प्रौद्योगिकी व सामरिक प्रक्रियाओं को विकसित करने से संभव हुई हैं। उन्होंने कहा, "यही कारण है कि भारतीय सेना की यह सबसे युवा कमान भविष्य के युद्ध के लिए तैयार है और यह तकनीकी रूप दक्ष, घातक और चुस्त बल के रूप में उभरी है।" सिंह ने कहा कि भारतीय सेना के विजन के अनुरूप कई पहल की गई हैं। उन्होंने कहा, "इनमें प्रमुख पांच स्तंभ हैं– संयुक्तता और एकीकरण, बल पुनर्गठन, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी अंगीकरण, सिस्टम प्रोसेस फंक्शन और मानव संसाधन प्रबंधन। इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम अब दिखाई दे रहे हैं।" उन्होंने कहा, "सबसे युवा कमान होने के बावजूद, हमने नई रणनीतिक योजना, बहु–डोमेन संचालन में तालमेल, निगरानी ढांचे में सुधार और नई प्रौद्योगिकी शामिल करके परिचालन तैयारियों में सुधार किया है। कमान ने 'टेक्नालाजी अब्जॉर्प्शन' को विशेष प्राथमिकता दी है।" लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने कहा कि कमान ने आईआईटी कानपुर और रुड़की के साथ मिलकर अनुसंधान और विकास परियोजनाएं शुरू की हैं और कई तकनीकी विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि कमान ने दिग्गजों और वीर नारियों के कल्याण के लिए नई पहल की है। उन्होंने कहा कि जयपुर में एक वृद्धाश्रम बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं और सरकार के साथ भूमि आवंटन की प्रक्रिया चल रही है।

भाजपा की दिल्ली इकाई के नये कार्यालय के पास पीडब्ल्यूडी करेगा सड़क सौंदर्यीकरण और सुधार कार्य

नयी दिल्ली, (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी में दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) मार्ग पर स्थित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली इकाई के नये कार्यालय के पास लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) सड़क सुधार और सौंदर्यीकरण का काम करेगा। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना को पूरा करने की समय–सीमा एक माह है और इसकी लागत 2.23 करोड़ रुपये है, जिसमें सिविल और बिजली संबंधी कार्य शामिल हैं। भाजपा की दिल्ली इकाई का कार्यालय लुटियंस दिल्ली में पंडित पंत मार्ग पर एक बंगले में स्थित है, जिसे अब डीडीयू मार्ग स्थित पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय के पास ही स्थानांतरित किया जा रहा है। भाजपा की दिल्ली इकाई का नया भव्य कार्यालय 2023 से निर्माणाधीन है और जल्द ही पूरा होने की संभावना है। बहुमंजिला कार्यालय में मौजूदा कार्यालय से ज़्यादा जगह होगी, ताकि ज्यादा लोग और पार्टी पदाधिकारी बैठ सकें। इसमें बेसमेंट पार्किंग, कॉन्फ्रेंस कक्ष और बैठक कक्ष जैसी आधुनिक सुविधाएं भी होंगी। भाजपा के एक पदाधिकारी ने बताया, "फिलहाल प्रदेश कार्यालय हमारी जरूरतों के हिसाब से बहुत छोटा है और वाहनों की पार्किंग के लिए बहुत कम जगह है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नए कार्यालय का निर्माण कराया जा रहा है, काम पूरा होने में एक से दो महीने का समय लगने की संभावना है।" योजना के अनुसार क्षेत्र को साफ किया जाएगा तथा सड़क की मरम्मत की जाएगी। पीडब्ल्यूडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "भाजपा की दिल्ली इकाई के नये कार्यालय की ओर जाने वाले मार्ग की हालत खराब है।" सड़क पर समुचित प्रकाश व्यवस्था की जाएगी। नई एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी तथा सड़क पर मार्किंग और पेंटिंग का काम किया जाएगा।

गठबंधन सरकार में अलग–अलग पृष्ठभूमि के लोगों में असहमति होना स्वाभाविकः चंद्रकांत पाटिल

मुंबई, (भाषा) महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति में दरार की अटकलों के बीच राज्य के मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि किसी गठबंधन सरकार में विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के बीच मतभेद होना स्वाभाविक है। महाराष्ट्र के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री पाटिल उन खबरों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिनमें कहा गया था कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से उपमुख्यमंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख अजित पवार के बारे में शिकायत की है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "एक ही छत के नीचे रहने वाले परिवार के सदस्यों के बीच भी मतभेद होते हैं। विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग गठबंधन सरकार में एकसाथ आए हैं और यदि ऐसी स्थिति में कोई शोर नहीं होता है, तो किसी को यह जांचना पड़ सकता है कि वे जीवित हैं या नहीं।" पाटिल ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री शिंदे और पवार अलग–अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। उन्होंने कहा, "जब ऐसे लोग एकसाथ आते हैं, तो स्वाभाविक रूप से कुछ शोर होगा। यह शोर दिखाता है कि वे जीवित हैं। असंतोष जताना आवश्यक है।" शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना कथित तौर पर इस बात से नाराज है कि पार्टी के पास जो मंत्रालय हैं, उनसे संबंधित कुछ फाइल पवार के पास अटकी हुई हैं। अजित पवार राज्य के वित्त मंत्री भी हैं। ऐसी अटकलें हैं कि फडणवीस द्वारा राज्य की पूर्ववर्ती शिंदे सरकार द्वारा लिए गए कुछ फैसलों को पलटे जाने से भी शिवसेना नाराज है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में भाजपा, शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल हैं। महायुति गठबंधन दिसंबर में विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद सत्ता में आया था। हालांकि, जून 2022 से मुख्यमंत्री रहे शिंदे को देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली नयी सरकार में उपमुख्यमंत्री पद से संतोष करना पड़ा।

दिल्ली में अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया

नयी दिल्ली, (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को धूप खिली रहने और आसमान साफ रहने के कारण अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। अपने सप्ताह भर के मौसम पूर्वानुमान में भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने किसी भी प्रकार की लू की स्थिति की भविष्यवाणी नहीं की है, लेकिन आगामी दिनों में तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया है। दिल्ली का न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री अधिक 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि दिन में आर्द्रता का स्तर 52 से 34 प्रतिशत के बीच रहा। मौसम विभाग ने बुधवार को भी तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है तथा अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। इस बीच, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 180 रहा, जो 'मध्यम' श्रेणी में आता है। शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 के बीच को 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच को 'मध्यम', 201 से 300 के बीच को 'खराब', 301 से 400 के बीच को 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच को 'गंभीर' माना जाता है।

इस बार मानसून में देश में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना : आईएमडी

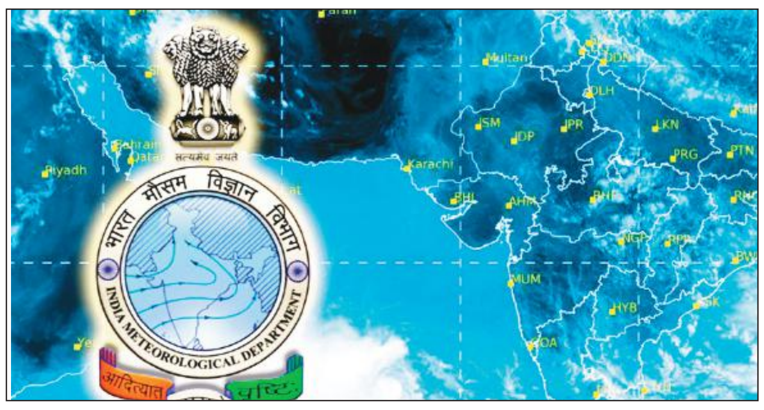

नयी दिल्ली, (भाषा) भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मंगलवार को कहा कि आगामी दक्षिण–पश्चिम मानसून मौसम में भारत में सामान्य से अधिक वर्षा होने की उम्मीद है, जिससे फसलों की अच्छी पैदावार की उम्मीद बढ़ गई है। आईएमडी ने मानसून के दीर्घकालिक पूर्वानुमान के अनुसार, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर क्षेत्र के बड़े हिस्से में सामान्य से कम वर्षा होने का अनुमान है, जबकि मराठवाड़ा और उससे सटे तेलंगाना के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में सचिव एम रविचंद्रन ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, "भारत में चार महीने (जून से सितंबर) के मानसून के मौसम में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है तथा कुल वर्षा दीर्घावधि औसत 87 सेमी का 105 प्रतिशत (पांच प्रतिशत की मॉडल त्रुटि के साथ) रहने का अनुमान है।" दक्षिण–पश्चिम मानसून एक जून से 30 सितंबर तक सक्रिय रहता है। उन्होंने कहा कि भारत में मानसून की वर्षा को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण कारकों में से दो का प्रभाव तटस्थ होगा, जबकि एक का इस वर्ष बारिश पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा, "मानसून के दौरान सामान्य वर्षा की 30 प्रतिशत संभावना, सामान्य से अधिक वर्षा की 33 प्रतिशत संभावना तथा अत्यधिक वर्षा की 26 प्रतिशत संभावना है।" आईएमडी के अनुसार, 50 वर्ष के औसत 87 सेंटीमीटर के 96 प्रतिशत से 104 प्रतिशत के बीच वर्षा को 'सामान्य' माना जाता है। दीर्घावधि औसत के 90 प्रतिशत से कम वर्षा को 'कम' माना जाता है, 90 प्रतिशत से 95 प्रतिशत के बीच को 'सामान्य से कम', 105 प्रतिशत से 110 प्रतिशत के बीच को 'सामान्य से अधिक' तथा 110 प्रतिशत से ज्यादा को 'अधिक' वर्षा माना जाता है। मानसून के दौरान जम्मू–कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा होने का अनुमान है। मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बड़े हिस्सों में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। ये देश के मुख्य मानसून क्षेत्र हैं जहां कृषि मुख्यतः वर्षा आधारित होती है। देश के कई हिस्से पहले से ही भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं और अप्रैल से जून की अवधि में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने का अनुमान है। इससे बिजली ग्रिड पर दबाव पड़ सकता है और पानी की कमी हो सकती है। मानसून भारत के कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, जो लगभग 42.3 प्रतिशत आबादी की आजीविका का आधार है और देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 18.2 प्रतिशत का योगदान देता है। कुल खेती योग्य क्षेत्र का 52 फीसदी हिस्सा वर्षा आधारित प्रणाली पर निर्भर है। यह देशभर में बिजली उत्पादन के अलावा पीने के पानी के लिए महत्वपूर्ण जलाशयों को फिर से भरने के लिए भी अहम है। इसलिए, मानसून के मौसम में सामान्य वर्षा का पूर्वानुमान देश के लिए एक बड़ी राहत है। हालांकि, सामान्य वर्षा का यह मतलब नहीं है कि पूरे देश में हर जगह एक समान बारिश होगी। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा आधारित प्रणाली की परिवर्तनशीलता और अधिक बढ़ जाती है। जलवायु वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश के दिनों की संख्या घट रही है, जबकि भारी बारिश की घटनाएं (थोड़े समय में अधिक बारिश) बढ़ रही हैं। इससे कुछ क्षेत्रों में बाढ़ और कुछ क्षेत्रों में सूखे की स्थिति पैदा होती है। मानसून की वर्षा का पूर्वानुमान लगाने के लिए तीन बड़े पैमाने की जलवायु परिघटनाओं पर विचार किया जाता है। पहली है ईएनएसओ। यह एक जलवायु पैटर्न है जो उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान में उतार–चढ़ाव से संबंधित है, जो वैश्विक मौसम पैटर्न को प्रभावित करता है। दूसरा कारक है हिंद महासागर द्विध्रुव, जो भूमध्यरेखीय हिंद महासागर के पश्चिमी और पूर्वी किनारों के भिन्न–भिन्न तापमान के कारण उत्पन्न होता है। तीसरा कारक है उत्तरी हिमालय और यूरेशियाई भूभाग पर बर्फ का आवरण, जो भूभाग के भिन्न–भिन्न तापमान के कारण भारतीय मानसून को भी प्रभावित करता है। महापात्र ने कहा कि मौसम के दौरान ईएनएसओ–तटस्थ स्थितियां और तटस्थ हिंद महासागर द्विध्रुव स्थितियां होने का अनुमान है। साथ ही, उत्तरी गोलार्ध और यूरेशिया में बर्फ का आवरण कम है।

2022 के मार्च–अप्रैल में भारत में लू का कारण अधिक ऊंचाई की हवा और मिट्टी का शुष्क होना थाः आईआईटीबी

मुंबई, (भाषा) मुंबई स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटीबी) की एक अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2022 के मार्च–अप्रैल में भारत में लू (हीट वेव) चलने का कारण अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की हवा का पैटर्न और मिट्टी के शुष्क होने की स्थिति थी। आईआईटीबी और जर्मनी के जोहान्स गुटेनबर्ग–यूनिवर्सिटी मेंज के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक नए अध्ययन में पाया गया कि 2022 के मार्च और अप्रैल में असामान्य रूप से तीव्र लू चलने की घटनाएं (जिनमें तापमान वर्ष के उस समय के सामान्य सीमा से कहीं अधिक था) विभिन्न वायुमंडलीय प्रक्रियाओं द्वारा संचालित थीं, जिसने लू के प्रभावों को बढ़ा दिया। अध्ययन रिपोर्ट के मुख्य लेखक रोशन झा ने कहा, "हमारा विश्लेषण दर्शाता है कि मार्च की गर्मी मुख्य रूप से अल्पकालिक वायुमंडलीय रॉस्बी तरंगों के आयाम में अचानक वृद्धि से जुड़ी थी, जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की हवाओं में ठीक उसी तरह बड़े पैमाने पर घुमाव लाती हैं जैसे घुमावदार नदी का घुमाव होता है।" उन्होंने कहा कि ध्रुवों के पास उच्च ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाओं ने भूमध्यरेखा के करीब पश्चिमी हवाओं को ऊर्जा हस्तांतरित की, क्योंकि वे लू के दौरान एक–दूसरे के करीब आ गई जिससे लू और प्रचंड हो गई। हालांकि, अप्रैल में लू चलने का मुख्य कारण अत्यधिक शुष्क मिट्टी की स्थिति तथा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के उत्तर–पश्चिमी भू–भागों से भारत में गर्मी का प्रवाह था। आईआईटीबी में एसोसिएट प्रोफेसर और अध्ययन की सह–लेखिका अर्पिता मोंडल ने बताया कि जब मिट्टी में नमी होती है, तो साफ आसमान की स्थिति में सूर्य की कुछ ऊर्जा हवा को गर्म करने के बजाय उस नमी को वाष्पित करने में चली जाती है। लेकिन जब मिट्टी पहले से ही सूखी होती है तो सारी ऊर्जा सीधे हवा को गर्म करने में इस्तेमाल होती है।

देश में प्रति दस लाख जनसंख्या पर केवल 15 न्यायाधीशः 2025 'इंडिया जस्टिस' रिपोर्ट

नयी दिल्ली, (भाषा) देश में प्रति दस लाख आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश हैं, जो विधि आयोग की प्रति दस लाख की आबादी पर 50 न्यायाधीशों की सिफारिश से बहुत दूर है। मंगलवार को जारी 'इंडिया जस्टिस सिस्टम रिपोर्ट' 2025 में यह जानकारी सामने आई है। 'इंडिया जस्टिस रिपोर्ट' के मुताबिक, "1.4 अरब लोगों के लिए भारत में 21,285 न्यायाधीश हैं या प्रति दस लाख की आबादी पर लगभग 15 न्यायाधीश हैं। यह 1987 के विधि आयोग की प्रति दस लाख की आबादी पर 50 न्यायाधीशों की सिफारिश से काफी कम है।" इस रिपोर्ट में देश में न्याय प्रदान करने के मामले में राज्यों की स्थिति की जानकारी दी गयी है। रिपोर्ट के मुताबिक, उच्च न्यायालयों में रिक्तियां कुल स्वीकृत पदों का 33 प्रतिशत थीं। रिपोर्ट में 2025 में 21 प्रतिशत रिक्तियों का दावा किया गया, जो मौजूदा न्यायाधीशों के लिए अधिक कार्यभार को दर्शाता है। रिपोर्ट में बताया गया, "राष्ट्रीय स्तर पर जिला न्यायालयों में प्रति न्यायाधीश औसत कार्यभार 2,200 मामले है। इलाहाबाद और मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयों में प्रति न्यायाधीश मुकदमों का बोझ 15,000 है।" रिपोर्ट के मुताबिक, जिला न्यायपालिका में महिला न्यायाधीशों की कुल हिस्सेदारी 2017 में 30 प्रतिशत से बढ़कर 38.3 प्रतिशत हो गई है और 2025 में उच्च न्यायालयों में यह 11.4 प्रतिशत से बढ़कर 14 प्रतिशत हो गई है। रिपोर्ट में बताया गया, "उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय (छह प्रतिशत) की तुलना में जिला न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की हिस्सेदारी अधिक है। वर्तमान में, 25 उच्च न्यायालयों में केवल एक महिला मुख्य न्यायाधीश है।" रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली की जिला अदालतें देश में सबसे कम रिक्तियों वाली न्यायिक शाखाओं में से हैं, जहां 11 प्रतिशत रिक्तियां और 45 प्रतिशत महिलाएं न्यायाधीश हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि जिला न्यायपालिका में, केवल पांच प्रतिशत न्यायाधीश अनुसूचित जनजाति (एसटी) से और 14 प्रतिशत अनुसूचित जाति (एससी) से हैं। वर्ष 2018 से नियुक्त उच्च न्यायालय के 698 न्यायाधीशों में से केवल 37 न्यायाधीश एससी और एसटी श्रेणियों से हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायपालिका में अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) का कुल प्रतिनिधित्व 25.6 प्रतिशत है।

जम्मू–कश्मीर को खास पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की जरूरत : उमर अब्दुल्ला

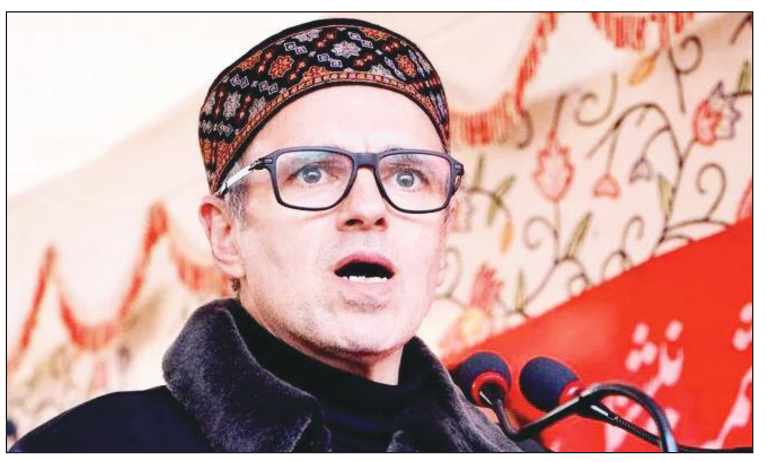

नयी दिल्ली, (भाषा) जम्मू–कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि केंद्रशासित प्रदेश एक बार फिर प्रमुख पर्यटन स्थल बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के बजाय "मूल्य आधारित पर्यटन" का रास्ता चुनने पर जोर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने यहां एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए श्रीनगर जाने वाली घरेलू उड़ानों के लिए ऊंचे हवाई किराये की भी आलोचना की, खासकर यदि टिकट यात्रा से एक या दो दिन पहले बुक किए गए हों। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाली नयी वंदे भारत ट्रेन, जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जल्द ही हरी झंडी दिखाएंगे, यात्रियों के लिए कुछ राहत लेकर आएगी। इस कार्यक्रम – आईसीसी एविएशन एंड टूरिज्म कॉन्फ्रेंस 2025 – की मेजबानी भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा की गई थी। अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू–कश्मीर की खूबसूरती लंबे समय से पर्यटकों को आकर्षित करती रही है, यहां तक कि घाटी के आतंक और हिंसा के साये में आने से भी पहले। अब्दुल्ला ने कहा, "पर्यटन एक ऐसी चीज है, जिसके लिए जम्मू–कश्मीर प्रसिद्ध है। परेशानियों के लिए कुख्याति से बहुत पहले, हम जम्मू–कश्मीर की खूबसूरती और जम्मू–कश्मीर के पर्यटन के लिए प्रसिद्ध थे। और यह खूबसूरती ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी चर्चा हाल के दिनों में होती है।" उन्होंने लाल किले की दीवार पर अंकित प्रसिद्ध पंक्ति का हवाला देते हुए अपनी बात को स्पष्ट किया, जिसमें कश्मीर को "धरती पर स्वर्ग" बताया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, "ये शब्द सदियों पहले लिखे गए थे। तब से लेकर अब तक जम्मू–कश्मीर ने बड़े पैमाने पर अच्छी चीजों के लिए ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन हाल के वर्षों में कुछ हद तक बुरे (कारणों) के लिए भी ध्यान आकर्षित किया है।" मुख्यमंत्री ने कहा, "मेरा दृढ़ विश्वास है कि जम्मू–कश्मीर को अब पर्यटन स्थल के रूप में खुद को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है... आज, मैं तेजी से इस दृष्टिकोण से सहमत हो रहा हूं कि हमें जम्मू–कश्मीर को बड़े पैमाने पर पर्यटन के लिए नहीं, बल्कि मूल्य (आधारित) पर्यटन के लिए एक गंतव्य के रूप में पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। हमें मूल्य श्रृंखला को ऊपर ले जाने की आवश्यकता है।"

हिप्र : मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कंगना को बताया 'बड़ी बहन'

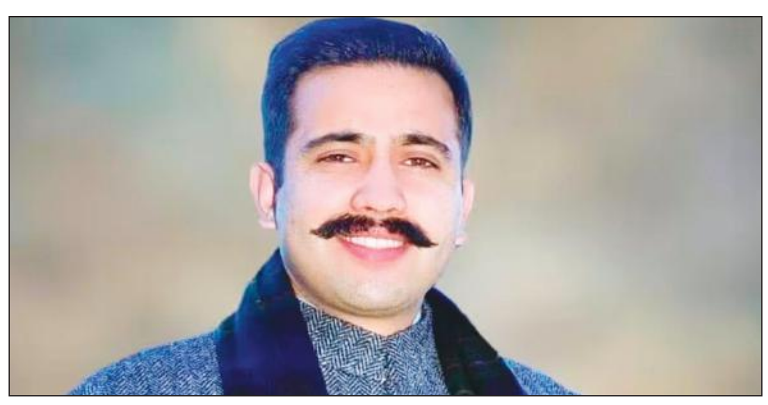

शिमला, हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपनी धुर विरोधी कंगना रनौत को 'बड़ी बहन' करार दिया। उन्होंने मंडी से लोकसभा सदस्य कंगना को विकास कार्यों के लिए केंद्रीय निधि लाने को कहा और उन्हें राज्य सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। पीडब्ल्यूडी और शहरी विकास मंत्री सिंह ने मंगलवार को कुल्लू में हिमाचल दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह से इतर संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा सांसद के लिए कहा, "हम उनका सम्मान करते हैं। वह बड़ी बहन की तरह हैं।" उन्होंने कहा, "अब कंगना एक सांसद हैं और उन्हें केंद्र व सांसद निधि से धन प्राप्त करना चाहिए। हम उनके साथ खड़े हैं और इसमें कोई राजनीति नहीं है।" मंत्री ने कहा, "उन्हें (कंगना को) हिमाचल प्रदेश में योगदान देना चाहिए। हम उनके साथ खड़े हैं और प्रशासन पूरी तरह से उनका समर्थन करेगा।" सिंह और कंगना के बीच अतीत में कई बार जुबानी जंग देखने को मिली है, खासकर पिछले वर्ष हुए लोकसभा चुनावों के दौरान, जब दोनों मंडी सीट पर आमने–सामने थे। सिंह ने कंगना रनौत को 'विवादों की रानी' करार दिया था, जबकि भाजपा सांसद (कंगना) ने राज्य सरकार में मंत्री को अप्रत्यक्ष रूप से 'छोटा पप्पू' कहा था।

जर्मन पनडुब्बी ने जहाज के साथ आंबेडकर का पीएचडी शोध प्रबंध भी पानी में डुबो दिया था

नयी दिल्ली, (भाषा) डॉ. बी.आर. आंबेडकर को शिक्षा के क्षेत्र में अपने करियर के रास्ते में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, उनमें से एक जर्मन पनडुब्बी भी थी। वर्ष 1917 में, जब प्रथम विश्वयुद्ध अपने चरम पर था, आंबेडकर ने अपने पीएचडी शोध प्रबंध का एक मसौदा और पुस्तकों का एक विशाल संग्रह एसएस साल्सेट नामक जहाज के जरिये लंदन से तत्कालीन बॉम्बे भेजा था। हालांकि एक जर्मन पनडुब्बी से दागे गए टारपीडो ने उक्त जहाज के साथ ही आंबेडकर की पुस्तकों और उनके पीएचडी शोध प्रबंध के मसौदे को इंग्लिश चैनल की गहराई में डुबो दिया था। 'प्रॉब्लम आफ रुपी' नामक पुस्तक के लेखक आंबेडकर से जुड़ी यह घटना अब एक पुस्तक का हिस्सा बन गई है। हालांकि इस घटना के बावजूद आंबेडकर ने आगे बढ़ने का अपना हौसला नहीं छोड़ा और उन्होंने अपना प्रयास दोगुना कर दिया। उन्हें कम से कम दो डॉक्टरेट और कई अन्य मानद उपाधियां मिलीं। इस घटना के साथ ही आंबेडकर के अथक शैक्षणिक प्रयासों को आकाश सिंह राठौर की पुस्तक 'बीकमिंग बाबासाहेबः द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ भीमराव रामजी आंबेडकर' (खंड 1) में शामिल किया गया है। इस पुस्तक को हार्परकॉलिन्स इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। बड़ौदा छात्रवृत्ति की अवधि समाप्त होने और रियासत द्वारा वित्तीय सहायता बढ़ाने से इनकार किये जाने के बाद आंबेडकर को वर्ष 1917 की गर्मियों में भारत लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे लंदन से रवाना हुए, वह शहर जहां उन्होंने एक साल से अधिक समय तक अथक परिश्रम किया था। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एमएससी का कोर्सवर्क पूरा कर लिया था और कोलंबिया विश्वविद्यालय में पीएचडी की तैयारी में थे। हालांकि, उन्हें अभी भी अपनी 'मास्टर्स थीसिस' जमा करनी थी और उनका डॉक्टरेट शोध प्रबंध भी पूरा नहीं हुआ था। इसके अलावा, उन्होंने 'ग्रेज इन' में अपना विधिक प्रशिक्षण शुरू ही किया था। इस प्रकार विवश होकर उन्होंने अपनी पुस्तकें और कागजात ब्रिटिश स्टीमर एसएस साल्सेट के कार्गो में अलग–अलग भेजे तथा स्वयं एसएस कैसर–ए–हिंद पर सवार होकर भारत पहुंचे। बीस जुलाई को जर्मन पनडुब्बी यूबी–40 ने एसएस साल्सेट पर एक टारपीडो दागा। इस हमले में चालक दल के 15 सदस्य मारे गए और आंबेडकर की थीसिस के साथ–साथ उनकी पुस्तकों का विशाल संग्रह भी पानी में डूब गया। राठौर ने अपनी पुस्तक में लिखा है, "टारपीडो के हमले के 45 मिनट बाद एसएस साल्सेट डूब गया, जिससे बड़ी संख्या में आंबेडकर की पुस्तकें और उनके महत्वपूर्ण कागजात समुद्र की तलहटी में समा गए।"

संपादकीय

योगी ने साकार किया राम को रोटी से जोड़ने का सपना

अपने यहां कहा जाता है,"जिसने जन्म दिया वही रोटी का भी इंतजाम करेगा"। यह ऊपरवाले पर मुकम्मल भरो. `से के साथ इस बात की ओर भी संकेत करता है कि अगर अपने इष्टदेवों से जुड़े स्थलों को सजा सवार दिया जाय। वहां आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा एवं सुविधा के मद्देनजर बुनियादी सुविधाएं विकसित कर दी जाएं तो वहां भारी संख्या में रोजी रोजगार के अवसर स्थानीय और आसपास के लोगों को उपलब्ध होते हैं। यह राम को रोटी को जोड़ने जैसा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे सच साबित कर दिया। आज शिव की अविनाशी काशी और राम की अयोध्या पर्यटकों की आमद के मद्देनजर यहां के लाखों लोगों की रोजी–रोटी का जरिया बन गए हैं। कमोबेश यही स्थिति अन्य तीर्थ स्थलों की भी है। तीरथराज प्रयाग में आयोजित महाकुंभ में तो इसका चरमोत्कर्ष दिखा। सरकार का अनुमान था कि करीब डेढ़ महीने तक चलने वाले विश्व के इस सबसे बड़े धार्मिक समागम में करीब 35 से 40 करोड़ श्रद्धालु एवं पर्यटक शामिल होंगे, पर शामिल हुए 66 करोड़ से अधिक लोग। इनमें से बहुतों की मंजिल सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, काशी, अयोध्या, वनगमन के दौरान जहां भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता सहित राम को निषादराज ने जहां उनको गंगा पार कराया था वह श्रृंगवेरपुर और वनगमन के दौरान राम ने मंदाकिनी के तट पर जिस चित्रकूट में सर्वाधिक समय गुजारा था, वह भी थी। कई लोगों ने विंध्याचल स्थित मां जगदंबा के दरबार में भी हाजिरी लगाई। अब एक पर्यटक ने औसतन इस दौरान कितना खर्च किया। इस खर्च का कितना कितना लाभ इस सेक्टर्स से जुड़े स्टेकहोल्डर्स और स्थानीय लोगों को मिला। केंद्र और राज्य सरकार के हिस्से में प्रयागराज के महाकुंभ और काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर और राममंदिर एवं अयोध्या के कायाकल्प पर हुए खर्च की तुलना में कितना लाभ हुआ, यह अर्थशास्त्र के जानकारों के लिए अनुमान विषय है। पर, यह निर्विवाद सच है कि पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं की बढ़ती आमद से लाभ में सब रहे। साथ ही इसने उत्तर प्रदेश के लिए संभावनाओं का एक नया और बड़ा दरवाजा खोल दिया। क्योंकि, बहुसंख्यक समाज के रोम रोम में बसने वाले राम की अयोध्या, तीनों लोकों से न्यारी शिव की काशी और राधा कृष्ण की जन्म भूमि, ग्वाल बालों और गोपियों के साथ लीला के स्थल ब्रज उत्तर प्रदेश में है। इन सभी जगहों की संभावनाओं के मद्देनजर योगी सरकार यहां आने वालों की सुरक्षा और सुविधा के लिहाज से लगातार काम भी कर रही है। इसका नतीजा है कि पर्यटकों की आमद के हिसाब से उत्तर प्रदेश लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। 2022 से ही घरेलू पर्यटकों के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश में नंबर एक पर बना हुआ है। सरकार के आंकड़ों पर गौर करें तो 2017 में उत्तर प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या मात्र 24 करोड़ थी, जो 2024 में बढ़कर 65 करोड़ हो गई। आठ वर्षों में 41 करोड़ की यह वृद्धि खुद में अभूतपूर्व है। स्वाभाविक है कि महाकुंभ के नाते 2025 एक नया रिकॉर्ड रचेगा। यह संख्या एक अरब का ऊपर तक जा सकती है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली चैंबर ऑफ कॉमर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 60 फीसद से अधिक घेरलू यात्राएं धार्मिक स्थलों की होती हैं। धार्मिक पर्यटन आर्थिक उन्नति और सांस्कृतिक आदान–प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धार्मिक पर्यटन की संभावनाओं का अधिकतम लाभ लेने के लिए ऐसी सभी जगहों को बेहतरीन बुनियादी सुविधाओं, सड़क और एयर कनेक्टिविटी, आने वालों की सुरक्षा और सेवा देनी होती है। यह सारा काम उत्तर प्रदेश सरकार पूरी संजीदगी से कर रही है। यह सब यूं ही नहीं हुआ। इसकी पृष्ठभूमि मार्च 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तभी से शुरू हो गई थी। तब अयोध्या जाना तो दूर की बात, कोई नेता अयोध्या का नाम तक नहीं लेना चाहता था उस अयोध्या में वह बार बार गए। हर बार उन्होंने अयोध्या को विकास की बड़ी सौगात दी। दीपावली के एक दिन पूर्व भव्य दीपोत्सव आयोजन कराया। इससे एक बार फिर देश–दुनिया में राम को मानने वालों का ध्यान अयोध्या की ओर गया। राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने और मंदिर का शिलान्यास होने के बाद तो केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार ने अयोध्या के कायाकल्प के लिए खजाने का मुंह खोल दिया।

मुख्यमंत्री की मंशा अयोध्या की दुनिया की सबसे खूबसूरत पर्यटन नगरी बनाने की है। इसे वे कई बार सार्वजनिक मंचों से भी कह चुके हैं। उसी मंशा के अनुरूप अयोध्या में लगातार काम भी हो रहे है। काशी, प्रयाग, ब्रज क्षेत्र पर भी उनका इसी तरह फोकस है। उल्लेखनीय है कि राम और रोटी का रिश्ता अटूट है। दोनों एक–दूसरे के पूरक हैं। राम मंदिर आंदोलन को धार देकर भाजपा ने इसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सबसे प्रमुख एजेंडा बनाया। करीब 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद जब राम मंदिर आंदोलन के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो केंद्र और उत्तर प्रदेश में भाजपा ही सत्ता में रही। सोने पर सुहागा यह कि इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर स्थित गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ थे। यह वह पीठ है जिसका राम मंदिर आंदोलन से वास्ता करीब 100 वर्षों का है। योगी के दादागुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ, गुरु ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ और खुद योगी आदित्यनाथ राम मंदिर आंदोलन के हर महत्वपूर्ण घटना के समय मौजूद रहे। ऐसे में जनमानस के मन में यह बैठ गया है कि अयोध्या में श्रीराम को फिर से पुनर्स्थापित करने का काम भाजपा ने किया। इस काम में गोरक्षपीठ की अहम भूमिका रही। बतौर पीठ के पीठाधीश्वर एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न केवल इस कसौटी पर खरे उतरे, बल्कि काशी, मथुरा, प्रयागराज सहित अन्य धार्मिक स्थलों के नियोजित विकास से अपने पद एवं दायित्व के अनुसार उसे विस्तार भी दिया। यह सिलसिला अभी जारी है।

कृष्णा अग्रवाल
focusnews9@gmail.com

महत्वपूर्ण है बच्चों की आंखों की सुरक्षा

हम अपने चारों ओर देखें तो पाएंगे कि जीवन में जो वस्तुएं अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं, उन पर अनजाने, अनचाहे हम ध्यान नहीं दे पाते। इसका कारण अशिक्षा तो है ही, हमारी असावधानी भी है। यदि सावधानी रखी जा सके तो ऐसी क्षति जो अज्ञानवश घटित होती है, उससे उबरा जा सकता है। हमारे शरीर का प्रत्येक अंग अमूल्य है, कोई अधिक या कम महत्त्वपूर्ण नहीं है लेकिन आंखों का महत्त्व तो वही जान सकता है जो आंखों के अंधेरे को भुगत चुका हो। आंखें हमारे लिए अमूल्य हैं। जो कुछ बाहर घटित हो रहा है, जो कुछ हमारे अन्दर चल रहा है, उसके दर्शन केवल आंखों से ही हो सकते हैं किन्तु इतने महत्त्वपूर्ण अवयव के प्रति भी हम उपेक्षा बरतते हैं, इसका क्या अर्थ हो सकता है?

बच्चों को आंखों के रोग हमारी उदासीनता से हो सकते हैं। आंखों के रोग सामान्यतः दो वर्ष से पांच वर्ष की उम्र में होते हैं। ये रोग विटामिन 'ए' की कमी से होते हैं। यदि इसका पता प्रारम्भ से न हो तो बच्चा अंधा तक हो सकता है, इसलिए यह जान लेना आवश्यक है कि कैसे यह पता चले कि बच्चा विटामिन 'ए' की कमी का शिकार है। जैसे ही यह पता चले, उसका उपचार प्रारंभ हो जाना चाहिए। उपचार का न होना एक खतरनाक बिन्दु है जिसका सुधार बाद में नहीं हो सकता।

रतौंधी में बच्चा सामान्य बच्चों की तरह अंधेरे में नहीं देख सकता। इस बच्चे की आंखें शुष्क हो जाती हैं। आंखों की सफेदी अपनी चमक खोने लगती है। आंखों पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं। आंखों में भूरे रंग की छोटी–छोटी फुंसियां हो सकती हैं। यह रोग जैसे–जैसे बढ़ता है, आंखों की पुतली भी सूखी और तेज रहित दिखाई देने लगती है और आंखों पर छोटे–छोटे गड्ढे भी पड़ सकते हैं। यह अंतिम स्थिति है। इसके बाद शीघ्र ही आंख की पुतली मुलायम सी पड़ने लगती है या उसमें उभार आ सकता है या वह फूट सकती है। इसमें सामान्य रूप से दर्द नहीं होता। बच्चों को स्तनपान कराना इस बीमारी से बचने के लिए महत्त्वपूर्ण है। यदि बच्चा दो वर्ष तक स्तनपान करे तो इस रोग से बचने के लिए सहायक होगा किन्तु इसके अतिरिक्त बच्चों को पहले छह महीनों के बाद हरी पत्तेदार सब्जियां, लाल–पीले फल व सब्जियों जैसा आहार देना भी आवश्यक है क्योंकि इनमें विटामिन 'ए' पाया जाता है। इसके अतिरिक्त दूध, अंडा, कलेजी, मांस आदि में भी विटामिन 'ए' पाया जाता है। बच्चों में यह रोग विटामिन 'ए' की कमी से ही होता है। आंखों को दुर्घटना से बचाएं:– यह तो बीमारी की बात हुई। बच्चों के अंधत्व के लिए दुर्घटनाएं भी बड़ी संख्या में उत्तरदायी हैं। हमारे देश में रामायण सीरियल के प्रारम्भ होने पर अनेक बच्चों ने खेल–खेल में धनुष बाण चलाए और आंखें क्षतिग्रस्त हुई। बच्चों को खतरनाक खेलों से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए ऐसे खेलों के प्रति सावधान रहना आवश्यक है। हमारे देश में आंखों की क्षति गुल्ली डण्डा, तीर–कमान व पत्थरों के खेलों से अधिक होती हैं। दीपावली या अन्य उत्सवों पर पटाखे चलाने या छोड़ने से भी आंखों को क्षति पहुंचती है। अतः आवश्यक है कि बच्चे आपकी उपस्थिति में पटाखे चलाएं। दुर्घटना घट जाने के बाद पछताने के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं बचता। इसी प्रकार से नुकीली वस्तुओं को दूर रखिए। इनसे आंखें दुर्घटनाग्रस्त हो सकती हैं। जो आंकड़े उपलब्ध हैं, उनसे स्पष्ट है कि बड़ी संख्या में आंखों का नुकसान दुर्घटनाओं से होता है। यह ऐसा अंधत्व है कि जिस पर किसी का बस नहीं रह जाता। बाद में आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं। आज से ही सावधानी बरतना व निरन्तर इनके तथ्यों को स्मरण रखना आपके अच्छे माता–पिता होने का सबूत है।

बच्चों की आंखों पर ध्यान दीजिए:– बच्चों की आंखों पर माता पिता व शिक्षकों द्वारा निरंतर ध्यान देना अब समय की आवश्यकता हो गई है। बड़ी संख्या में बच्चे आंखों की कमजोरी के कारण चश्मा पहनने लगे हैं, इसलिए आवश्यक है कि बच्चा यदि ब्लैक बोर्ड को देख नहीं पा रहा, पुस्तक को आंख के पास ला कर पढ़ रहा है या खेल में अन्य बच्चों की तरह गेंद को पकड़ नहीं पा रहा तो आप बच्चे की आंखों की जांच अवश्य कराएं। यदि बच्चा धुंधलेपन की शिकायत करे, उसकी पुतलियां लाल तथा सूजी हों, पढ़ते समय आंखों को मलता हो या रंग पहचानने में परेशानी हो तो तत्काल नेत्रा चिकित्सक को दिखाएं।

चश्मा पहनने से परेशान न हों:– हमारे देश में चश्मा पहनने से बचना एक आदत है। विशेष रूप से माताएं अभी भी यह मानती हैं कि यदि बेटी चश्मा पहन लेगी तो उसके विवाह में परेशानी होगी क्योंकि यह माना जाएगा कि बेटी की आंखें कमजोर हैं पर यह व्यर्थ की बात है। इसे दूर किया जाना चाहिए। चश्मा पहनने से आंखों की क्षमता बढ़ जाती है और बच्चा खेल में पूरी शक्ति से पढ़ाई में पूर्ण मनोयोग से भाग लेकर महान सफलताएं अर्जित कर सकता है।

शिक्षक–पालकों का योग:– बच्चों की आंखों की सुरक्षा के लिए शिक्षक भी यदि कक्षा में, खेल के मैदान में ध्यान दें और कमजोर आंखों वाले बच्चों को विशषज्ञों को दिखाने की व्यवस्था करें वो अपना तो कर्तव्य पूरा करेंगे ही, पुण्य लाभ भी प्राप्त करेंगे। देश के लिए अंधत्व नियंत्राण कार्यक्रम में हर कोई हर कहीं सहयोगी हो सकता है।

अच्छी आदतों का निर्माण:– शिक्षक व माता पिता आंखों की देखभाल के लिए अच्छी आदतों का निर्माण भी कर सकते हैं जैसे बच्चों को दिन मे कम से कम तीन बार अपनी आंखें धोनी चाहिए। पढ़ने के लिए पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए। टेलीविजन को देखते समय बच्चों को कम से कम तीन मीटर दूर बैठना चाहिए।

अशिक्षा व असावधानी हमारे शत्रु हैं। आंखें इन्हें दूर करने का साधन हैं। इसकी रक्षा कीजिए। देश के भविष्य बच्चे आपका भी भविष्य हैं। उन को दिशादान दीजिए।

लाभदायक है फल, सब्जियों के रस का सेवन

उत्तम स्वास्थ्य के लिए अच्छे व संतुलित आहार के साथ–साथ ताजे फलों एवं सब्जियों के रस भी बहुत लाभकारी होते हैं। इनमें खनिज लवणों, विटामिनों, एंजाइम आदि तत्वों की भरपूर मात्रा होती है। फलों के रस शरीर में संचारित होने वाले रक्त के अल्कलाइन भंडार में वृद्धि करते हैं जिससे शरीर के भीतर आंतरिक रसों का उत्पादन बढ़ता है। जिनकी पाचन शक्ति कम होती है या जो उदर रोगों से पीड़ित रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए फलों एवं सब्जियों का रस अत्यन्त उपयोगी होता है। आइये, देखते हैं कुछ रसों का महत्त्व–

चुकन्दर का रस – चुकन्दर रक्त शुद्धि के लिए बेहद उपयोगी है। खून की परेशानियों, त्वचा संबंधी रोग व कब्ज से पीड़ित रोगों के लिए चुकन्दर लाभकारी है। इसके सेवन से लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में मदद मिलती है। अनीमिया के रोगियों के लिए यह बहुत लाभकारी होता है। सुबह–सुबह दो बड़े चम्मच चुकन्दर का रस पीने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है तथा दिन भर ताज़गी बनी रहती है।

टमाटर का रस – पके हुए टमाटर में विटामिन 'ए' और विटामिन 'सी' प्रचुर मात्रा में एवं अन्य विटामिन व खनिज सूक्ष्म मात्रा में मौजूद होते हैं। टमाटर का रस सुस्त जिगर को सक्रिय करता है। यह यकृत, पाचन क्रिया एवं त्वचा की सभी परेशानियों को दूर करने में मदद करता है।

पालक का रस – इसमें विटामिन 'ए' और कई खनिजों का अच्छा स्रोत पाया जाता है। इसे टमाटर या गाजर के रस के साथ मिलाकर अगर लिया जाए तो यह काफी फायदेमंद साबित होता है। अल्सर, अनीमिया, कब्ज, मोटापा, आंखों की तकलीफ एवं सिरदर्द से पीड़ित व्यक्तियों के लिए पालक का रस बहुत लाभकारी होता है।

मेथी का रस – मेथी के पत्तों का रस कृमिनाशक, अपच को दूर करने वाला व बवासीर में लाभ पहुंचाने वाला होता है। मेथी में विपुल मात्रा में लौह तत्व होता है अतः पाण्डुरोग में भी यह गुणकारी होता है। यद्यपि कच्ची भाजी के रस का सेवन अत्यधिक लाभदायक होता है, तथापि पकाने की इच्छा हो तो उसे प्रेशरकुकर में अथवा वाष्प से थोड़ी मात्रा में उबालकर उसी पानी में उसका सूप पीना लाभदायक होता है।

पोदीना का रस – पोदीना (पुदीना) के पत्तों को पीसकर उसका रस निकाल लिया जाता है। दो चम्मच पोदीना का रस, एक चम्मच नींबू का रस तथा दो चम्मच शहद का मिश्रण पेट की शिकायतों में लाभ प्रदान करता है। यह कृमिनाशक, हैजा रोधी तथा सुपाचक होता है। पोदीना, प्याज तथा नींबू के रस को बराबर मात्रा में मिला कर लेने से हैजा में निश्चित लाभ होता है।

अनन्नास का रस – इसमें कई विटामिन एवं खनिज होते हैं। इसमें 'पापाइन' तथा 'ब्रोमेलिन' नामक दो एंजाइम पाए जाते हैं। ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। गले के दर्द, टांसिल, सर्दी–जुकाम व पेट की गड़बड़ी में अनन्नास का रस बहुत उपयोगी होता है।

गाजर का रस – इसका रस रक्त शुद्धि के लिए अत्यन्त उपयोगी है। जिन लोगों को एसिडिटी हो, आंखों में इंफेक्शन हो या सांस संबंधी तकलीफ हो, उन्हें इनका सेवन अवश्य करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को नित्य गाजर के रस का सेवन करना चाहिए। इससे मां एवं शिशु दोनों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। गाजर का रस बल–पुष्टि प्रदान करता है।

खीरे का रस – खीरा एवं ककड़ी के रस के सेवन से मूत्रा संबंधी अनेक रोग दूर होते हैं। इसका रस मूत्रा की निकासी में तेजी लाता है और अवशिष्ट व नुक्सानदेह पदार्थों को मूत्रा के माध्यम से बाहर निकालने में मदद करता है। यह मूत्रा तंत्रा को सही रखता है तथा शीघ्र स्खलन एवं कामशीतलता को भी दूर करता है। इसका रस त्वचा की आभा को भी निखारने में मदद करता है।

नींबू का रस – नींबू के रस में यदि शहद मिलाकर सेवन किया जाए तो मोटापा घटाने में सहायक होता है। इसके सेवन से पेट और खून भी साफ होता है। पेट में जलन या एसिडिटी होने पर नींबू का सेवन नहीं करना चाहिए। नींबू के रस की सहायता से त्वचा कोमल होती है तथा कील मुंहासे दूर होते हैं।

संतरे का रस – संतरे में विटामिन 'सी' अत्यंत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। स्कर्वी नामक रोग से यह विटामिन बचाता है। विटामिन 'सी' के साथ–साथ इसमें कैल्शियम और फास्फोरस भी पाये जाते हैं। संतरे का रस सर्दी–जुकाम में अत्यंत लाभकारी होता है। यह उदरकृमि, उदरशूल का नाश करता है तथा हड्डियों को मजबूत करता है।

दूर करें अपने मनोगत अवरोध

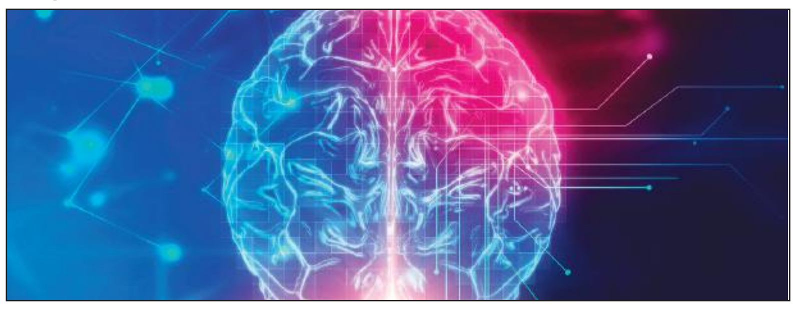

श्री 'ख' अपरिचित लोगों के सामने मुंह ही नहीं खोल पाते। उनकी जुबान पर जैसे ताला सा लग जाता है, वह हकलाने लगते हैं। उन के मन में यह बैठ गया है कि वह अनजान लोगों के सामने समयोचित वार्तालाप नहीं कर पाएंगे।

श्री 'ग' स्टेज पर जाने के नाम से ही नर्वस हो जाते हैं। उन के हाथ–पांव फूल जाते हैं, पसीने छूटने लगते हैं। मुझे याद है कि स्कूल कॉलेजों के दिनों में मैं पढ़ाई में सब से आगे रहता था मगर खेलकूद के नाम से मुझे घबराहट होने लगती थी। मेरी यह दृढ़ धारणा बन गई थी कि मैं कोई भी गेम ठीक से नहीं खेल पाऊंगा।

उपरोक्त किसी भी व्यक्ति में किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक अथवा मानसिक त्राुटि हो या कमी हो, ऐसी कोई बात नहीं है। केवल अपनी कल्पना में ही उन्होंने ऐसा मान लिया है। एक भ्रम पाल लिया है। वे चाहें तो अपनी इस धारणा से उबर सकते हैं, इस भ्रमजाल को काट सकते हैं मगर वे इस हेतु प्रयास ही नहीं करते क्योंकि यह धारणा इन के मन–मस्तिष्क पर पूरी तरह हावी हो गई है। उन्होंने इस से समझौता ही कर लिया है। इस स्थिति को 'मैंटल ब्लाक्स' अर्थात् ' मनोगत अवरोध' कह सकते हैं।

मजे की बात यह है कि ऐसा कोई न कोई मानसिक अवरोध हम में से अधिकांश लोग पाले रहते हैं यद्यपि उसे हम इस रूप में या इस नाम से नहीं जानते अथवा स्वीकार नहीं करते। उसे हम अभिरूचि, रूझान, प्रवृत्ति, पसंद, दिलचस्पी का नाम दे देते हैं।

दिन–प्रतिदिन के जीवन में तो इससे अड़चनें आती ही हैं, यह अवरोध हमारे कैरियर को भी प्रभावित करता है। हर प्रकार से सुयोग्य होते हुए भी इन मनोगत अवरोधों से ग्रस्त व्यक्ति प्रायः व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं। स्वयं को प्रोजेक्ट करने में ये अवरोध कहीं न कहीं, किसी न किसी प्रकार, उनके आड़े आ जाते हैं।

मनोवैज्ञानिक इन मनोगत अवरोधों के लिए कई कारण बताते हैं। उनके अनुसार बचपन में मिला पारिवारिक वातावरण, माता–पिता के आपसी संबंध, बहन–भाइयों का व्यवहार, बाल्यकाल में घटी कोई घटना–दुर्घटना देखना या सुनना कोई असामान्य दृश्य आदि जीवन भर के लिए व्यक्ति के मन में एक ग्रंथि उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह सही है कि अवचेतन में गहरे पैठे, जकड़ जमाए इन मनोगत अवरोधों से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है किन्तु यह भी उतना ही सही है कि बिना इन से छुटकारा पाए व्यक्ति सही अर्थों में स्वयं को सामान्य भी नहीं कह सकता और न ही एक सामान्य व्यक्ति जैसा जीवन ही जी सकता है।

यह भी एक ध्रुव सत्य है कि मनुष्य यदि दृढ़ निश्चय कर ले तो असम्भव को भी सम्भव बनाने का सामर्थ्य रखता है। महान व्यक्तियों की जीवनियां स्पष्ट बताती हैं कि उन में भी कोई न कोई कमी, कमजोरी, दोष, दुर्बलता थी जिसे उन्होंने अपने अध्यवसाय, लगन व दृढ़ निश्चय से दूर करने में सफलता पाई।

स्कूल के दिनों में हमारे एक अनुभवी अध्यापक ने, जो स्वयं एक सफल वक्ता थे, मंचभीति (स्टेज फ्राइट) से निबटने के लिए एक आसान या घरेलू नुस्खा बताया था, जिसमें हींग लगे न फिटकरी और रंग भी चोखा आए। इनका कहना था कि घर से दूर खेतों में निकल जाओ, पेड़–पौधों को श्रोताओं की भीड़ मान लो और उन्हें अपना भाषण पूरे आत्मविश्वास के साथ सुनाओ, बार बार सुनाओ।

यह एक तथ्य है कि हम में से वे विद्यार्थी जिन्होंने उनकी बात गांठ बांध ली और वैसा अभ्यास किया, स्टेज फ्राइट से सदा के लिए मुक्त हो गए तथा अच्छे वक्ता बन गए। इसी प्रकार अभ्यास, निरंतर अभ्यास से इन मनोगत अवरोधों पर काबू पाया जा सकता है। इस में रत्ती भर भी संशय नहीं। कहा भी तो गया है:

'करत–करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान
रसरि आवत जात ते सिल पर पड़त निसान।'

अतः पहला काम है अपने मनोगत अवरोध को पहचानना, तदुपरांत आवश्यक है उस से छुटकारा पाने हेतु दृढ़ संकल्प करना तथा तद्नुसार आवश्यक कदम उठाना। जरा सोचिए, आखिर क्यों लादें फिरें हम इन मानसिक अवरोधों को। क्यों न झटक दें इन्हें अपने पल्लू से। ऐसा करना ज्यादा कठिन भी तो नहीं है।

मुंह की बदबू दूर करता है पुदीना

भोजन में पुदीने का जितना महत्त्व है, उतना अन्य किसी शाक, सब्जी या फल का नहीं है। चाहे शर्बत बनाना हो या खुशबूदार चटनी का स्वाद लेना हो अथवा कढ़ी में भीनी–भीनी खुशबू हो, पुदीने को प्रयोग में लीजिए।

सर्वसुलभ सस्ता एवं रोगनाशक पुदीना हमारे देश में लगभग हर जगह उपलब्ध है। पुदीना अपच एवं दमा जैसे रोगों से भी मुक्ति दिलाता है। पुदीने का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है। यूं विश्व में सबसे अधिक पुदीने का उत्पादन चीन में होता है। पुदीना वातनाशक होता है। यदि आपने भोजन अधिक कर लिया है या पाचन संबंधी अन्य कोई शिकायत है तो पुदीने में थोड़ा अजवायन और नींबू का रस मिला कर शर्बत तैयार कीजिए और पी जाइए। कुछ ही समय में अपच और पेट की गड़बड़ी खत्म हो जाएगी।

कहा जाता है कि पुदीने की पत्ती को मुंह में रखकर चूसते रहने से अमृत उत्पन्न करता है। इससे मुंह की दुर्गन्ध तो गायब होती ही है साथ ही दांतों की सड़न भी दूर हो जाती है और दांत पूर्णतः स्वस्थ एवं निरोग हो जाते हैं।

पुदीने की चटनी अरूचि दूर करती है। यदि भूख होते हुए भी भोजन न करने की इच्छा हो तो थोड़ी सी चटनी खाकर एक गिलास पानी पीजिए। फिर देखिये आप भोजन के प्रति कितनी रूचि महसूस करते हैं।

पुदीना रूचिकर, वायु एवं कफनाशक तथा पाचन शक्ति बढ़ाने वाला होता है। पेट में कृमि, हैजा एवं खांसी जैसी शिकायतें भी पुदीना फौरन दूर कर देता है। पुदीने के नियमित रूप से सेवन करने से मस्तिष्क स्वस्थ व प्रसन्न रहता है। यदि आपको भूख नहीं लगती और दुर्बलता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तो फिक्र मत कीजिए। पुदीना आपकी हर शिकायत दूर कर देगा। पुदीने के पत्ते, थोड़े से तुलसी के पत्ते, दो चार दाने काली मिर्च एवं एक कली अदरक में आधा नींबू निचोड़कर पीजिए। आप दिन में एक बार नहीं बल्कि दो बार भोजन करेंगे और पाचन क्रिया भी विधिवत रहेगी। नियमित रूप से पुदीने का रस पीने से कृमि दूर हो जाते हैं एवं वायु संबंधी गड़बड़ी भी दूर हो जाती है। पुदीने का ताजा रस शहद के साथ मिलाकर सेवन करने से ज्वर दूर हो जाता है तथा न्यूमोनिया से होने वाले विकार भी नष्ट हो जाते हैं। यदि आँतों की खराबी, शिथिलता या पेट के कोई अन्य रोग हों तो पुदीने का सेवन कर इन्हें दूर किया जा सकता हैं। पेट में अचानक दर्द उठता हो या मरोड़ हों तो अदरक और पुदीने के रस में थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर सेवन कीजिए, पेट दर्द गायब। यूं पुदीने से तो कई शारीरिक समस्याएं भी दूर हो जाती हैं परन्तु यदि नियमित रूप से पुदीने का सेवन किया जाए तो शरीर में रोग होने ही नहीं पाते।

पुदीना विटामिन 'ए' का भंडार है। पुदीना में जितने विटामिन उपस्थित रहते हैं, उतने अधिक न तो किसी खास पदार्थ में होते हैं न ही किसी औषधि में। एक तरह पुदीना चमत्कारिक औषधि ही है। पुदीना संभोगशक्ति तो बढ़ाता ही है, इससे शरीर में तंदुरूस्ती का आलम भी बना रहता है।

बहुत फायदे हैं तरबूज के

गरमी के मौसम में पैदा होने वाले फलों में तरबूज सर्वश्रेष्ठ फल है क्योंकि वह स्वादिष्ट, शीतल तथा स्वास्थ्यवर्धक ही नहीं बल्कि इतना सस्ता भी होता है कि इसे गरीब से गरीब आदमी भी खा सकता है। गरमी के झुलसाने वाले मौसम में अपनी शीतलता से तन–मन को ठंडक पहुंचाने वाला यह फल रेगिस्तानी क्षेत्रों में तो बहुत ही प्रतिष्ठित माना जाता है। इसे जो खाता है, उसे यह लू से तो बचाता ही है, साथ ही यह उसके शरीर में पानी की कमी भी नहीं होने देता। सचमुच यह फल हमारे लिए वरदान ही है जिसके कारण गरमी जैसे आग बरसाने वाले मौसम में भी तरबूज जैसा शीतल और मधुर फल पैदा होता है। पूरी तरह पके हुए इस फल में 76 प्रतिशत खाने योग्य गूदा, प्रति किलोग्राम तरबूज में लगभग 40 ग्राम लाल अथवा काले रंग के बीज तथा 24 प्रतिशत न खाने योग्य छिलका होता है। यह छिलका मनुष्य के खाने योग्य तो नहीं होता किंतु यह दुधारू पशुओं हेतु अति पौष्टिक आहार है। इसे उन्हें यदि नियमित खिलाया जाए तो उनकी दूध देने की क्षमता और भी बढ़ जाती है।

शीघ्र पाचक शर्करा से युक्त क्षार प्रधान इस फल में जो 76 प्रतिशत खाने योग्य गूदा होता है, वह जितना शीतल तथा मधुर होता है उतना ही स्वास्थ्यवर्धक भी क्योंकि उसमें 96 प्रतिशत जल, 3º2 प्रतिशत कार्बोहाईट्रेट, 0.3 प्रतिशत प्रोटीन 0,2 प्रतिशत खनिज लवण तथा 0.2 प्रतिशत वसा भी होता है। इन तत्वों के अलावा इसमें प्रति 100 ग्राम गूदे में 11 मिली ग्राम फास्फोरस, 8 मिलीग्राम लौह तथा 12 मिलीग्राम कैल्शियम तो होता ही है, साथ ही उसमें अति अल्प मात्रा में विटामिन–सी तथा पोटेशियम लवण भी होता है।

तरबूज का 100 ग्राम गूदा हमारे शरीर के लिए 37 कैलोरी ऊर्जा देता है जबकि यदि हम तरबूज के बीजों की 100 ग्राम गिरी खा लें तो हमें 512 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। हालांकि बीजों की तुलना में गूदा ज्यादा स्वादिष्ट होता है लेकिन गूदे की अपेक्षा बीज कुछ ज्यादा ही पौष्टिक होते हैं। इसके बीजों में 50 प्रतिशत वसा, 34 प्रतिशत प्रोटीन, तथा 4 प्रतिशत जल होता है। इसके अलावा प्रति 100 ग्राम बीज में 100 मिलीग्राम कैल्शियम, 937 मिलीग्राम फास्फोरस तथा 3 मिलीग्राम लौह होता है। यही कारण है कि ठंडे शर्बतों के निर्माण एवं विभिन्न प्रकार की मिठाइयों की पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उनमें तरबूज के बीज भी डाले जाते हैं।

मेरे पिता मेरे अभिनय के सपने को लेकर डरे हुए थे : बाबिल खान

नयी दिल्ली, (भाषा) मशहूर अभिनेता इरफान खान के बेटे बाबिल खान का कहना है कि उनके पिता हमेशा उनकी यादों और बातों में जिंदा हैं और उनका सपना अपने पिता की तरह ही एक ''कलाकार'' बनना है। बाबिल कहते हैं कि वह अपने इस सपने को स्वीकारने से डरते थे क्योंकि सच कहूं तो इरफान खान बहुत ''उम्दा कलाकार'' थे और देखा जाए तो ''बाप–बेटे'' के बीच अपना अपना एक अहम भी होता है। इरफान उन चुनिंदा भारतीय कलाकारों में शामिल हैं जिन्होंने न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी खूब नाम कमाया। बाबिल (26) अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए 'कला' जैसी फिल्म और 'द रेलवे मेन' जैसी वेबसीरीज से अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। उनके फिल्मी करियर की राह में कई मोड़ आए। बाबिल एक खिलाड़ी बन सकते थे, लेकिन एक चोट ने उनकी आकांक्षाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया और फिर वह ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी से सिनेमैटोग्राफी का कोर्स करने पहुंच गए। उन्होंने कहा कि वह अपने पिता से यह कहने से डरते थे कि वह भी फिल्मों में आना चाहते हैं। बाबिल ने 'पीटीआई–भाषा' के साथ एक विशेष साक्षात्कार में कहा, ''...क्योंकि बाप–बेटे के बीच अपना एक अहम होता है...ये भी डर था कि अगर मैं नाकाम हो गया तो? क्योंकि वह बहुत महान कलाकार थे। लेकिन आखिर में मैंने उनसे अपने दिल की बात कह दी। यह सुनकर वह मेरे लिए काफी डर गए क्योंकि वह जानते थे कि उन्होंने मुझे कैसे पाला है। मैं बहुत संवेदनशील बच्चा था।'' उन्होंने बताया कि अब उन्हें यह अहसास हुआ है कि उन्हें सिनेमैटोग्राफी पसंद है लेकिन फोटोग्राफी के एक शौक की तरह। बाबिल का कहना था, '' मेरा जुनून परफोर्मेंस है। ये अभिनय भी हो सकता है, संगीत भी हो सकता है। अभी मैं बहुत ही शर्मिला किस्म का गायक हूं। थोड़ा अभिनय करने के बाद मैं इसमें हाथ आजमाना चाहूंगा।'' बाबिल जब पढ़ रहे थे तभी इरफान को पता चला था कि उन्हें कैंसर है। इरफान खान का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। बाबिल ने उन दिनों के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा, ''मैं यूनिवर्सिटी से वापस आकर बाबा के साथ समय बिताने वाला था। मैंने सोचा ही नहीं था कि वह हमें छोड़कर चले जाएंगे। ममा (मां) को भी लगता था कि वह कैंसर से 100 प्रतिशत ठीक हो जाएंगे।'' उन्होंने कहा, ''उन्होंने कैंसर को हराया और फिर हमें छोड़कर चले गए...। उन्हें दुनिया छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि कीमो (कीमोथेरेपी) ने उनके शरीर को बर्बाद कर दिया था। कैंसर कोशिकाएं बिल्कुल नहीं थीं लेकिन शरीर की प्रतिरोधक क्षमता एकदम खत्म हो गई थी। एक छोटे से संक्रमण ने उनकी जिंदगी छीन ली। उन्होंने कैंसर को मात दी। यह भी कितनी खूबसूरत बात थी कि उन्होंने अपनी आखिरी चुनौती से भी पार पा लिया।'' अप्रैल 2020 वो महीना था जब भारत में कोविड–19 महामारी के कारण 'लॉकडाउन' लगा था लेकिन इससे इरफान के प्रशंसकों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बाबिल ने बताया, ''जब उनके जनाजे को कब्रिस्तान ले जाया जा रहा था तब सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था...। मुझे एहसास हुआ कि उनका जाना सिर्फ मेरे जीवन का खालीपन नहीं था। इसलिए एक परिवार के नाते हमने एक नोट लिखा, हम सबने इसे मिलकर लिखा और हमने कहा कि उनके जाने से सिर्फ हमें ही उनकी कमी नहीं खलेगी बल्कि सबको उनकी कमी खलेगी जिसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता।'' यही वह समय था जब सोशल मीडिया पर बाबिल की सक्रियता बढ़ गई थी। यही वह समय था जब उन्होंने अपनी भावनाओं के बारे में पूरी तरह से खुलकर बात की थी। उन्होंने कहा, ''लोग मेरे पास आते, मुझे गले लगाते और रोते थे। उस वक्त मैं लोगों के बहुत करीब महसूस करता। मुझे बाबा के साथ जुड़ी निजी यादों के प्रति जिम्मेदारी का एहसास हुआ।'' बाबिल ने कहा कि जैसे–जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ी, उन्हें यह भी एहसास होने लगा कि सोशल मीडिया की प्रसिद्धि का एक स्याह पक्ष भी है और 'ट्रोल्स' आपकी भावनात्मक सेहत पर बुरा असर डाल सकते हैं। उन्होंने कहा, ''मेरी मासूमियत पर असर पड़ने लगा। मुझे खुद को बचाना था... इसलिए मैंने उस मंच पर जाना बंद कर दिया।'' अभिनेता ने कहा कि एक समय वह सोशल मीडिया पर सुरक्षित महसूस करते थे क्योंकि लोगों में उनके पिता के लिए प्यार था और जब वह अभिनेता बने तो उन्होंने शुरुआती 'ट्रोलिंग' को सहजता से लिया। पिछले साल 'रेड कार्पेट' पर एक अन्य अतिथि से माफी मांगने की उनकी एक क्लिप व्यापक रूप से प्रसारित हुई और बाबिल एक बार फिर बड़े पैमाने पर 'ट्रोलिंग' का निशाना बन गए, जिसमें बिना वजह टिप्पणियों में उनके पिता का नाम घसीटा गया। बाबिल ने कहा, ''मैं टूट गया क्योंकि मुझे लगा कि ये मैंने किया और इससे उनकी (इरफान की) छवि प्रभावित हो रही है।'' उन्होंने कहा कि उनकी मां सुतापा सिकदर ने उनसे कहा कि उनके पिता इस सब की कोई परवाह नहीं करते।जी5 पर 18 अप्रैल को रिलीज होने वाली 'लॉगआउट' के निर्माण के दौरान ही वह इस बात को समझ पाए कि सोशल मीडिया पर लोग दूसरों से क्यों नफरत करते हैं। उन्होंने कहा, ''मेरा मानना है कि हमने अपने आत्मसम्मान को दूसरों की स्वीकृति के सामने गिरवी रख दिया है। हमने दूसरों की राय पर आधारित अपनी छवि से अपनी पहचान को जोड़ लिया है। इसलिए हम लगातार खुद की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। और इसी के चलते हम खुद के लिए नफरत पैदा कर रहे हैं जिसे हम दूसरों पर थोपते हैं।'' बाबिल का एक सपना है– भारत में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार लाना। उन्होंने यह भी साफ किया कि वह पूरी तरह से एक पेशे से बंधे नहीं रहना चाहते हैं। वर्ष 2022 में आई अपनी पहली फिल्म 'कला' में उन्होंने एक प्रतिभाशाली शास्त्रीय संगीतकार का किरदार निभाया था। 'द रेलवे मेन' में उन्होंने रेलकर्मी का किरदार निभाया जो 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के दौरान लोगों की जान बचाता है। 2023 की फिल्म 'फ्राइडे नाइट प्लान' और अब की 'लॉगआउट' युवा किरदारों पर आधारित हैं। 'लॉगआउट' में उन्होंने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की भूमिका निभाई है जिसका फोन गुम हो जाने के बाद उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है।

बाबिल ने कहा, ''मेरे माता पिता ने बहुत सोच समझ कर मुझे फोन और तकनीक से दूर रखा था...। दूसरे बच्चों पर इसका असर जो पड़ रहा था, वह उन्हें पसंद नहीं था। एक बात जो बाबा ने मुझे बताई थी और जो मुझे तब समझ में नहीं आई, वह यह थी, 'अगर तुम इन चीजों से दूर नहीं रहोगे तो तुम खुद से दूर हो जाओगे।'' उन्होंने कहा कि उन्हें याद है कि कैसे एक बार उनके पिता ने उन्हें अपना टूटा हुआ ब्लैकबेरी फोन दे दिया था, जबकि उनके साथी पहले से ही बेहतर फोन इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने बताया, '' उस समय मैं परेशान हो जाता था लेकिन आज मैं आभारी हूं उनका क्योंकि मेरा स्क्रीन टाइम बहुत कम है। मैं केवल अपने फोन पर संगीत सुनता हूं और नोट्स ऐप इस्तेमाल करता हूं।'' अपने माता–पिता के साथ अपने किशोरावस्था के दिनों को याद करते हुए बताया कि उनके पिता उनके साथ शतरंज का खेल यह जानने के लिए खेलते थे कि उनका बेटा कैसा महसूस कर रहा है। बाबिल ने बताया,'' वह अक्सर कहते थे, बोरियत को महसूस करो। बैठो और बैठ कर बोरियत को महसूस करो। अगर तुम्हें बोरियत हो रही है तो कुछ देर तक बोर होते रहो। समस्या क्या है? तुम्हें किसी काम को करने की इतनी जल्दी क्यों है?''

संगीत में एआई का संभावित दुरुपयोग ऑक्सीजन में जहर घोलने जैसा : ए.आर. रहमान

मुंबई, (भाषा) ऑस्कर पुरस्कार विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान का कहना है कि संगीत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के इस्तेमाल के अच्छे और बुरे दोनों पहलू हैं, लेकिन अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो अराजकता फैल जाएगी। उन्होंने कहा कि वह संगीत में नयी तकनीक के इस्तेमाल के खिलाफ नहीं हैं और वास्तव में उन्होंने रजनीकांत अभिनीत फिल्म "लाल सलाम" के एक गीत 'थिमिरी येझुदा' के लिए दिवंगत गायकों बंबा बाक्या और शाहुल हमीद की आवाज के लिए एक एआई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया। रहमान ने कहा कि लेकिन उन्होंने संगीतकारों के परिवार से उचित अनुमति लेकर ऐसा किया। रहमान ने स्वीकार किया कि संगीत में एआई का उपयोग "बेतहाशा बढ़ गया है"। उन्होंने 'पीटीआई–भाषा' को दिए साक्षात्कार में कहा, "कुछ गीत बहुत खराब हैं, और उनमें लोकप्रिय गायकों की आवाज इस्तेमाल की गई है। इसे नियंत्रित करने की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अराजकता फैल जाएगी।" उन्होंने कहा कि एआई प्रौद्योगिकी के नैतिक उपयोग के लिए नियम होना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, "इसके अच्छे और बुरे दोनों पहलू हैं, और अच्छी चीजों का इस्तेमाल उन लोगों को सशक्त बनाने के लिए किया जाना चाहिए, जिन्हें कभी अपने विजन को अमल में लाने का मौका नहीं मिला। लेकिन इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करना हमारे लिए बुरा है। यह ऑक्सीजन में जहर मिलाने और उसे सांस के साथ अंदर लेने जैसा है।" उन्होंने कहा, "नियम होने चाहिए, जैसे कि कुछ चीजें आप नहीं कर सकते। जैसे, समाज में नैतिकता या व्यवहार के बारे में बात की जाती है, सॉफ्टवेयर और डिजिटल दुनिया में भी ऐसा होना चाहिए।"

कृतिका कामरा 'पीपली लाइव' की निर्देशक अनुषा रिजवी की अगली फिल्म में काम करेंगी

मुंबई, (भाषा) 'भीड़', 'बंबई मेरी जान', और 'ग्यारह ग्यारह' जैसी फिल्मों के लिए मशहूर अभिनेत्री कृतिका कामरा, 'पीपली लाइव' से मशहूर अनुषा रिजवी द्वारा निर्देशत एक आगामी महिला–प्रधान ड्रामा में मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। इस फिल्म का निर्माण जियो स्टूडियोज द्वारा किया जा रहा है और इसमे शीबा चड्ढा और श्रेया धनवंतरी भी काम करेंगी। फिल्म का शीर्षक अभी तय नहीं किया गया है। दिल्ली की जीवंत पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म एक मार्मिक मानवीय कहानी को उजागर करती है जो अपनी नायिकाओं की ताकत और दृढ़ता को दर्शाती है। जियो स्टूडियोज के एक प्रतिनिधि ने कहा कि वे इस फिल्म के लिए इतनी प्रतिभाशाली टीम को एक साथ लाने को लेकर उत्साहित हैं। प्रतिनिधि ने एक बयान में कहा, "कहानी प्रभावशाली और समय के अनुरूप है, और हमें विश्वास है कि यह दर्शकों पर गहरा असर करेगी।" फिल्म की शूटिंग अप्रैल के पहले सप्ताह में राजधानी में शुरू हो चुकी है।

छत्तीसगढ़ की 1460 ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल से शुरू होगी नकद भुगतान की सुविधा

रायपुर, (भाषा) छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की 1460 ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के अवसर पर नकद भुगतान की सुविधा सहित अन्य डिजिटल सेवाएं शुरू करने का फैसला किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि राज्य की 1460 ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के अवसर पर नकद भुगतान सहित अन्य डिजिटल सेवाएं शुरू की जाएंगी। उन्होंने बताया कि सोमवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में राज्य के प्रत्येक विकासखंड की 10–10 ग्राम पंचायतों में ''अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र'' के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया। अधिकारियों ने बताया कि इन सुविधा केंद्रों में ग्रामीणों को अब बहुत सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल सकेंगी। वे अपने खाते से आसानी से पैसे निकाल सकेंगे, अपने खाते से किसी अन्य के खाते में पैसे भेज सकेंगे, बिजली–पानी के बिल का भुगतान कर सकेंगे तथा पेंशन–बीमा जैसी कई सुविधाओं का लाभ अपने पंचायतों में ही ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि ''अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र'' के लिए ''कॉमन सर्विस सेंटर'' के सेवा प्रदाताओं और सरपंचों के बीच सोमवार को एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ। यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित किया गया। इन सुविधा केंद्रों के शुरू होने से ग्रामीणों को छोटे–छोटे कार्यों के लिए विकासखंड और जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। गांव में ही उन्हें बहुत–सी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री साय ने अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला मुख्यालयों में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 'गारंटी' की एक और 'गारंटी' को पूरा करने जा रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता से ग्राम पंचायतों में नकद भुगतान की सुविधा शुरू करने का वादा किया था, जो अब पूरा होने जा रहा है। साय ने कहा, ''हमने सवा साल में ही मोदी की गारंटी के अधिकतर वादों को पूरा किया है। चाहे किसानों के लिए 3100 रुपये में धान खरीदी हो या पिछले दो वर्षों का धान बोनस, महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना, बुजुर्गों के लिए रामलला दर्शन, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का पुनः प्रारंभ, या पांच लाख 62 हजार कृषि मजदूरों को सालाना 10 हजार रुपये देने का वादा।'' उन्होंने कहा, ''ग्राम पंचायतों में शुरू हो रहे इन सुविधा केंद्रों से किसान धान का भुगतान, महतारी वंदन योजना, पेंशन तथा अन्य योजनाओं की राशि का भुगतान ले सकेंगे, साथ ही जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य सुविधाओं का भी लाभ ले सकेंगे।''

आंध्र प्रदेश में सरकारी एवं निजी इंटरमीडिएट कॉलेज ने प्रभावशाली परिणाम दर्ज किये

अमरावती, (भाषा) आंध्र प्रदेश के मानव संसाधन विकास मंत्री नारा लोकेश द्वारा शुरू की गई पहलों के चलते राज्य के सरकारी और निजी, दोनों इंटरमीडिएट कॉलेजों ने शैक्षणिक वर्ष 2024–25 के लिए प्रभावशाली परिणाम दर्ज किए हैं। सरकार के करीबी सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि सरकारी जूनियर कॉलेज ने पिछले 10 वर्षों में अपना सर्वश्रेष्ठ इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम दर्ज किया है, जो इस परिवर्तनकारी परिणाम को प्राप्त करने के लिए केंद्रीकृत मूल्यांकन, शिक्षक प्रदर्शन निगरानी प्रणाली और नियमित अभिभावक–शिक्षक बैठकों की शुरुआत से संभव हुआ है। सूत्रों ने बताया कि सरकारी जूनियर कॉलेज में दूसरे वर्ष के छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत बढ़कर 69 प्रतिशत हो गया, जो एक दशक में सबसे अधिक है। सूत्रों ने बताया कि इसी तरह, 47 प्रतिशत छात्रों ने प्रथम वर्ष की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की, जो पिछले दशक का दूसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन है। सूत्रों ने बताया, ''सार्वजनिक और निजी संस्थानों में समग्र सफलता दर भी समान रूप से उच्च रही, जिसमें प्रथम वर्ष के 70 प्रतिशत छात्र और द्वितीय वर्ष के 83 प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए।'' लोकेश द्वारा शुरू किए गए सुधारों में सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यार्थी मित्र योजना के माध्यम से मुफ्त पाठ्यपुस्तकों और नोटबुक की पुनः शुरुआत और इंटरमीडिएट छात्रों के लिए डोक्का सीताम्मा मध्याह्न भोजन योजना शामिल है। पांच वर्ष के अंतराल के बाद 217 प्रिंसिपल की पदोन्नति, अक्टूबर 2024 से केंद्रीकृत मूल्यांकन की शुरुआत भी एक अन्य पहल है। लोकेश ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, ''शिक्षा के मोर्चे पर सुधारों वाले इस साल का परिणाम अविश्वसनीय रूप से संतोषजनक रहा है। इस बेहतरीन परिणाम के लिए मैं सभी छात्रों को बधाई देता हूं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए आगे और सुधार शुरू करेंगे कि हमारे छात्र इस उपलब्धि को बरकरार रखें और अगले साल अपने प्रदर्शन में और सुधार करें।'' इसके अलावा, लोकेश ने कहा कि वह पहले वर्ष में ही इतने प्रभावशाली प्रदर्शन से खुश हैं।

उत्तराखंड में देश की सबसे लंबी सुरंग के निर्माण की सफलता के गवाह बने वैष्णव

जनासू (उत्तराखंड), (भाषा) रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बुधवार को उत्तराखंड के जनासू में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग के निर्माण में मिली सफलता के गवाह बने। एक बोरिंग मशीन ने चट्टान की आखिरी परत को तोड़कर दूसरी तरफ निकलकर सफलता हासिल की, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ वैष्णव सुरंग में लगभग 3.5 किलोमीटर तक अंदर गए। देवप्रयाग और जनासू के बीच 14.57 किलोमीटर लंबी सुरंग संख्या–8 उत्तराखंड में महत्वाकांक्षी 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश–कर्णप्रयाग ब्रॉड गेज रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। वैष्णव ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया, क्योंकि यह सफलता 16 अप्रैल को मिली, जिस दिन 1853 में भारत में रेल सेवा शुरू हुई थी। पूरी परियोजना की देखरेख कर रहे रेल मंत्रालय के अधीन आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) ने जर्मनी में निर्मित 'शक्ति' नामक टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) का उपयोग करके यह सफलता हासिल की। सुरंग–8 दोहरी सुरंग है और दूसरी समानांतर सुरंग पर दूसरे टीबीएम की मदद से काम चल रहा है। जुलाई तक इसके दूसरे पार पहुंचने की उम्मीद है। इस सुरंग निर्माण का ठेका एलएंडटी कंपनी के पास है। आरवीएनएल की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, ''यह उल्लेखनीय उपलब्धि माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में हासिल की गई, जिन्होंने हिमालयी रेल संपर्क में इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने के अवसर पर स्थल का दौरा किया।''

हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने राज्य में वृद्धाश्रमों के निर्माण की सुस्त रफ्तार पर चिंता जताई

चंडीगढ़, (भाषा) हरियाणा मानवाधिकार आयोग (एचएचआरसी) ने राज्यभर में वृद्धाश्रमों के निर्माण की सुस्त रफ्तार पर गंभीर चिंता जताई है। आयोग ने 31 जनवरी 2025 के अपने आदेश के अनुपालन में की गई समीक्षा में पाया कि मौजूदा समय में केवल एक वृद्धाश्रम रेवाड़ी में चालू अवस्था में है, जिसका उद्घाटन लगभग दो साल पहले छह जनवरी 2023 को किया गया था। एचएचआरसी को एक अप्रैल को सौंपी गई वस्तुस्थिति रिपोर्ट के मुताबिक, पांच जिलों–झज्जर, पलवल, पानीपत, रोहतक और सिरसा में वृद्धाश्रम के निर्माण के लिए अभी तक भूमि की पहचान नहीं की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, गुरुग्राम, कैथल, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और नूंह जैसे जिलों ने जमीन चिह्नित कर ली है और निर्माण प्रक्रिया शुरू कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फरीदाबाद, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कुरुक्षेत्र, सोनीपत और यमुनानगर जैसे जिलों में निर्माण संबंधी मंजूरी न मिलने के कारण निर्माण कार्य अटका हुआ है। इसमें कहा गया है कि करनाल (स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत) और पंचकूला (माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की देखरेख में) में वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य जारी है। एचएचआरसी के प्रोटोकॉल–सह–सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी पुनीत अरोड़ा ने कहा, ''आयोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रेवाड़ी वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया और पाया कि 170 निवासियों के लिए बनाए गए इस आश्रय स्थल में केवल 12 वरिष्ठ नागरिक (नौ पुरुष और तीन महिलाएं) रह रहे थे।'' अरोड़ा ने बताया कि इसके अलावा, स्वच्छता की स्थिति भी चिंताजनक मिली, क्योंकि रसोई और शौचालय गंदी स्थिति में थे तथा साफ–सफाई के लिए केवल एक 'सफाई सेवक' तैनात था, जो इतने बड़े परिसर में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त था। एचएचआरसी अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा, न्यायिक सदस्य कुलदीप जैन और सदस्य दीप भाटिया की सदस्यता वाली पीठ ने अपने एक आदेश में हरियाणा में 'माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007' की धारा 19 लागू की थी, जिसके तहत प्रत्येक जिले में कम से कम एक वृद्धाश्रम होना अनिवार्य है। अरोड़ा ने कहा कि आयोग ने हाल ही में एक आदेश में इस बात की पुष्टि की कि बुजुर्गों के लिए सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य का संवैधानिक एवं नैतिक दायित्व है। उन्होंने बताया कि आयोग ने वरिष्ठ अधिकारियों को राज्यभर में वृद्धाश्रम के निर्माण की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने और उसमें तेजी लाने का भी निर्देश दिया। इन अधिकारियों में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) पंचकूला के मुख्य प्रशासक, विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक और नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक शामिल हैं। अरोड़ा के मुताबिक, आयोग ने संबंधित विभागों को 29 जुलाई तक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

लेप्चा बेंत पुल परंपरा को संरक्षित करने के लिए सिक्किम सरकार और यूनेस्को साथ आए

गंगटोक, (भाषा) सिक्किम सरकार और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने पारंपरिक लेप्चा बेंत पुल या 'रु–सोम' की कला को संरक्षित करने के लिए समझौता किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर राज्य के कंचनजंगा अभयारण्य के अंतर्गत दज़ोंगू जनजातीय रिजर्व में लेप्चा समुदाय अब भी इस पारंपरिक पुल का निर्माण करता है। यहां ताशीलिंग सचिवालय में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक के दौरान, यूनेस्को के क्षेत्रीय निदेशक टिम कर्टिस ने सहयोग की सराहना की तथा लेप्चा बेंत पुल कला के लिए वैश्विक मानकों के अनुरूप तकनीकी दस्तावेजीकरण और विरासत मान्यता दिलाने में सहयोग की पेशकश की। अधिकारियों ने बताया कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री पिंट्सो नामग्याल लेप्चा ने बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर विशेषज्ञ, कारीगर और सामुदायिक नेता जंगली बेंत और बांस जैसी पूरी तरह से प्राकृतिक सामग्री से तैयार 'रु–सोम' का प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हुए।

राज्यों के साथ साझेदारी में विकसित किए जाने वाले पर्यटन स्थलों की इस साल के अंत तक हो जाएगी पहचान

नयी दिल्ली, (भाषा) केंद्र सरकार देश के उन शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों के लिए दिशा–निर्देश तैयार करने पर काम कर रही है, जिन्हें राज्यों के साथ साझेदारी में विकसित करने का प्रस्ताव है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। पर्यटन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव सुमन बिल्ला ने यहां सम्मेलन में परिचर्चा के दौरान यह भी कहा कि राज्यों के साथ ''अनौपचारिक परामर्श'' शुरू हो गया है। एक फरवरी को केंद्रीय बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि देश के शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों के साथ साझेदारी में विकसित किया जाएगा। उन्होंने पर्यटन को रोजगारोन्मुखी विकास का वाहक बताया और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, कौशल विकास व यात्रा को आसान बनाने के उद्देश्य से कई पहलों की घोषणा की। बिल्ला और विभिन्न निजी होटलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक दिवसीय 'भारत यात्रा और पर्यटन स्थिरता सम्मेलन 2025' में 'द ट्रिपल बॉटम लाइन इन हॉस्पिटैलिटी– पीपुल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट' विषय पर एक परिचर्चा में भाग लिया। सम्मेलन का आयोजन 'मेकमाईट्रिप फाउंडेशन' और 'वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल इंडिया इनिशिएटिव' ने किया था। अतिरिक्त सचिव से पूछा गया कि क्या प्रस्तावित 50 गंतव्यों की पहचान कर ली गई है और क्या मंत्रालय ने राज्यों के साथ परामर्श शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, ''अनौपचारिक परामर्श शुरू हो गया है.. . हम दिशा–निर्देशों पर काम कर रहे हैं। और, पहले दिशा–निर्देश राज्यों को दिखाए जाएंगे। हमें उम्मीद है कि इस साल 50 गंतव्यों की पहचान कर ली जाएगी।''

अमरावती में 4,700 करोड़ रुपये की लागत से एकीकृत सचिवालय के निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित

अमरावती, (भाषा) आंध्र प्रदेश सरकार ने लगभग 4,700 करोड़ रुपये की लागत से पांच इमारतों वाले एकीकृत राज्य सचिवालय के निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं। आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा जारी निविदा अधिसूचना के अनुसार, सचिवालय में पांच इमारतें होंगी, जिनमें अमरावती में एकीकृत राज्य सचिवालय और विभाग प्रमुख कार्यालय (जीएडी टावर) शामिल होंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि परियोजना की कुल लागत 4,688.82 करोड़ रुपये आंकी गई है और तकनीकी बोलियां एक मई को खोली जाएंगी। इस बीच, आंध्र प्रदेश के नगर निकाय मंत्री पी. नारायण ने संवाददाताओं को बताया कि अमरावती में विभिन्न परियोजनाओं के लिए 41,000 करोड़ रुपये की निविदाएं पहले ही दी जा चुकी हैं और काम शुरू हो गया है।

उत्तर प्रदेश: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 18 अप्रैल से लखनऊ के तीन दिवसीय दौरे पर

लखनऊ, (भाषा) उत्तर प्रदेश के लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 18 अप्रैल को अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचेंगे और अपने तीन दिवसीय दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। एक पदाधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार रात पौने नौ बजे लखनऊ हवाई अड्डे पर उतरेंगे, जहां से वह सीधे 5ए कालिदास मार्ग अपने सरकारी आवास पर जाएंगे। उन्होंने बताया कि सिंह 19 अप्रैल यानी शनिवार को सुबह साढ़े नौ बजे के.डी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित 'सांसद खेल महाकुंभ' की शुरुआत करेंगे। द्विवेदी ने बताया कि इस कार्यक्रम के बाद वह पूर्वाह्न 11 बजे मुन्नू खेड़ा सदरौना रोड जाएंगे और पश्चिम मंडल3 के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री अगले दिन रविवार को पूर्वाह्न 11 बजे आईआईएम रोड स्थित महर्षि डिग्री कॉलेज पहुंचेंगे और वहां उत्तर मंडल4 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। महानगर अध्यक्ष ने बताया कि सिंह दोपहर सवा 12 बजे अलीगंज में डॉ. बिंदेश्वर पाठक की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे।

कहानी– 'अनुराग'

नैना आठ साल की थी । माता – पिता की चहेती थी । एक मिनट के लिए भी नैना को छोड़ना उनके लिए मुश्किल बन जाता था । नैना जो चाहती थी वही उसको मिल जाता था । क्या खिलौने क्या मिठाई , क्या कापी क्या किताब —— कुछ भी उसके लिए दुर्लभ न था । लेकिन एक दिन जब उसे पता चला कि उसके खेलने के लिए उसके माता–पिता एक नन्हा मेहमान लाने वाले हैं , तो उसका मन खुशी से खिल उठा , बिल्कुल कमल की भांति । वह इस बारे में रोज – रोज अपनी मां से पूछने लगी थी । एक आठ साल की बच्ची के सामने मानों जीने का सबसे बड़ा आधार उसके घर आने वाला उसका भाई या बहन ही था । उसने एक – एक कर ढेर सारे खिलौने व गुड़ियां खरीद लिए थे । बस अब वह अपनी कल्पना को साकार होते देखना चाहती थी । लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था । बहुत ही कठिन स्थिति सामने आ गई । एक सुंदर सलोना नन्हा मुन्ना घर तो आया लेकिन वह नेत्रहीन था । कुछ देख नहीं पाता था । दुख भरे दिन आगे बढ़ने लगे । तमाम चिकित्सकों को दिखलाया गया , मगर सबने यही कहा कि बच्चा नेत्रहीन है । अभी कुछ भी ज्यादा बताना मुश्किल है । माता – पिता ने तो जैसे तैसे परिस्थितियों से समझौता कर लिया था , मगर नैना अपने को मना न पाती थी कि उसका भाई कभी देख न पाएगा । कारण यह था कि वह नितांत भावुक प्रकृति की थी । कोमल मन की थी , बहुत ज्यादा सकारात्मक सोचने वाली थी । माता – पिता ने जब बच्चे का नामकरण किया तो उसका नाम त्रिनेत्री पड़ा । नैना चाहती थी कि त्रिनेत्री का जीवन सुधर जाए और वह नेत्रहीन होकर भी एक अच्छी जिंदगी का मालिक बन जाए । एक दिन घुटने घुटने चलता त्रिनेत्री दरवाजे तक पहुंच गया और सीढ़ियों से गिर गया, उसे सबने मिलकर उठाया और घर के अंदर ले आए । माता – पिता को बहुत दुख हुआ । आखिर कोई कब तक किसी को पकड़ कर रखेगा । फिर भी माता – पिता उसे अक्सर पलंग से बांध देते थे जिससे कि वह यहां – वहां न हो जाए । स्कूल से लौटकर नैना को पता चला कि त्रिनेत्री आज गिर गया । नैना को सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने त्रिनेत्री को गोद में उठा लिया और उसके साथ खेलने लगी । वह पढ़ती थी तो भी त्रिनेत्री को पास में बैठाकर । पाठ पढ़ती थी तो भी आवाज निकाल कर । इससे त्रिनेत्री बचपन से ही पाठ – कविता सब कुछ मुंह जुबानी सीखने लगा था । माता – पिता ने त्रिनेत्री को अब नेत्रहीनों की पाठशाला में डालना सही समझ लिया ताकि उसके जीवन का बोझ कम हो जाए । इससे नैना भी सहमत हो गई । जिस दिन त्रिनेत्री को पाठशाला भेजा गया उस दिन नैना को ऐसा लगा कि मानों किसी ने उसके दिल को कुरेद दिया हो , उसे खींचकर लहुलुहान कर दिया हो । तकिए में सर छुपाकर इतनी रोई कि जीवन भर का रोना भी कम पड़ जाए । लेकिन जिंदगी तो उसे जीनी ही थी । माता – पिता को भी कम कष्ट नहीं हुआ , बस वे नैना के आर्तनाद को बढ़ाना नहीं चाहते थे , इसलिए सीने पर पत्थर रख लिया । देखते–देखते समय बीतता गया और नैना ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली । स्कूल की शिक्षिका भी बन गई । मगर उसकी आंखों व दिल में त्रिनेत्री की छवि ही विद्यमान थी और वह उसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ पात्र था । और इधर त्रिनेत्री ने भी अपनी प्राथमिक पढ़ाई पूरी कर ली और ईश्वरीय योग था कि वह सुंदर – सुंदर कविताएं करने लगा , गीत रचने लगा । मोबाइल पर वह माता – पिता व बहन नैना को अक्सर सुनाया करता था । और उसने यह इच्छा भी जताई दी उच्च माध्यमिक शिक्षा के बाद घर लौटना चाहेगा । गीत लिखने का काम करेगा । अब सबके जीवन का ठहराव – सा जो बन गया था , उसमें थोड़ी सी गति आ गई थी । त्रिनेत्री घर आ गया था । अब वह काफी सुलझा हुआ था , मगर किसी पर निर्भर रहने की विवशता भी कम नहीं थी । यही वह समय था जब नैना ने अपनी आंखें त्रिनेत्री के नाम कर दी । और तो और अपने सारे अंग भी जरूरतमंदों के नाम कर दिया । और यह विधान भी था कि नैना का विवाह हो जाए । मन नहीं मानता था , मगर माता – पिता की इच्छा के आगे कुछ न कर पाई । त्रिनेत्री से विदा होते – होते उसमें न जाने कहां से जबर्दस्त ताकत आ गई थी । कई – कई लोगों ने पकड़कर उसे विदा किया । त्रिनेत्री के जीवन का भी यह सबसे दर्द भरा समय था । ससुराल जो मात्र किलोमीटर की दूरी पर था , वहां नैना के साथ अनहोनी हो गई । डॉक्टरों ने साइलेंट हार्ट अटैक बतलाया । नैना अब इस दुनिया में नहीं थी । एक ओर नैना की आंखों को त्रिनेत्री में लगाया जाना और दूसरी ओर नैना को अग्नि के सुपुर्द किया जाना , घर – परिवार , स्नेहियों व मित्रों के लिए बहुत व्यस्ततम समय था , व्यस्ततम दौर था । जब डॉक्टरों ने कहा कि त्रिनेत्री अब देख सकता है , साथ – साथ बातचीत भी कर सकता है । मगर सबसे पहले माता – पिता को ही सामने जाना चाहिए । लेकिन त्रिनेत्री का आर्तनाद कम नहीं था । उसने महसूस किया कि यह कैसी दुनिया है । कितनी अद्भुत व रंग – रंगीली दुनिया है । उसने इसकी कल्पना सपने में कभी नहीं की थी । यह उसका दुर्भाग्य है कि वह अपनी बहन नैना को नहीं देख पाया । जिसने उसे इतना कुछ दे दिया , वही छू – मंतर हो गई । लगातार ध्यान रखने वाली , अंतरात्मा से प्रेम रखने वाली , एक बड़ी बहन का प्रेम व समर्पण , स्नेह व आत्मिक संबंध हमेशा – हमेशा के लिए मानवता के इतिहास की कहानी बन गया ।

भारत की वायु गुणवत्ता डब्ल्यूएचओ मानकों से काफी पीछे, एलपीजी सब्सिडी योजना बढ़ाने की जरूरतः निदेशक

नयी दिल्ली, (भाषा) विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की एक अधिकारी ने कहा है कि भारत की वायु गुणवत्ता संयुक्त राष्ट्र के इस निकाय के मानकों से काफी कम है और देश की 40 प्रतिशत से अधिक आबादी अब भी बायोमास ईंधन पर निर्भर है, जिसके कारण हर साल लोगों की मौत होती है। 'पीटीआई वीडियो' के साथ एक विशेष साक्षात्कार में विश्व स्वास्थ्य संगठन में पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य विभाग की निदेशक डॉ. मारिया नीरा ने भारतीय अधिकारियों से मौजूदा कार्यक्रमों को, विशेष रूप से उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का आग्रह किया जो खाना पकाने के लिए बायोमास ईंधन के उपयोग से घरों के भीतर होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से हैं। नीरा ने 'पीटीआई–भाषा' से कहा, ''हमें एलपीजी और सब्सिडी तक पहुंच उपलब्ध कराने जैसे कार्यक्रमों पर विचार करने की जरूरत है, लेकिन निश्चित रूप से प्रयास न केवल जारी रखने होंगे, बल्कि इन प्रयासों को संभवतः बढ़ाना भी होगा।'' बायोमास ईंधन एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जिनमें पेड़ों की लकड़ी और पशु अपशिष्ट से बने उपले जैसे जैविक पदार्थ होते हैं। उन्होंने कहा, ''एक थिंक टैंक की रिपोर्ट के अनुसार, 41 प्रतिशत भारतीय परिवार अब भी बायोमास ईंधन पर निर्भर हैं, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु दर और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। हम भारत सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि वह घरों के भीतर के प्रदूषण से निपटने के लिए और अधिक उपाय करे क्योंकि इनके क्रियान्वयन के बाद अच्छे परिणाम सामने आए हैं।'' विश्व स्वास्थ्य संगठन की अधिकारी ने कहा कि आदर्श स्थिति यह होगी कि स्वच्छ ऊर्जा और नवीकरणीय गैर–प्रदूषक स्रोतों की ओर तुरंत कदम बढ़ाए जाएं, लेकिन नीति में निष्पक्षता होनी चाहिए। उन्होंने कहा, ''हम मानते हैं कि एक निष्पक्ष बदलाव होना चाहिए, खासकर उन सबसे कमजोर लोगों के लिए जो वर्तमान में प्रदूषणकारी स्रोतों का उपयोग कर रहे हैं। ऊर्जा के बेहतर स्रोतों के माध्यम से इस बदलाव में एलपीजी, बायोगैस, इथेनॉल तक पहुंच शामिल होगी, जो लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए बदलाव सुनिश्चित कर सकती हैं।''

नीरा ने कहा कि वायु प्रदूषण गैर–संचारी रोगों या एनसीडी का प्रमुख कारण है, जो सितम्बर में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव का विषय होगा। वायु गुणवत्ता मानकों के बीच अंतर के बारे में पूछे जाने पर, नीरा ने 'द लांसेट प्लेनेटरी हेल्थ' में प्रकाशित हाल के निष्कर्षों का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि खराब वायु गुणवत्ता केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश भर के सभी क्षेत्रों में है। उन्होंने कहा, ''एक अध्ययन से पता चलता है कि जब प्रदूषण की बात आती है तो हम हमेशा नयी दिल्ली पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन मुझे डर है कि लगभग पूरे भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों को लागू नहीं किया जाता है।''

उन्होंने कहा, ''वायु प्रदूषण भारत में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है और इस पर पहले से ही लागू कार्रवाई में तेजी लाने के लिए और अधिक राजनीतिक भागीदारी की आवश्यकता है।'' उन्होंने कहा कि देश में प्रदूषण से निपटने के लिए संसाधन, नवाचार और प्रौद्योगिकी मौजूद हैं। उन्होंने कहा, ''हमें पूरी उम्मीद है कि भारत इस स्थिति को पूरी तरह बदल सकता है और अन्य देशों के लिए एक उदाहरण भी स्थापित कर सकता है।'' डब्ल्यूएचओ के 'ग्रीन पेज' के बारे में बात करते हुए नीरा ने पर्यावरणीय स्वास्थ्य जोखिमों को पहचानने और उनका समाधान करने के लिए स्वास्थ्य पेशेवरों को शिक्षित और प्रशिक्षित करने के उनके प्रयासों पर प्रकाश डाला। हाल में डब्ल्यूएचओ सम्मेलन के दौरान लगभग 50 देशों और शहरों द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं के बारे में पूछे जाने पर, नीरा ने कहा कि डब्ल्यूएचओ ने प्रतिबद्धताओं की निगरानी के लिए तंत्र स्थापित किया है। उन्होंने कहा, ''जहां आवश्यक हो, हम संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, तथा यह देखना चाहते हैं कि क्षेत्रवार प्रतिबद्धताओं की निगरानी कैसे की जाए और फिर, निश्चित रूप से, 'ब्रीथ लाइफ', सी40 तथा अन्य तंत्रों के माध्यम से, हमारा लक्ष्य शहर स्तर पर निगरानी करना है।'' 'ब्रीथ लाइफ' अभियान विश्व स्वास्थ्य संगठन और जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन (सीसीएसी) के नेतृत्व में एक वैश्विक पहल है, जिसका उद्देश्य वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और स्वच्छ वायु के लिए कार्रवाई करने के वास्ते समुदायों को संगठित करना है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमरावती में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया

अमरावती (महाराष्ट्र), महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को राज्य के पूर्वी हिस्से अमरावती में एक हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। उन्होंने दावा किया कि इस हवाई अड्डे के निकट बनने वाला पायलट प्रशिक्षण स्कूल दक्षिण पूर्वी एशिया में इस तरह का सबसे बड़ा संस्थान होगा। फडणवीस ने हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद कहा कि पांच से छह महीने में बनने वाले इस स्कूल में हर साल करीब 180 पायलट तैयार होंगे और इसके पास प्रशिक्षण के लिए 34 विमान होंगे। इस अवसर पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, ''यहां बनने वाला पायलट प्रशिक्षण स्कूल दक्षिण पूर्वी एशिया का ऐसा सबसे बड़ा स्कूल होगा और नागपुर से करीब 150 किलोमीटर दूर स्थित इस शहर को विश्व मानचित्र पर स्थान दिलाएगा।'' उन्होंने कहा कि यह नरेन्द्र मोदी सरकार के कार्यकाल में शहर को मिला एक बड़ा उपहार है। फडणवीस ने कहा कि अमरावती में बनने वाले 'पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क' से लगभग दो लाख नौकरियां पैदा होंगी। उन्होंने यह भी कहा कि अमरावती संभाग में अकोला और यवतमाल स्थित मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार किया जा रहा है। इस अवसर पर नायडू ने कहा कि अमरावती हवाई अड्डा विदर्भ और महाराष्ट्र के लिए प्रगति के नए द्वार खोलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में मुंबई, पुणे, नागपुर और शिरडी हवाई अड्डों पर यात्रियों की संख्या में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि नयी मुंबई हवाई अड्डा भी जल्द ही शुरू हो जाएगा।

विजय शेखर शर्मा ने 1,800 रुपये के 2.1 करोड़ पेटीएम के शेयर लौटाए

नयी दिल्ली, (भाषा) वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी वन97 कम्युनिकेशन के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विजय शेखर शर्मा ने लगभग 1,800 करोड़ रुपये के 2.1 करोड़ शेयर स्वेच्छा से छोड़ दिए हैं। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में यह जानकारी दी। शेयरों को पेटीएम ब्रांड की मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस की सूचीबद्धता के समय ईएसओपी (कर्मचारी शेयर स्वामित्व योजना) के हिस्से के रूप में शर्मा को दिया गया था। अब ये शेयर वन97 के कर्मचारियों की शेयर विकल्प योजना, 2019 के तहत ईएसओपी पूल में लौट आएंगे। कंपनी ने कहा, "कंपनी के सीएमडी और सीईओ विजय शेखर शर्मा ने 16 अप्रैल, 2025 को दिनांकित पत्र में सूचित किया है कि उन्होंने स्वेच्छा से सभी 2,10,00,000 (2.1 करोड़) ईएसओपी को वन97 कम्युनिकेशन के कर्मचारी शेयर विकल्प योजना, 2019 के तहत लौटा दिए हैं।" पेटीएम शेयर के बंद भाव 864.5 रुपये के आधार पर, ईएसओपी का मूल्य 1,815.45 करोड़ रुपये है।

भारतीय सिख तीर्थयात्रियों ने करतारपुर गुरुद्वारे के खेतों में गेहूं की कटाई शुरू की

लाहौर, (भाषा) भारतीय सिख तीर्थयात्रियों ने बुधवार को करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब के खेतों में गेहूं की फसलों की कटाई की वार्षिक परंपरा शुरू की। गुरु नानक देव ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष यहीं बिताए थे। 'परियोजना प्रबंधन इकाई करतारपुर' के तहत बैसाखी उत्सव में भाग लेने के लिए 6,000 से अधिक भारतीय सिख वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हैं। परियोजना प्रबंधन इकाई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सैफुल्लाह खोखर और 'इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड' (ईटीपीबी) के अन्य अधिकारियों के साथ सिख तीर्थयात्रियों ने विशाल खेतों में फसलों की कटाई की। तीर्थयात्रियों ने काम करते समय 'जो बोले सो निहाल' का जयकारा लगाते हुए भूमि के साथ अपने आध्यात्मिक जुड़ाव और खुशी को व्यक्त किया। यह आयोजन बैसाखी के उत्सव के साथ हुआ और सिख तीर्थयात्रियों ने अपने ऐतिहासिक गुरुद्वारों की अच्छी देखभाल करने और उन्हें गुरु नानक देव के खेतों की जुताई करने की अनुमति देने के लिए सरकार के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने बैसाखी समारोह और खालसा जयंती के लिए किए गए गर्मजोशी भरे आतिथ्य और उत्कृष्ट व्यवस्थाओं के लिए भी सरकार की प्रशंसा की। खोखर ने कहा, ''गुरु नानक देव की फसलों की कटाई एक ऐतिहासिक क्षण था, जो सिख धर्म की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को दर्शाता है। इस कार्यक्रम ने सिख धर्म में कृषि, सामुदायिक सेवा और भक्ति के महत्व को दर्शाया, जिसने सिख तीर्थयात्रियों पर एक अमिट छाप छोड़ी।'' बैसाखी समारोह के हिस्से के रूप में 'परियोजना प्रबंधन इकाई करतारपुर' और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा कबड्डी मैच का आयोजन किया गया। सिख तीर्थयात्रियों ने भांगड़ा सहित पारंपरिक पंजाबी नृत्य का आनंद लिया और अपनी खुशी और कृतज्ञता व्यक्त की। बैसाखी सिख नववर्ष का प्रतीक है और 1699 में गुरु गोबिंद सिंह के नेतृत्व में खालसा पंथ के गठन की याद दिलाता है। ईटीपीबी के अनुसार, गुरु नानक देव की जन्मस्थली पर खालसा की 326वीं जयंती पर आयोजित समारोह में शामिल होने वाले सिखों में करीब 10,000 विदेशी सिख श्रद्धालु भी शामिल हुए।

भारत 2026 में हवाई यात्री वृद्धि दर में चीन को पीछे छोड़ देगा : एसीआई

नयी दिल्ली, (भाषा) हवाई अड्डों के समूह एयरपोर्ट्स इंटरनेशनल काउंसिल (एसीआई) ने बुधवार को कहा कि भारत 2026 में हवाई यात्रियों की संख्या में वृद्धि दर के मामले में चीन को पीछे छोड़ सकता है। दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते नागर विमानन बाजारों में से एक, भारत की हवाई यात्री वृद्धि दर इस वर्ष 10.1 प्रतिशत है, जो चीन के लिए 12 प्रतिशत से कम है। पड़ोसी राष्ट्र में भारत की तुलना में बहुत बड़ा विमानन बाजार है। एसीआई एशिया–प्रशांत और पश्चिम एशिया के महानिदेशक स्टेफैनो बैरोंकी ने कहा कि भारत एक ऐसा बाजार है जो विकसित हो रहा है और अपने बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की प्रक्रिया में है। एसीआई एशिया प्रशांत और पश्चिम एशिया, इस क्षेत्र में 600 से अधिक हवाई अड्डों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अनुमान के अनुसार, भारत की हवाई यात्री वृद्धि दर 2026 में 10.5 प्रतिशत और 2027 में 10.3 प्रतिशत होगी, जबकि चीन क्रमशः 8.9 प्रतिशत और 7.2 प्रतिशत पर होगा। वर्ष 2023–27 के लिए भारत में हवाई यात्रियों की संख्या के लिए सालाना वृद्धि दर (सीएजीआर) का अनुमान 9.5 प्रतिशत है, जो एसीआई के अनुसार चीन के लिए 8.8 प्रतिशत से अधिक है। भारत भी 2023–2053 की अवधि के लिए विश्वस्तर पर सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार होगा।

ईरान, अमेरिका के बीच दूसरे दौर की परमाणु वार्ता रोम में होगी : ईरान का सरकारी टेलीविजन

दुबई, ईरान के सरकारी टेलीविजन ने बुधवार को पुष्टि की कि ईरान–अमेरिका परमाणु वार्ता का दूसरा दौर रोम में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले इस बात पर भ्रम था कि वार्ता कहां होगी। सरकारी टीवी चैनल की खबर में कहा गया है कि वार्ता की मध्यस्थता ओमान द्वारा की जाएगी। पिछले सप्ताहांत ओमान की राजधानी मस्कट में पहले दौर की वार्ता हुई थी। सोमवार को कई अधिकारियों ने कहा कि वार्ता रोम में होगी। हालांकि, मंगलवार की सुबह ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ओमान में वार्ता आयोजित होगी।

पतंजलि, पांच अन्य इकाइयों को मैग्मा जनरल इंश्योरेंस के अधिग्रहण की मंजूरी

PATANJALI

नयी दिल्ली, (भाषा) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने पतंजलि आयुर्वेद और पांच अन्य इकाइयों के मैग्मा जनरल इंश्योरेंस में बहुलांश हिस्सेदारी हासिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आयोग ने एक नोटिस में कहा, ''प्रस्तावित अधिग्रहण को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा छह (चार) के अंतर्गत 'ग्रीन चैनल रूट' के तहत अधिसूचित किया जा रहा है।'' 'ग्रीन चैनल रूट' के तहत, ऐसा लेनदेन आता है, जिससे प्रतिस्पर्धा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का जोखिम न हो। मामले को प्रतिस्पर्धा नियामक को सूचित किए जाने पर उसे स्वीकृत माना जाता है। पतंजलि आयुर्वेद के अलावा, लेनदेन में भाग लेने वाली इकाइयां एसआर फाउंडेशन, रीति फाउंडेशन, आरआर फाउंडेशन, सुरुचि फाउंडेशन और स्वाति फाउंडेशन हैं। सीसीआई को दी गयी सूचना के अनुसार, ''अधिग्रहण करने वाली इकाइयों का शेयर खरीद के माध्यम से मैग्मा जनरल इंश्योरेंस लि. में 98.055 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने का प्रस्ताव है।'' आयोग की मंजूरी के बाद, बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद लि. मैग्मा जनरल इंश्योरेंस की प्रवर्तक इकाई होगी। इससे पतंजलि के कारोबार में विविधता आएगी, जो वर्तमान में स्वास्थ्य और दैनिक उपयोग के सामान के कारोबार से जुड़ी है।

शुल्क छूट की तीन माह की अवधि से पहले निर्यात खेप अमेरिका भेजने में जुटे निर्यातक

नयी दिल्ली, (भाषा) अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुल्क के कार्यान्वयन को 90 दिन के लिए टाले जाने के बीच उसका लाभ उठाने के मकसद से निर्यातक तय समय से पहले ही वस्तुओं को अमेरिका भेजने में जुट गये हैं। मुख्य रूप से रत्न एवं आभूषण, जूते और परिधान जैसे कुछ क्षेत्रों के निर्यातकों ने अमेरिका को तय समय से पहले ही सामान भेजना शुरू कर दिया है। निर्यातकों ने कहा कि चूंकि अमेरिकी शुल्क को आगे टाले जाने के बारे में अनिश्चितता है, ऐसे समय में अधिक माल भेजना बेहतर है, जब शुल्क कम हैं। उन्होंने कहा कि चीनी वस्तुओं पर अमेरिका के 245 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने के बाद खालीपन को भरने के लिए भारतीय कंपनियों को उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि करने की आवश्यकता है। निर्यातकों के शीर्ष निकाय फियो के अध्यक्ष एस सी रल्हन ने कहा, ''सरकार को इस स्थिति में उन क्षेत्रों में विनिर्माताओं का समर्थन करने के लिए तुरंत आगे आना चाहिए, जिनमें उच्च निर्यात क्षमता है। कुछ क्षेत्रों के निर्यातक शुल्क कार्यान्वयन में छूट की अवधि का लाभ उठाने के लिए सामान तेजी से भेज रहे हैं।'' अमेरिका को चीन के मुख्य निर्यात में इलेक्ट्रॉनिक सामान, कंप्यूटर, मशीन कलपुर्जे, इलेक्ट्रिक बैटरी, हीटर, खिलौने, फर्नीचर, कपड़े और जूते शामिल हैं। रल्हन ने कहा, ''उच्च शुल्क लगाए जाने के कारण हमारे लिए निर्यात की काफी संभावनाएं हैं और हमारे निर्यातकों को इसका लाभ उठाने पर विचार करना चाहिए।'' उन्होंने कहा कि निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, उत्पादों और बाजारों में विविधता लाने तथा लॉजिस्टिक और बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने के लिए उपायों की आवश्यकता है। रल्हन ने विनियामक बोझ को कम करने और सस्ते कर्ज तक पहुंच बेहतर बनाने का भी सुझाव दिया। अमेरिका ने भारत पर 26 प्रतिशत अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने की घोषणा की थी। बाद में नौ अप्रैल को इसे नौ जुलाई तक 90 दिन के लिए टाले जाने की घोषणा की। चमड़ा क्षेत्र के एक निर्यातक ने कहा कि कुछ व्यापारी इस अवधि का लाभ उठाने के लिए जल्दी–जल्दी माल भेज रहे हैं। प्रमुख चमड़ा उत्पाद विनिर्माता और निर्यातक फरीदा समूह के अध्यक्ष रफीक अहमद ने कहा, ''फुटवियर क्षेत्र स्थिति का आकलन कर रहा है। यह पूरी तरह से असमंजस की स्थिति है। हम प्रतीक्षा करेंगे और देखेंगे और फिर निर्णय लेंगे।'' हालांकि, घरेलू उद्योग चीन से भारत में माल की डंपिंग की आशंका को लेकर चिंतित है। सरकार ने आयात बढ़ने पर नजर रखने को एक अंतर–मंत्रालयी निगरानी समूह का गठन किया है। चीन और वियतनाम जैसे कुछ देशों पर उच्च शुल्क के कारण भारत में वस्तुओं की डंपिंग किये जाने की आशंका है।

रिजर्व बैंक ने अहमदाबाद के कलर मर्चेंट्स को–ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया

मुंबई, (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को कहा कि उसने अहमदाबाद स्थित 'कलर मर्चेंट्स को–ऑपरेटिव बैंक' का लाइसेंस रद्द कर दिया है क्योंकि उसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बयान में कहा कि गुजरात सहकारी समितियों के पंजीयक को भी बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से केवल पांच लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमा राशि पर बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। रिजर्व बैंक ने आगे कहा कि सहकारी बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, लगभग 98.51 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। 31 मार्च, 2024 तक, डीआईसीजीसी ने बैंक के जमाकर्ताओं को 13.94 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है। लाइसेंस रद्द करने के पीछे कारण बताते हुए रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। सहकारी बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत कुछ आवश्यकताओं का पालन करने में भी विफल रहा है। रिजर्व बैंक ने कहा, ''बैंक का जारी रहना जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है। अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ बैंक अपने जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा।'' रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि यदि बैंक को अपना बैंकिंग कारोबार आगे भी जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो इससे जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लाइसेंस रद्द होने के बाद, सहकारी बैंक बुधवार (16 अप्रैल, 2025) को कारोबार बंद होने से बैंकिंग व्यवसाय कारोबार बंद कर देगा। बैंकिंग कारोबार में अन्य चीजों के अलावा जमा स्वीकार करना और जमा का पुनर्भुगतान शामिल है।

ओडिशा में आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई–जीजेएवाई का लाभार्थी सत्यापन करेगी बीएलएस

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
आयुष्मान भारत
PM-JAY

नयी दिल्ली, (भाषा) प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं देने वाली बीएलएस ई–सर्विसेज को ओडिशा में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना–गोपबंधु जन आरोग्य योजना (एबी पीएमजेएवाई–जीजेएवाई) के लाभार्थियों का सत्यापन करने के लिए लिए प्रदेश सरकार से जिम्मेदारी मिली है। कंपनी ने बुधवार को एक बयान में यह जानकारी दी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के सहयोग से शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य राज्य भर में 3.5 करोड़ लाभार्थियों को पीवीसी सह–ब्रांडेड एबी–पीएमजेएवाई–जीजेएवाई कार्ड वितरित करना है। बीएलएस ई–सर्विसेज, बीएलएस इंटरनेशनल की इकाई है। इस आदेश के तहत बीएलएस एबी पीएमजेएवाई–जीआईएवाई कार्ड के लंबित होने के मामलों को दूर करने के लिए एनएचए दिशानिर्देशों और राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार काम करेगी। बीएलएस इंटरनेशनल के संयुक्त प्रबंध निदेशक और बीएलएस ई–सर्विसेज के चेयरमैन शिखर अग्रवाल ने कहा, "ओडिशा सरकार द्वारा हमें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपे जाने पर हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं। एबी–पीएमजेएवाई–जीजेएवाई योजना ओडिशा के लोगों के लिए एक बड़ा बदलाव लाने वाली है, जो उन्हें बिना किसी वित्तीय कठिनाई के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। उन्होंने कहा, ''हम निर्बाध लाभार्थी सत्यापन सेवाएं और एबी–पीएमजेएवाई–जीजेएवाई कार्ड का समय पर वितरण सुनिश्चित करेंगे।"

भारतीय मूल की डॉ. मुमताज 'रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन' की अध्यक्ष चुनी गईं

लंदन, (भाषा) भारतीय मूल की डॉ. मुमताज पटेल 'रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन' (आरसीपी) की 123वीं अध्यक्ष चुनी गई हैं। आरसीपी दुनियाभर के 40,000 से अधिक चिकित्सा पेशेवरों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्रमुख स्वास्थ्य निकाय है, जिसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में की गई थी। उत्तर–पश्चिमी इंग्लैंड के लंकाशायर में एक प्रवासी भारतीय दंपति के घर जन्मी डॉ. मुमताज मैनचेस्टर के शीर्ष किडनी रोग विशेषज्ञों में शुमार हैं। आरसीपी ने निकाय की "पहली भारतीय–एशियाई मुस्लिम अध्यक्ष" और "पांचवीं महिला अध्यक्ष" के रूप में डॉ. मुमताज का स्वागत किया। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मतदान सोमवार को संपन्न हुआ और उनके चार साल के कार्यकाल के आधिकारिक शुरुआत की तारीख की अभी पुष्टि नहीं हो सकी है। डॉ. मुमताज ने कहा, "अध्यक्ष के रूप में, मैं आरसीपी को सर्वोत्तम संगठन बनाने की कोशिश करूंगी। मैं इसके प्रत्येक सदस्य का करियर के हर चरण में समर्थन करूंगी, ताकि हमारे मरीजों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जा सके।" उन्होंने कहा, "मैं पूरे जुनून, प्रतिबद्धता, दूरदर्शिता और मूल्य आधारित दृष्टिकोण से इस भूमिका को निभाऊंगी और आरसीपी की सदस्य के तौर पर 20 साल से अधिक का मेरा अनुभव इसमें मेरी मदद करेगा।" डॉ. मुमताज जून 2024 से आरसीपी की वरिष्ठ सेंसर और शिक्षा एवं प्रशिक्षण मामलों की उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थीं। वह निकाय की कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी सेवाएं दे रही थीं। अध्यक्ष के रूप में वह आरसीपी परिषद की अध्यक्षता करेंगी और न्यासी बोर्ड की सदस्य बनेंगी। आरसीपी के न्यासी बोर्ड की अध्यक्ष डॉ. डायना वालफोर्ड ने कहा, "डॉ. मुमताज ऐसे समय में यह पद संभालेंगी, जब कॉलेज चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। मुझे ईमानदारी के साथ नेतृत्व करने, हमारे सदस्यों में फिर से विश्वास जगाने और इस प्रतिष्ठित कॉलेज का आकर्षण बहाल करने की उनकी क्षमता पर पूरा भरोसा है।"

Government accords high priority for Muslims' Haj pilgrimage

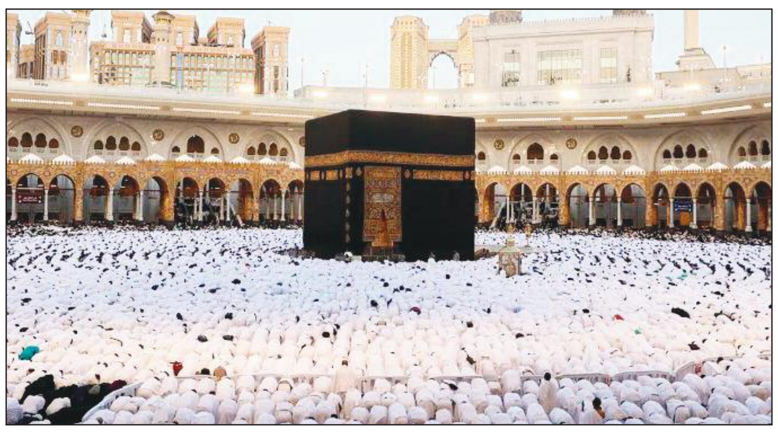

New Delhi, Focus News: The Government of India accords high priority for Indian Muslims to undertake the annual Haj pilgrimage. As a result of its efforts, the country allocation for India which was 136,020 in 2014 has gradually increased to 175,025 in 2025. These quotas are finalized by the Saudi authorities closer to the time of the pilgrimage. The Ministry of Minority Affairs (MoMA) through the Haj Committee of India manages arrangements for the bulk of the quota allotted to India, which is 122,518 in the current year. All the necessary arrangements including flight schedules, transportation, Mina camps, accommodation, and additional services have been taken up and completed as per the Saudi requirements, within the given timelines. The balance of the quota was allotted, as is customary, to Private Tour Operators. Due to changes in Saudi guidelines, more than 800 Private Tour Operators were consolidated into 26 legal entities termed Combined Haj Group Operators (CHGOs), by MoMA this year. Addressing legal challenges, the Haj quota was allocated by MoMA to these 26 CHGOs well in advance. However, despite reminders, they failed to comply with the necessary timelines set by the Saudi authorities and failed to finalise the mandatory contracts, including for Mina camps, accommodation and transport of pilgrims, as required under the Saudi regulations. Government of India has been continuously engaging on this matter with the concerned Saudi authorities, including at the Ministerial level. The Saudi Haj Ministry highlighted its concerns for the safety of the pilgrims, particularly in Mina, where Haj rituals have to be completed under extreme summer heat conditions in a limited space. It also underlined that due to delays, the available space in Mina became occupied. The Saudi authorities have further conveyed that they were not extending the timelines for any country this year. Due to the Government's intervention, the Saudi Haj Ministry has agreed to re-open the Haj Portal (Nusuk Portal) to all CHGOs to complete their work in respect of 10,000 pilgrims based on the current space availability in Mina. Directions have been issued by MoMA to CHGOs to do so urgently. India would naturally appreciate any gesture by Saudi authorities to accommodate more pilgrims.

Centre for Joint Warfare Studies Hosts Defence Literature Festival 'Kalam & Kavach 2.0' in New Delhi

New Delhi, Focus News: The Centre for Joint Warfare Studies (CENJOWS), under the aegis of Headquarters Integrated Defence Staff (HQ IDS), Ministry of Defence, in collaboration with Pentagon Press, successfully hosted the second edition of the Defence Literature Festival 'Kalam & Kavach 2.0' at Manekshaw Centre in New Delhi. This year's theme was 'Securing India's Rise through Defence Reforms'. The event, held on April 15, 2025, focused on Defence Technology and Future Warfare, particularly in the context of defence manufacturing. It was aligned with the Prime Minister's call for 'Aatmanirbhar Bharat' (Self-reliant India) and highlighted key aspects of acquisition & procurement reforms. The event brought together distinguished experts from the Armed Forces, strategic policymakers, industry leaders, and domain specialists to deliberate on critical issues affecting India's national security. Discussions included several cutting-edge topics including Technology & Future Warfare; the role of AI, cyber technologies, quantum computing, drones, space technology, and semiconductors in modern military operations; Defence Manufacturing & Aatmanirbharta, Acquisition & Procurement Reforms.

The event focused on charting a strategic roadmap for its national security, diplomacy and development. It also covered the progress made on adoption of niche technologies, enhancing multi-domain and cross-domain operational capabilities to include land, air, sea, cyber and space. The agenda also included contemporary maritime security paradigms, future challenges and the way ahead to further the combat capability. Raksha Mantri Shri Rajnath Singh declared 2025 as the 'Year of Reforms,' marking a transformational year aimed at converting the Armed Forces into a technologically-advanced, combat-ready force. This vision underscores the nation's commitment to multi-domain, integrated operations and emphasises a mission-mode approach to defence reforms, facilitating technology transfer, and improving public-private partnerships.

Dr. Jitendra Singh, Minister of Science and Technology Reviews CSIR Activities; Lauds Breakthroughs under NMITLI Programme

New Delhi, Focus News: As a major breakthrough in shipping transport and inland waterway transport, Union Minister of Science & Technology and Vice President CSIR (Council of Scientific & Industrial Research) Dr Jitendra Singh has hailed India's first indigenously developed hydrogen fuel sea vessel. Describing it as a success story emanating from the joint effort of public and private sectors, the Minister disclosed that the country's first indigenous green hydrogen fuel cell inland waterway vessel, which may later pave the way for hydrogen fuel driven larger sea vessels or ships, was developed by Cochin Shipyard Ltd featuring a hydrogen fuel cell-based drivetrain built by KPIT, drawing upon the foundational work enabled by the CSIR. Dr. Jitendra Singh was convening a high-level meeting today to review the ongoing initiatives and achievements of the Council of Scientific and Industrial Research (CSIR). The meeting was attended by all Heads of CSIR Directorates, the Joint Secretary and Financial Adviser, CSIR. Director General, CSIR, Dr. N. Kalaiselvi presented a detailed overview of CSIR's current research activities, recent technological advancements, and collaborative engagements with industry. During the discussions, the Minister emphasized the importance of aligning CSIR's scientific pursuits with the vision of Prime Minister Shri Narendra Modi for a Atma Nirbhar, especially in critical technology domains where indigenous development is key. The Minister lauded the CSIR-New Millennium Indian Technology Leadership Initiative (NMITLI), calling it a unique example of collaborative innovation in the public-private space. As India's largest publicly funded, industry-oriented R&D programme, NMITLI brings together top institutions, industrial partners, and research labs to pursue high-risk technological ventures with the potential for national impact. Bhopal, and M/s TechnoS Instruments, Jaipur.

These high-end Raman spectrometers, approved for marketing in January 2022, represent a significant milestone in India's scientific instrumentation capabilities. Eleven units of indigenous Raman Spectrometers have been supplied across the country to date, demonstrating growing national adoption of this indigenous technology. The second highlighted success, Dr Jitendra Singh noted, was the development of fuel cell technology under the Industry-Originated NMITLI programme. In this initiative, KPIT collaborated with CSIR-National Chemical Laboratory (CSIR-NCL) Pune and CSIR-Central Electrochemical Research Institute (CSIR-CECRI) to develop and demonstrate low-temperature PEM fuel cell systems. The expertise developed through this collaboration has since been translated into applications for the marine, defence, and automotive sectors. A major outcome of this effort was the launch of the country's first indigenous green hydrogen fuel cell inland waterway vessel by Prime Minister Narendra Modi at Thoothukudi, Tamil Nadu, under the Harit Nauka initiative. The vessel, developed by Cochin Shipyard Ltd., features a hydrogen fuel cell-based drivetrain built by KPIT, drawing upon the foundational work enabled by CSIR. Dr. Jitendra Singh underscored that these achievements exemplify the role of CSIR in driving technology-led growth and contributing to India's self-reliance in frontier areas.

Startup selected under NQM launches one of India's most powerful quantum computers

New Delhi, Focus News: Bangaluru based QpiAI, one of the 8 startups selected under the National Quantum Mission, coordinated by the Department of Science and Technology (DST) announced the launch of one of India's most powerful quantum computers featuring 25 superconducting qubits, on the occasion of World Quantum Day yesterday. QpiAI-Indus, the quantum computer launched, is the first full-stack quantum computing system in the country and combines advanced quantum hardware, scalable control, and optimized software for transformative hybrid computing. It integrates advanced quantum processors, next-generation Quantum-HPC software platforms, and AI-enhanced quantum solutions. With this milestone, QpiAI is driving deep-science and deep-tech innovation across life sciences, drug discovery, materials sciences, mobility, logistics, sustainability, and climate action. As a part of India's National Quantum Mission, QpiAI is at the forefront of building the country's quantum computing technology ecosystem, national quantum adoption programs, and creating one of the world's largest quantum talent ecosystems. QpiAI is committed to accelerating India's quantum journey, making quantum computing technologies practical, accessible, and globally impactful. The technologies from the company, bootstrapped in 2019, have led to 11 patent applications and generated a revenue of around Rs 1 million per annum. They have also generated substantial capital from the Small Industries Development Bank of India (SIDBI). With this announcement on World Quantum Day which marks a shared vision for a quantum-enabled future that transforms industries, accelerates scientific discovery, and empowers the next generation of innovators, QpiAI joins the global community of scientists, engineers, policy makers, and enthusiasts in celebrating the remarkable progress and possibilities unlocked by quantum science and technology.

NADA India Hosts National Conference on 'Building Together a Clean Sport Ecosystem'

New Delhi, Focus News: The National Anti-Doping Agency (NADA) India successfully organized a conference on "Building Together a Clean Sport Ecosystem" today at the India International Centre (IIC), New Delhi. The event, held as part of Play True Week 2025, brought together a wide spectrum of stakeholders committed to fostering a clean, fair, and values-based sporting environment in India. In the inaugural session, Secretary, Department of Sports, Smt. Sujata Chaturvedi emphasised that as India is bidding to host the 2036 Summer Olympics, we must anchor our sporting ambition with a robust anti-doping system to ensure fairness, integrity, and commitment to clean sport. Dr. Mayumi Yaya Yamamoto, Director, Asia/Oceania Office, World Anti-Doping Agency (WADA) commended NADA India's and national stakeholders' efforts in this year's global Play True Campaign. She underscored the importance of the 'It Starts With Me' campaign and highlighted the shared responsibility and unity required to build a clean sport ecosystem together. One of the key moments of the inaugural session was the unveiling of "NADA India's Fair Play Guide" in ten different regional languages, aimed at making clean sport education more accessible to athletes and stakeholders across the nation. Participants also engaged in a pledge signing ceremony to reaffirm their commitment to fair play and doping-free sport. The conference featured engaging panel discussions on critical themes including anti-doping policy, enhancing education and testing, and increasing awareness about athlete rights & responsibilities, particularly in the context of Therapeutic Use Exemptions (TUEs). Experts from national sports federations, medical institutions, and international organizations shared practical insights and actionable strategies to strengthen India's anti-doping system. A group of people sitting in a roomAI-generated content may be incorrect. The event witnessed participation from sport administrators, athletes, coaches, educators, and medical experts, and created a space for collaboration, idea exchange, and future-oriented planning.

Savitri Thakur inspects key initiatives in East Khasi Hills District

New Delhi, Focus News: The Minister of State, Ministry of Women and Child Development, Government of India, Smt. Savitri Thakur, on her second day of her visit to Meghalaya conducted an official visit to East Khasi Hills District on April 16, 2025, to review the implementation of flagship schemes and engage with grassroots stakeholders. As part of the visit, the Minister inspected the One Stop Centre, Shakti Sadan, in Mawroh. Eighteen residents, aged between 18 and 50 years, are currently housed at the facility and are participating in vocational training programs. The Minister interacted with the inmates and encouraged their efforts toward empowerment and rehabilitation. The Minister also visited the Child Care Institution at Mawkasiang, where she engaged with staff, children, and caregivers. She commended the institution's work in ensuring child protection and care and emphasized the need for continued psychosocial support and quality education for children in need of care and protection. At the Anganwadi Centre in Mawsmai, the Minister reviewed services provided under the Integrated Child Development Services (ICDS) scheme, including nutrition, preschool education, and health check-ups. She praised the dedication of Anganwadi Workers and Helpers and encouraged sustained community participation in child welfare programs. During her visit to the Community Health Centre (CHC) in Sohra, the Minister assessed maternal and child health services, the availability of essential medicines, and the integration of health and nutrition schemes. She reaffirmed the Government's commitment to improving healthcare access for women and children, especially in remote and tribal areas. The visit also included an inspection of rural development projects under MGNREGS and PMAY-G. The Minister interacted with beneficiaries and reviewed the progress and impact of these initiatives. She appreciated the inter-departmental coordination contributing to enhanced rural livelihoods and infrastructure. The Minister concluded her visit by commending the District Administration and local stakeholders for their dedicated efforts in strengthening institutional care, nutrition, and the overall empowerment of women and children in Meghalaya.

In a first, ECI trains Booth Level Agents (BLAs) to strengthen grassroot participation by political parties

New Delhi, Focus News: The Election Commission of India (ECI) has commenced the training of Booth Level Agents (BLAs) from Bihar in view of the forthcoming elections in the State. Around 280 BLAs from the State associated with 10 recognised political parties are taking part in the 2-day training programme being organised at the India International Institute for Democracy and Election Management, IIIDEM, New Delhi. Chief Election Commissioner Shri Gyanesh Kumar along with Election Commissioners Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Dr. Vivek Joshi addressed the BLAs in a first of its kind training programme. The training was conceptualised during the Chief Electoral Officers (CEO) conference held on the 4th of March, 2025.

Defence Secretary calls on Italian Defence Minister in Rome to further enhance bilateral defence cooperation

New Delhi, Focus News: Defence Secretary Shri Rajesh Kumar Singh visited Rome, Italy from April 14-15, 2025 on an official trip. The visit started with the Defence Secretary calling on the Defence Minister of Italy Mr Guido Crosetto. During the meeting, the two sides held productive discussions aimed at further enhancing defence cooperation as a key pillar of India-Italy strategic partnership. During his visit, Shri Rajesh Kumar Singh co-chaired the 11th India-Italy annual bilateral Joint Defence Committee meeting with his Italian counterpart, Secretary General of Defence Ms Luisa Riccardi. They discussed a wide range of defence, security and industrial cooperation issues including maritime cooperation and information sharing arrangements between India and Italy with emphasis on Trans Regional Maritime Network. The situation in the Red Sea and Western Indian Ocean Region also came up during the discussions. The Defence Secretary stressed on closer defence collaboration especially in technology and armament production, which is a priority area for India. He also brought out that the Government of India is proactively building an ecosystem for defence production and innovation within the country through conscious policy initiatives. India has developed a vibrant innovation and industrial ecosystem.

In his keynote address during India-Italy Defence Industry Roundtable, Shri Rajesh Kumar Singh shared his views on how the Indian defence industry has witnessed significant changes, particularly in the past few years through progressive reforms. He said that these reforms have been marked by the creation of a conducive environment for the growth of the Indian Industry through transparency, predictability and Ease of Doing Business. An MoU between Society of Indian Defence Manufacturers (SIDM) and the Federation of Italian Companies for Aerospace, Defence and Security (AIAD) was also signed, marking a significant step toward fostering closer cooperation between the defence industries of both nations. The Defence Secretary was accompanied by a high-level Ministry of Defence delegation, comprising senior officials from Service Headquarters, Department of Defence and Department of Defence Production. A substantial industry delegation from SIDM also accompanied the Defence Secretary to foster closer B2B connections between the Indian and Italian defence industries.

CCI imposes monetary and non-monetary sanctions on UFO Moviez India Pvt. (along with its subsidiary Scrabble Digital Ltd.) and Qube Cinema Technologies Pvt. Ltd., for indulging in anti-competitive conduct

New Delhi, Focus News: The Competition Commission of India (CCI) passed an order dated 16.04.2025 under the provisions of Section 27 of the Competition Act, 2002 (Act) imposing monetary and non-monetary sanctions on UFO Moviez India Pvt. (UFO Moviez), Scrabble Digital Ltd. and Qube Cinema Technologies Pvt. Ltd. (Qube), for contravention of provisions of Section 3(4) of the Act, resulting in tie-in arrangement, exclusive supply agreement and refusal to deal. In this matter, the Commission determined that UFO Moviez and Qube were significant players in the relevant market for the supply of Digital Cinema Initiatives-Compliant Digital Cinema Equipment (DCI-Compliant DCE) on lease/rent to Cinema Theatre Owners (CTOs) in India. The Commission found that UFO Moviez and Qube, through imposition of restrictions on supply of content in lease agreements entered into with CTOs, created barriers for players engaged in the provision of Post-Production Processing (PPP) services as well as blocked a significant portion of CTOs having DCI-Compliant DCEs from being served by any other player. The Commission held UFO Moviez (along with its subsidiary Scrabble Digital Ltd.) and Qube in contravention of provisions of Section 3(4) of the Act. The Commission, under the provisions of Section 27 of the Act, directed UFO Moviez and Qube to not re-enter lease agreements with the CTOs imposing restrictions on supply of content from other parties. The Commission further held that the existing lease agreements with CTOs shall stand modified such that they do not impose restrictions on supply of content from parties other than UFO Moviez (and its affiliates) and Qube. The Commission, after considering nature and gravity of the contravention along with assessment of mitigating and aggravating factors, also imposed monetary penalty on UFO Moviez (along with its subsidiary Scrabble Digital Ltd.) and Qube, amounting to Rs. 104.03 Lakh and Rs. 165.8 Lakh, respectively. A copy of public version of the order passed in Case No.11 of 2020 is available on the CCI website at www.cci.gov.in.

Second meeting of the Scientific Steering Committee for the National One Health Mission held on 15th April 2025

New Delhi, Focus News: The second meeting of the Scientific Steering Committee for the National One Health Mission under the chairmanship of Prof. Ajay K. Sood, Principal Scientific Adviser to the Government of India for the National One Health Mission, was held on April 15, 2025 in Vigyan Bhawan. The meeting was attended by Dr. Rajiv Bahl, Secretary DHR and DG ICMR; Dr. Parvinder Maini, Scientific Secretary, Office of PSA; Shri Rajesh Kotecha, Secretary, AYUSH; Dr. Rajan Khobragade, Additional Chief Secretary (Health), Kerala; Shri Dhananjay Dwivedi, Principal Secretary (Health), Gujarat; Dr. Ranjan Das, Director, National Centre for Disease Control (NCDC); senior representatives from Indian Council of Medical Research (ICMR); Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC); PSA's office, Department of Animal Husbandry and Dairying (DAHD); Department of Biotechnology (DBT); Department of Science and Technology (DST); Council for Scientific and Industrial Research (CSIR); Defence Research and Development Organisation (DRDO); National Security Council Secretariat (NSCS); Ministry of Ayush; NCDC; National Institute of One Health (NIOH); Department of Pharmaceuticals (DoP) and state representatives. The committee discussed several important initiatives that contribute towards the implementation of the One Health mission and how these efforts can be recalibrated to maximise impact. Gujarat and Kerala, the two states nominated to be the members of the Scientific Steering Committee showcased their programmatic initiatives and the existing governance mechanism. The Chair emphasised on the importance of state participation and mentioned the relevance of exploring different modalities for implementing the One Health approach. The states were encouraged to strategise and design pilot programs aligned to the initiatives of the mission.

Another important highlight of this meeting was the presentation of the outcomes of the Advisory and Review (A&R) committees constituted for the operationalisation of various work streams. The chairs of the four A&R committees - Bio-Safety Level (BSL) 3/4 Laboratory Network (Chaired by Lt. Gen.(Retd.) Madhuri Kanitkar), Technology enhanced integrated surveillance and outbreak investigation (Chaired by Dr NK Arora), Research and Development on medical countermeasures (Chaired by Dr Renu Swaroop)and Integration of databases and data sharing (Chaired by Dr Vijay Chandru) – apprised the steering committee of the preliminary roadmaps for achieving their respective mandates and emphasised on the need for adopting the One Health lens for all the interventions. The meeting also discussed the funding mechanism for the projects under the mission, which were focused on surveillance methodologies, developing R&D countermeasures like vaccines, diagnostics and monoclonals for diseases of One Health importance; Plan for the animal disease mock drill; update on augmenting the state engagements by creating the cross-learning platform. The chair emphasised that to take the activities of the mission to scale, continued collaboration, innovation, and adaptability is required from all the stakeholders. During the meeting, a special edition of 'Vigyan Dhara' dedicated to the National One Health Mission which presents the vision of this multi-ministerial collaborative effort was showcased. Further a video encapsulating the vision, diverse stakeholders and overarching goals of the Mission was released in the meeting.

Conclave on PM Vishwakarma–National SC-ST Hub organised in Baripada, Mayurbhanj, Odisha

New Delhi, Focus News: The Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises (MSME), Government of India, organised the 'PM Vishwakarma – National SC-ST Hub Conclave' on 16 April, 2025, at the Convention Hall, Maharaja Sriram Chandra Bhanja Deo University, Baripada, Mayurbhanj, Odisha. The event commenced with the inauguration of an exhibition and brought together stakeholders, beneficiaries, and government officials to highlight key initiatives such as the PM Vishwakarma Scheme and the National SC-ST Hub. The Conclave was co-chaired by Shri Jitan Ram Manjhi, Hon'ble Union Minister of MSME, and Shri Mohan Charan Majhi, Hon'ble Chief Minister of Odisha. The dignitaries inaugurated the Conclave with a ribbon-cutting and lamp-lighting ceremony. The gathering was also graced by Shri Gokulananda Mallick, Minister of State (Independent Charge), MSME, Fisheries & Animal Resources Development, Govt. of Odisha; Shri Hemant Sharma, Additional Chief Secretary, Industries & MSME Department, Govt. of Odisha; Shri Prakash Soren, Hon'ble MLA, Baripada, Govt. of Odisha; Ms. Mamata Mohanta, Hon'ble MP, Rajya Sabha, Mayurbhanj, Odisha; Ganesh Ram Singh Khuntia, Minister of State (IC)Forest, Environment & Climate Change, Labour, Labour & Employees State Insurance, Govt.of Odisha; Dr. Krushna Chandra Mahapatra, Hon'ble Minister, Housing and Urban Development, Public Enterprises, Govt. of Odisha; Shri Naba Charan Majhi, Hon'ble MP, Lok Sabha, Mayurbhanj, Odisha, and other senior officials of the Ministry. The conclave began with the welcome address by Dr. Ishita Ganguli Tripathy, ADC, DC(MSME), followed by a welcome address and a presentation on role of Ministry's Schemes and MSMEs growth in Odisha State by Dr. Rajneesh, AS & DC, DC(MSME). The event featured experience-sharing by beneficiaries of the PM Vishwakarma, PMEGP, and SC-ST Hub initiatives. To empower entrepreneurs, e-certificates were distributed to PM Vishwakarma beneficiaries, along with the distribution of credit cheques. Certificates were also awarded to National SC-ST Hub beneficiaries and PMEGP beneficiaries.

Ministry of Parliamentary Affairs Commences Swachhata Pakhwada 2025 with Swachhata Pledge

New Delhi, Focus News: The Ministry of Parliamentary Affairs today inaugurated the Swachhata Pakhwada 2025, a fortnight-long cleanliness drive aimed at promoting the spirit of Swachh Bharat and fostering a clean and sustainable work environment. On this occasion, Shri Umang Narula, Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs, administered the Swachhata Pledge to all officers and officials of the Ministry, urging them to renew their commitment to the cause of cleanliness and hygiene in both personal and professional spaces. He also motivated officials of the Ministry to make plantation at the nearby places of their residence or at any suitable location to make the environment green. Addressing the gathering, Dr. Satya Prakash, Additional Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs, encouraged officials to actively participate in the 15-day Swachhata Pakhwada. He emphasized the importance of collective responsibility and consistent efforts in achieving the goals of a clean, green, and sustainable environment. Dr. Prakash also provided a brief overview of the activities to be carried out during the Pakhwada. The Ministry remains committed to the ideals of Swachh Bharat Abhiyan and will continue to promote cleanliness and sustainability through regular initiatives and campaigns.

Ministry of Mines Issues Guidelines for Setting up of Centres of Excellence Under the National Critical Mineral Mission

New Delhi, Focus News: The Ministry of Mines has today issued the guidelines for setting up of Centres of Excellence (CoE) under the National Critical Mineral Mission (NCMM). This is in pursuance to a key pillar of the Mission, which is research and technology development in critical minerals. Critical raw materials form the crucial supply chain for emerging sectors of clean energy and mobility transition, in addition to advanced technology and strategic sectors like electronics, defence, space, etc. In order to develop, demonstrate and deploy technologies in an end-to-end systems approach, it is essential to conduct R&D so as to reach higher Technology Readiness Levels (TRL). CoEs will identify, develop and implement extraction process and beneficiation technologies for a host of critical minerals from multiple sources and conduct directed R&D to reach TRL 7 / 8 pilot plant and pre-commercial demonstration and create a competency center. Under this new initiative, reputed academic/R&D institutions, as per eligibility prescribed, will be evaluated and recognized as CoEs for R&D in critical minerals. CoEs will undertake innovative and transformational research to strengthen and advance the nation's science and technology capability in the area of critical minerals. CoEs will aim at undertaking cutting edge research and promoting inter-/multi-disciplinary approaches to problem solving in critical minerals domain. A CoE will operate as a consortium, on a Hub & Spoke model, to leverage R&D in critical minerals and pooling the core competence of each constituent under one umbrella.

नायडू ने केंद्रीय करों का हस्तांतरण बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का किया आग्रह

अमरावती, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने 16वें वित्त आयोग से राज्यों को केंद्रीय करों का 'वर्टिकल डिवोल्यूशन' मौजूदा 41 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की अपील की है। नायडू ने विशेष वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्य के पुनर्निर्माण में सहयोग देने का भी आग्रह किया है। संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण को 'वर्टिकल डिवोल्यूशन' कहा जाता है। नायडू की अपील इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार में प्रमुख सहयोगी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के लिए तेदेपा के 16 लोकसभा सदस्यों का समर्थन महत्वपूर्ण है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में नायडू द्वारा आयोग से किए गए अनुरोध का हवाला देते हुए कहा गया, ''वर्टिकल डिवोल्यूशन' हिस्सेदारी को 41 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाए। दक्षिणी राज्यों के 'हॉरिजोंटल डिवोल्यूशन' में भी गिरावट पर ध्यान दिया जाए, जो 24.3 प्रतिशत (10वें वित्त आयोग) से 15.8 प्रतिशत (15वें वित्त आयोग) हो गया है।'' राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण को 'हॉरिजोंटल डिवोल्यूशन' कहा जाता है। नायडू ने दावा किया कि 'हॉरिजोंटल डिवोल्यूशन' में आंध्र प्रदेश का हिस्सा राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद और जनसंख्या में उसके हिस्से से कम है, जिससे उसे ''राजकोषीय घाटा'' हो रहा है। अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग के सदस्य 15 से 18 अप्रैल तक आंध्र प्रदेश के चार दिवसीय दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश का पुनर्निर्माण न केवल इसके भविष्य के लिए बल्कि राष्ट्र की प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, ''यदि आप आज हमें खड़ा रहने में मदद करेंगे, तो हम कल भारत की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।'' नायडू ने आयोग से राज्य के समक्ष प्रमुख चुनौतियों को समझने और 'स्वर्ण आंध्र 2047' के लिए उसके दृष्टिकोण का समर्थन करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री यादव ने 'लाडली बहना' समेत अन्य लाभार्थियों के लिए 2500 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए

मंडला, फोकस न्यूज, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 'लाडली बहना' कार्यक्रम सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को बुधवार को डिजिटल माध्यम से 2,500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंडला जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में यादव ने 1.27 करोड़ लाडली बहना लाभार्थियों को 1,552.38 करोड़ रुपये, 56.68 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों को 340 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए पात्र 25 लाख महिलाओं को 57 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए। मध्यप्रदेश की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने राज्य में 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले लाडली बहना योजना की घोषणा की थी। यादव ने कहा कि भाजपा सरकार माताओं, बहनों और बेटियों के हितों की रक्षा के लिए हमेशा उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी कि बहनों को उनका हर हक मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास में आधी आबादी की अहम भूमिका सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि देश की राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए आने वाले वर्षों में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यादव ने मंडला जिले की रहने वाली शुचि उपाध्याय को भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चुने जाने पर बधाई भी दी। मुख्यमंत्री ने युवाओं को विभिन्न योजनाओं के लाभ और नियुक्ति पत्र वितरित किए और 232 करोड़ रुपये तक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया।

अनुसंधान, नवोन्मेष को बढ़ावा देने वाले विकास मॉडल को अपनाये उद्योगः ओम बिरला

नयी दिल्ली, फोकस न्यूज, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को उद्योग जगत से विकास का ऐसा मॉडल अपनाने का आग्रह किया जो समावेशी हो और अनुसंधान, नवोन्मेष तथा दूरदर्शी उद्यम की भावना पर आधारित हो। बिरला ने उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की 120वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की 'विकासोन्मुखी नीतियां' उद्योग को नई ऊर्जा प्रदान कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत में वर्तमान समय आर्थिक सशक्तीकरण और नवोन्मेष का है। बिरला ने 'विकसित भारत 2047' की रूपरेखा का जिक्र करते हुए कहा कि देश की व्यापार नीति आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण में गहराई से निहित है और वैश्विक मंच पर इसके बढ़ते कद को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक नीतियों का सरलीकरण, पारदर्शी और निवेशक–अनुकूल कर व्यवस्था और एक ही जगह पर सभी प्रकार की मंजूरी प्रणाली को अपनाने से देश में उद्यमशीलता की भावना को काफी बढ़ावा मिला है। बिरला ने कहा कि समकालीन भारत वैश्विक निवेशकों के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में उभरा है। एक ऐसा देश जहां व्यापार करने में आसानी केवल एक आकांक्षा नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्र तेजी से उपभोक्ता–संचालित अर्थव्यवस्था की अपनी पारंपरिक भूमिका से आगे बढ़कर नवोन्मेष और कौशल के जीवंत स्थल के रूप में उभर रहा है। उन्होंने भारतीय उद्यमों के परिवर्तनकारी योगदान विशेष रूप से स्टार्टअप के गतिशील परिवेश की सराहना की, जो अपने नए दृष्टिकोण और अभूतपूर्व विचारों के साथ सतत विकास का मार्ग प्रशस्त करने के साथ देश को वैश्विक महाशक्ति बनने का काम कर रहे हैं।

जमीनी स्तर पर सक्रिय होकर जलापूर्ति सुचारू बनाए रखें अधिकारी : मुख्यमंत्री शर्मा

जयपुर, (भाषा) मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गर्मियों में पेयजल प्रबंधन पर जोर देते हुए सम्बद्ध अधिकारियों से जमीनी स्तर पर सक्रिय होकर जलापूर्ति सुचारू बनाए रखने का निर्देश दिया है। शर्मा ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्ययोजना के तहत आमजन को निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर जिलों में पेयजल से संबंधित आकस्मिक कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। शर्मा ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में विभाग के अधिकारियों को जमीनी स्तर पर सक्रिय होकर जलापूर्ति की व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि गर्मी के मौसम में पेयजल व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए नवीन नलकूप एवं हैण्डपंप लगाए जाएं। उन्होंने पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यकता के अनुसार टैंकरों के जरिए पेयजल परिवहन की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही शर्मा ने पेयजल से संबंधित बजट घोषणा वर्ष 2024–25 के शेष कार्यों को शीघ्र पूरा करने को कहा।

संस्कृति और मूल्यों पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों का संकलन 18 अप्रैल को दिल्ली में जारी किया जाएगा

नयी दिल्ली, (भाषा) संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि संस्कृति पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाषणों का संकलन – 'संस्कृति का पांचवा अध्याय' – एक पुस्तक के रूप में 18 अप्रैल को जारी किया जाएगा। पुस्तक विमोचन समारोह नयी दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि पुस्तक का औपचारिक विमोचन जूना अखाड़ा के प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि महाराज करेंगे। 'संस्कृति का पांचवा अध्याय' प्रधानमंत्री मोदी के विभिन्न अवसरों पर दिए गए भाषणों का एक संग्रह है, जिनमें भारतीय संस्कृति, परंपराओं, आध्यात्मिक मूल्यों और सांस्कृतिक विरासत पर प्रकाश डाला गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश करेंगे। आईजीएनसीए के अध्यक्ष राम बहादुर राय मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। भाषणों का संकलन प्रभात ओझा द्वारा किया गया है। पुस्तक का प्रकाशन प्रभात प्रकाशन ने किया है।

उत्तराखंड में पुनर्निर्माण कार्यः मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों को और अधिक वित्तीय अधिकार दिये गए

देहरादून, (भाषा) उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संपत्तियों के पुनर्निर्माण में तेजी लाने के लिए मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों की वित्तीय शक्तियां बढ़ा दी गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार रात हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उनकी वित्तीय शक्तियां बढ़ाने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगौली ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी। फैसले के मुताबिक अब मंडलायुक्त एक से पांच करोड़ रुपये और जिलाधिकारी एक करोड़ रुपये तक के कार्यों को मंजूरी दे सकेंगे। इससे पहले मंडलायुक्त 20–50 लाख रुपये और जिलाधिकारी 20 लाख रुपये तक की पुनर्निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दे सकते थे। बगौली ने कहा कि राज्य में प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए ऐसा किया गया है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली 'मोटा अनाज नीति' के अलावा कीवी नीति और 'ड्रैगन फ्रूट' योजना को भी मंजूरी दी है। किसानों को मोटा अनाज उगाने के लिए 1,500 से 4,000 रुपये प्रति हेक्टेयर नकद प्रोत्साहन दिया जाएगा। कीवी नीति का उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में किसानों की आय दोगुनी करना है। बगौली ने बताया कि 'ड्रैगन फ्रूट' उगाने वाले किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने पंतनगर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 11 हेक्टेयर कृषि भूमि देने का भी फैसला किया।

न्यायमूर्ति अरुण पाली ने जम्मू–कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के 38वें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली

जम्मू, (भाषा) न्यायमूर्ति अरुण पाली ने बुधवार को जम्मू–कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के 38वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि न्यायमूर्ति पाली को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पद की शपथ दिलाई। यह शपथ ग्रहण समारोह जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथेर, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ अदालत के न्यायाधीशों तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी एस संधवालिया, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीश, अधिवक्ता, न्यायमूर्ति पाली के परिजन और मित्रगण भी समारोह में उपस्थित थे।

न्यायमूर्ति ताशी रबस्तान के नौ अप्रैल को सेवानिवृत्त होने के बाद, न्यायमूर्ति संजीव कुमार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे थे। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने 12 अप्रैल को न्यायमूर्ति पाली की नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी की थी। भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने चार अप्रैल को न्यायमूर्ति पाली को जम्मू–कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की थी। न्यायमूर्ति पाली ने वाणिज्य में स्नातक और चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय से वर्ष 1988 में कानून की डिग्री प्राप्त की।